



# दुनिया के विधान

लेखक

डा० पट्टाभि सीतारामैया

अनुवादक

नवीन नारायण अग्रवाल

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी लि०

आगरा

प्रकाशक  
प्रित्तिवास अग्रवास एवम् कम्पनी लि०  
होस्पिटल रोड, आगरा ।

प्रथमवार अगस्त १९४८  
मूल्य छात्रे तीन रुपया

मुद्रक  
मागीव-प्रिन्टिंग-वर्कस,  
लखनऊ ।

## प्रस्तावना

इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण को निकालने के लिये न छे कोई व्याख्या देने की आवश्यकता है और न सम-प्रार्थना की। प्रथम संस्करण का निरन्तरिचालकों के हाथों में अच्छा स्वागत हुआ। प्रस्तुत संस्करण इन पाठनीयों के लिए, जिसकी दिलचस्पी इस समय देश में होमे वाले परिवर्तनों के कारण विधान निर्माण काय में बहुत बढ़ गई है।

सभी तथ्यों और आंकड़ों को प्रोफेसर इन्द्रहस शर्मा, बी० ए० बी० काठेय, लाहौर के लौक्य से संशोधित कर दिया गया है। मैं इस कठिन काम को सम्पादन करने के लिये उन्हें कृतज्ञता पूर्णक धन्यवाद देता हूँ। फिर भी, इन छठों द्वारा मैं वाचन-निर्मात्री परियद् के सबकों की जारी आवश्यकताओं को पूरा करने का दावा नहीं करता। किंतु मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में एक ही नज़र में, विधान निर्माण संबंधी विभिन्न देशों की जारी बातों का पता चल जावेगा। साथ में वह भी कहूँ कि इस (द्वितीय) संस्करण का प्रकाशन केवल इंडियन बुक कम्पनी, लाहौर की अत्यधिक दक्षि दिक्कताने के कारण ही हुआ है।

जै देवली  
१-१०-१९४९

}

बी० पट्टमि सीतारामैय्या



## विषय सूची

### १ क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन विधान

१—आम्बरसैरह	...	...	...	१
२—बेनेडा	...	...	...	२
३—मास्त्रेसिवा	...	...	...	३
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	...	४
५—न्यूजीलैण्ड	...	...	...	५
६—फ्रांस	...	...	...	६
७—स्विट्जरलैण्ड ✓	...	...	...	७
८—जर्मनी	...	...	...	८
९—स्वाबो, कोटो, तथा वर्षों का समय	...	...	...	९
१०—रुस	...	...	...	१०
११—अमेरिका का समुद्र तट	...	...	...	११
१२—पोलिश प्रजातंत्र	...	...	...	१२
१३—जेकोस्लोवाकिया	...	...	...	१३
१४—आस्ट्रिया	...	...	...	१४
१५—स्वीडन	...	...	...	१५
१६—नार्वे	...	...	...	१६
१७—डेनमार्क	...	...	...	१७
१८—इसलैण्ड	...	...	...	१८
१९—स्पेन	...	...	...	१९
२०—बेल्जियम	...	...	...	२०
२१—जार्जिया	...	...	...	२१
२२—डेनमार्क	...	...	...	२२
२३—ग्रेनोबल	...	...	...	२३
२४—इटली	...	...	...	२४

## २ कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

१—आयरलैंड	---	---	२७
२—बेनेडा	---	---	२८
३—आस्ट्रेलिया	---	--	२८
४—फ्रांस	--	--	२८
५—इटली	---	--	२९
६—जर्मनी	---	--	२९
७—स्विटजरलैंड	---	--	२९
८—अमेरिका का संयुक्त राज्य	---	---	२९
९—सोवियत संघ	--	---	२९
१०—आस्ट्रिया	---	--	२९
११—बेल्जियम	---	--	२९
१२—स्वीडन	---	---	२९
१३—मार्से	---	---	२९
१४—डेन्मार्क	---	---	२९
१५—स्पेन	---	--	२९
१६—बेल्जियम	---	---	२९
१७—इंग्लैंड	---	--	२९
१८—डेन्मार्क	---	--	२९
१९—जापान ✓	--	---	२९
२०—इटली	---	--	२९

## ३ निधला यमन

१—आयरलैंड	--	--	२९
२—बेनेडा	---	---	२९
३—आस्ट्रेलिया	---	--	२९
४—इटली	---	---	२९
५—जर्मनी	---	---	२९
६—स्विटजरलैंड	--	---	२९





✓ ८—स्विट्ज़रलैण्ड	..	८१
✓ ९—सोवियत कृत	..	८१
१०—स्लावो क्रोयें तथा सर्बों का राज्य		८३
✓ ११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र		८७
१२—डेकोरलोवाकिया	..	८६
१३—पोलिश प्रजातन्त्र	..	८०
१४—रबीजन	..	८१
१५—नाबें	...	८१
१६—आस्ट्रिया	...	८२
✓ १७—इ. गलैड	..	८३
१८—डेन्मार्क	...	८५
१९—बेल्जियम	..	८६
२०—इटली	..	८८
२१—जापान	..	८८
२२—मैनिलो	...	१०

### ५—पान्त और न्यायालय

१—आयरलैण्ड	...	१०३
२—कैनेडा	...	१०४
३—आस्ट्रेलिया	..	१०५
४—न्यूजीलैण्ड	...	१०७
५—ब्राज़िली आफ्रीका	..	१०८
✓ ६—फ्रान्स	..	१०६
७—स्विट्ज़रलैण्ड	...	११
✓ ८—जर्मनी	...	११२
✓ ९—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	..	११२
✓ १०—	...	११५
११—डेकोरलोवाकिया	...	११६
१२—स्लावो, क्रोयें तथा सर्बों का राज्य	...	११७
१३—पोलिश प्रजातन्त्र	...	११७

१४—स्वीडन	...	...	११८
१५—आस्ट्रिया	...	...	११८
१६—नार्वे	...	...	१२१
१७—इंग्लैण्ड	...	...	१२१
१८—बेल्जियम	...	...	१२१
१९—जापान	...	...	१२४
२०—एथ्योपिया	...	...	१२४
२१—डेनमार्क	...	...	१२६
२२—इटली	...	...	१२६
२३—मैक्सिको	...	...	१२७

## ६—आधार भूत अधिकार व स्थानीय सरकार

१—आयरलैण्ड	...	...	१२८
२—आस्ट्रेलिया	...	...	१२८
३—कनैडा	...	...	१२८
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	...	१२८
५—स्पेन	...	...	१२९
६—फ्रांस	...	...	१२९
७—स्विटजरलैण्ड	...	...	१२९
८—जर्मनी	...	...	१३४
९—लिविंग स्टोन	...	...	१३५
१०—नेकोलोपक्रिया	...	...	१३७
११—अमेरिका का संयुक्त राज्य	...	...	१३७
१२—पोलिश प्रजातन्त्र	...	...	१३९
१३—स्वीडन	...	...	१४०
१४—नार्वे	...	...	१४०
१५—आस्ट्रिया	...	...	१४२
१६—स्लावो कोटो तथा सर्वो का राज्य	...	...	१४२
१७—एथ्योपिया	...	...	१४३
१८—इंग्लैण्ड	...	...	१४३

१८—डेन्मार्क	...	१४३
२०—स्पेन		१४४
२१—डेनमार्क	...	१४५
२२—इटली	...	१४६
२३—जापान	...	१४७
२४—मैक्सिको	...	१४८

### ७ राज्य और वयोग तथा शासन विधान में परिवर्तन

१—आबर्लेण्ड	...	१५०
२—कैनेडा	...	१५१
३—आस्ट्रेलिया	...	१५१
४—दक्षिणी अफ्रीका	...	१५१
५—स्प्रीसैबल	...	१५२
६—फ्रांस	...	१५२
७—स्विट्जरलैण्ड	...	१५३
८—बर्मीनी	...	१५३
९—सोवियतकम	...	१५४
१०—चेकोस्लोवाकिया		१५५
११—पोलिश प्रजातन्त्र	...	१५५
१२—अमेरिका का संयुक्तराज्य	...	१५६
१३—स्वानो, लॉथ, कोटो का राज्य		१५६
१४—स्वीडन	...	१५७
१५—नार्वे	...	१५७
१६—आस्ट्रिया		१५८
१७—हंगरी	...	१५८
१८—डेन्मार्क	...	१५८
१९—डेनमार्क	...	१५९
२०—मैक्सिको	...	१६०



८—राज्य सत्ता के स्थानीय भाग	...	१२६
९—स्वायत्तता और अभिव्यक्ति	..	१२७
१०—नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व	...	१२८
११—चुनाव परिपाटी	..	१०१
१२—विश्व धर्म, राजधानी	...	२०४

---

१ १ १

## क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन विधान

१ १ १

### आयरलैण्ड

क्षेत्रफल २७,१३७ वर्ग मील।

शासन विधान ५ दिसम्बर १८३७ की उन्नि के अंतर्गत बनाया गया, १८३७ ई में उसका संशोधन हुआ, नवीन शासन विधान को जनता ने जनमत-संग्रह (Plebiscite) के परचास् स्वीकार किया।

एकात्मक (स्वतंत्र राज्य)

उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त का कठोरता से पालन।

जनसंख्या २८,६५,००

प्रेसीडेन्ट का चुनाव जनता सात वर्ष के लिये करती है।

पेसन १०, ०० पौण्ड प्रति वर्ष।

यह 'काउन्सिल आफ स्टेट' के परामर्श पर किसी बिल को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। यह उपरोक्त म्यामल्लव उस अवधि घोषित कर दे, तो वह बिल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है। यदि व्यवस्थापिका सभा के नियुक्त मन्त्र के एक तिहाई सदस्य और सीनेट का बहुमत प्रेसीडेन्ट से बिल को अस्वीकार कर देने की प्रार्थना करे, तो वह उस बिल को जनमत-निर्णय (Referendum) के लिये भेज सकता है या उस बिल के प्रश्न पर आम चुनाव करा सकता है। साधारण तथा वह मधियों के परामर्श पर कार्य करता है, किंतु कुछ विषयों में 'काउन्सिल आफ स्टेट' की राय ले सकता है।

८—राज्य सभा के स्थानीय अंग	---	--	१६५
९—स्वायत्तत्व और अभियोग	--		१६७
१०—नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व			१६६
११—चुनाव परिपाटी		---	२०१
१२--बिह्व ध्वजा, राजधानी		---	२०४

---

(रोय अधिकार<sup>१</sup> संघ की इकाइयों को मिले हुए हैं) संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के ढंग पर बना है, किन्तु थोड़ा अन्तर है।

गवर्नर-जनरल को सम्राट् आस्ट्रेलिया के मंत्रिमण्डल के परामर्श पर नियुक्त करता है।

बैठन १०,००० पाँच प्रति वर्ष।

सरकार का वैधानिक<sup>२</sup> प्रधान है। सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है।

विरोध अवस्था में पार्लियामेंट के निचले मण्डल को मग करने का उसे अधिकार है और कुछ अन्य अवस्थानों में धारा-सभा के दोनों मण्डलों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

कानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट् की स्वीकृति के लिये उन्हें रल सकता है। वह स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिए। १९११ ई. के वेस्टमिंस्टर स्टैच्यूट (Statute of 1931), के पाल हो जाने के पश्चात् से पार्लियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट गई है।

## ४

### दक्षिणी अफ्रीका

क्षेत्रफल ४,७२,५५० वर्ग मील।

जनसंख्या ६६,८०,०००।

२०-६-१६ ई. का साठव अफ्रीका एक्ट।

फ्रेट्टाटन—पार्लियामेंट के अधिवेशनों का स्थान।

१—रोय अधिकार (Residuary powers) उन अधिकारों को कहते हैं जिन्का विधान में वह उल्लेख नहीं होता कि वे किसके पास रहेंगे।

२—वैधानिक प्रधान (Constitutional Head) का तात्पर्य यह है कि वह केवल दिखावे भर का प्रधान होता है। वास्तव में उससे पाठ कोई गलत नहीं होती। वास्तविक अधिकार मंत्रिमण्डल को प्राप्त होते हैं।



## कैनेडा

क्षेत्रफल ९९,६४,८६९ वर्ग मील ।

जनसंख्या १,१०,१२,००० ।

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, १८६७, और उसमें दिये गये म्यात्र संघोबनों के अंतर्गत शासन होता है । पर इन्हीं पर वर्तमान कैनेडा का शासन-विधान सम्पूर्णतः आधारित नहीं है ।

कैनेडा की संघ सरकार में गवर्नर-जनरल सम्राट् का प्रतिनिधित्व करता है । वह राजा द्वारा कैनेडा के मंत्रिमण्डल के परामर्श तथा स्वीकृति पर नियुक्त किया जाता है ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । संघ के किसी विध को सम्राट् की स्वीकृति के बिना रद्द सकता है । वह स्वीकृति जब कैनेडा के मंत्रिमण्डल के परामर्श पर ही जाती है ।

१९२६ ई० के बाद से यदि प्रधान मंत्री पार्लियामेंट मन्य करने की माँग करे तो वह इन्कार नहीं कर सकता ।

उसे उन साधारण एजेण्डों तथा सम्बन्धों को नियुक्त करने तथा विस्तार का अधिकार है जिन्हें सम्राट् या राजा सीधा नियुक्त नहीं करता या नहीं मिलता । कैनेडा तथा अन्य देशों के बीच ऐसी छोटी-मोटी सम्बन्धों कर सकता है किन पर सम्राट् सीधे हस्तक्षर नहीं करता ।

## आस्ट्रेलिया

क्षेत्रफल २६ ७४,४८१ वर्ग मील ।

जनसंख्या ६६,६७०० ।

शासन विधान १९०० ई में बना ।

(‘शेष अधिकार’ संघ की इकाइयों को मिले हुए हैं) संयुक्त राज्य, अमेरिका के ढंग पर बना है किन्तु थोड़ा अन्तर है।

गवर्नर-जनरल को सम्राट् आस्ट्रेलिया के मंत्रिमंडल के परामर्श पर नियुक्त करता है।

वेतन १०,००० पाँइ प्रति वर्ष।

सरकार का वैधानिक प्रधान है। सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है।

विशेष अवस्था में पार्लियामेंट के निचले भवन को मग करने का उसे अधिकार है और कुछ अन्य अवस्थाओं में चारा-सभा के दोनों मंचनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

कानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट् की स्वीकृति के लिये उन्हें रल सकता है। वह स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिए। १९११ ई० के वेस्टमिंस्टर स्टैचूट (Statute of 1931), के पास हो जाने के पश्चात् से पार्लियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट गई है।

४ :

## दक्षिणी अफ्रीका

क्षेत्रफल ४,७९,५५० वर्ग मील।

जनसंख्या ८३,८०,०००।

२०-९-१९९ का साठवें अधीका एक्ट।

फ्रेट्टाटन—पार्लियामेंट के अधिवेशनों का स्थान।

१—शेष अधिकार (Residuary powers) उन अधिकारों को कहते हैं जिन्हें विधान में यह उल्लेख नहीं होता कि वह किसके पास रहेंगे।

२—वैधानिक प्रधान (Constitutional Head) का तात्पर्य यह है कि वह कबल दिनाये मर का प्रधान होता है। वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। वास्तविक अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त होते हैं।

प्रीटोरिया—सरकार का स्थान ।

राजा इदिस आफीका की सरकार के परामर्श पर गवर्नर-जनरल को नियुक्त करता है ।

वेतन २०,००० पौंड प्रति वर्ष ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । व्यवस्थापिका सभी क मन्त्रों के बीच गति अविरोध हो जाने पर दोनों की सम्मिश्रित बैठक बुला सकता है ।

पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये किसी भी कानून में संशोधन के लिये मुझाब दे सकता है ।

किसी भी कानून को सम्राट की स्वीकृति के लिये रख सकता है जो एक वर्ष के भीतर ही जानी चाहिये ।

: ५ :

## न्यूजीलैण्ड

क्षेत्रफल १, १,२१४ वर्गमील ।

जनसंख्या : ११,०४,००० ।

१८३९ का एकद ।

१६०० में 'डोमीनियन' पर मिला ।

गवर्नर-जनरल को राजा न्यूजीलैण्ड सरकार के परामर्श पर नियुक्त करता है ।

वेतन ५००० पौण्ड प्रति वर्ष और एल ० पौण्ड का भत्ता ।

गवर्नर-जनरल के वेतन में, और मूल निवासियों के संबंध में शासन विधान द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों में परिवर्तन करने वाले किल सम्राट की स्वीकृति के लिये रख किये जाते हैं ।

सरकार का वैधानिक प्रधान है । कैनेडा के समान ही उसके अधिकार हैं ।

## फ्रान्स

क्षेत्रफल २,१२,९९६ वर्ग मील ।

जनसंख्या ४,२०,१४, ० ।

१७९१ और १८७० ई के बीच में ११ शासन विधान बने और बिगड़े ।

१८७५ ई का शासन विधान ।<sup>१</sup>

प्रेसीडेंट

वैतन ३६, ०, ०० फ्रांक प्रति वर्ष । इसमें सचे मी शामिल हैं ।

नेशनल असेम्बली — पूर्ण बहुमत<sup>२</sup> द्वारा चुनती है—७ वर्ष की अवधि ।

रेरात्रोह के अपराध में कक्ष निधला भवन सार्वजनिक अभियोग लगा सकता है और केवल सीनेट ही उसकी सुनवाई करके दण्ड दे सकता है ।

प्रेसीडेंट को १०० वोटों की सलाही दी जाती है—क्योंकि अमेरिकन प्रेसीडेंट को केवल २१ तापा की ।

अधिकार

कानून को पेश करने का अधिकार । व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास हुए बिलों पर थोड़ी अवधि के लिए वीटो<sup>३</sup> का अधिकार प्राप्त है ।

कानून लागू करता है । सभा प्रदान करने का अधिकार है, किन्तु आम रिहाई कानून द्वारा ही सम्भव है ।

१—सन् १८४९ में नया विधान बन चुका है ।

४—पूर्ण बहुमत से तात्पर्य यह है कि आधे से अधिक वोट पक्ष में हों ।

५—वीटो ( Veto ) उस विरोधाधिकार को कहते हैं जिसका उपयोग कर राज्य का प्रधान व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किये गये किसी भी कानून को रोक सकता है । पूर्ण वीटो ( Absolute veto ) का तात्पर्य होता है कि वह कानून अस्वीकृत हो गया और लागू नहीं हो सकता । थोड़ी अवधि के लिए वीटो ( Suspensary veto ) का तात्पर्य यह है कि कानून लागू होना में देर की जा सकती है, पर समय शर्तें पूरी होना पर उस लागू करना होता है ।

राष्ट्र की सैन्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राष्ट्र के कार्यों में समापत्ति करता है।

विदेशों के लिए सम्बन्ध निरूपित करता है और विदेशी राष्ट्रों से मित्रता है।

मसबिहों पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडेंट कह सकता है।

वह राज्य की वास्तवीय चलाता है।

मंत्रिमंडल के परामर्श पर व्यवस्थापिका सभा के निचले सदन को भंग कर सकता है।

स्वयं रिक्त होने पर मेहनत ससेम्बली नया चुनाव करती है। नवे चुनाव होने तक मंत्रिमंडल इन अधिकारों का उपयोग करता है।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका सभा को संघटित भेज सकता है। वे ट्रिबून (मंत्री) द्वारा पड़े जाते हैं जो दोनों सदन में आना सकता है।

कानूनों के लिये प्रेसीडेंट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु वह पुनर्विचार के लिए कह कर (शायद ही कभी ऐसा किया जाता हो) देरी लगा सकता है।

प्रेसीडेंट एक बार में व्यवस्थापिका सभा की बैठक एक मास के लिये स्थगित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

अमेरिकन प्रेसीडेंट न तो कंग्रेस (अमेरिकन व्यवस्थापिका सभा) को स्थगित कर सकता है और न भंग ही।

मंत्रिमंडल का प्रधान नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में समापत्ति का वह प्रवृत्त करता है।

१—विधान में सीनेट के परामर्श का उल्लेख है—मंत्रिमंडल के परामर्श का नहीं।

७—इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंट के हस्तक्षेप से बचने का उपाय यहाँ के मंत्रिमंडल से कोस ही निकाला। मंत्रिमंडल की बैठकें यहाँ दो प्रकार की होने लगीं। एक तो नियमित विनका समापत्ति प्रेसीडेंट स्वयं करता था और दूसरी अनियमित विनका समापत्ति प्रधान-मंत्री करता था।

अपने वैधानिक कार्यों के क्षेत्र में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

वे अधिकार प्रेसीडेंट स्वयं काम में नहीं ला सकता। शासन-विधान में स्पष्ट निर्देश है कि प्रेसीडेंट के प्रत्येक कार्य पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक हैं। ( कान्स्टीट्यूशनल ऑ, २५ फरवरी, १८७५, चारा ३ )।

नोट—फ्रांस के पतन के बाद आत्म-समर्पण की सन्धि पर २३ मूल, १८४० को हस्ताक्षर हो जाने पर तृतीय प्रजासत्तक का अन्त हो गया। नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेंट ( मार्शल पैरा ) को सौंप दिये। १२ मूल, १८४८ को तीन कान्स्टीट्यूशनल ऐक्ट पास हुए और पैरा ने उन पर हस्ताक्षर किये। १८४८ में फ्रांस के फिर स्वतंत्र होने पर अक्टूबर १८४९ और फिर मूल १८४९ में मेसनर ऐसेम्बली के चुनाव हुए। इस समय फ्रांस का नया विधान बन रहा है।

: ७ :

## स्विट्ज़रलैण्ड

क्षेत्रफल १५,२४४ वर्गमील।

जनसंख्या ४९,१८,००।

२२ कैन्टनों के बीच मित्रता की सन्धि के फलस्वरूप।

शेप अधिकार कैन्टनों के लिए सुरक्षित।

इन्हीं अनिवार्य बैठकों में सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखा निर्णय होता था। निवर्तित बैठकें केवल उन्हीं निर्णयों का निवर्तित रूप होती थीं। वही प्रथा (Convention) १८३० ई. में मंत्रिपरिषद् प्रवेश करने के पश्चात् में लघुक्त प्रांत के कार्यवाही मंत्रिमंडल तथा अन्य मंत्रिमंडलों में भी अपना सी मिलने गवर्नर के लघुक्त मंत्रिपरिषद् में निरूपित करने का मकदं।

८—यह अक्टूबर २४९ में बन चुका।

९—यह सन्धि १८४८ ई० में हुई। १८७४ ई. में इसमें संशोधन हुआ। उसके पश्चात् भी उसमें अनेक छोट-मोटे परिवर्तन हुए हैं।

राज्य की सैन्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राज्य के कार्यों में सम्मत्पक्षित करता है।

विदेशों के लिए राजदूत नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों से मिलता है।

मसविदों पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडेन्ट कह सकता है।

वह सर्वोच्च की शक्तों पर चलाता है।

मंत्रिमण्डल के परामर्श पर व्यवस्थापिका सभा के निचले सदन को भंग कर सकता है।

स्थान रिक्त होने पर गैरान्तर्गत असेम्बली नया चुनाव करती है। नये चुनाव होने तक मंत्रिमण्डल इन अधिकारों का उपयोग करता है।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका सभा को संदेश भेज सकता है। वे ट्रिब्यून (मंत्री) द्वारा पढ़े जाते हैं जो दोनों सभों में प्रसारित होता है।

कानूनों के लिये प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु वह पुनर्विचार के लिए कह कर (शामद ही कभी ऐसा किया जाता हो) देरी लाया सकता है।

प्रेसीडेंट एक बार में व्यवस्थापिका सभा की बैठक एक मास के लिये स्थगित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

अमेरिकन प्रेसीडेन्ट न तो कंग्रेस (अमेरिकन व्यवस्थापिका सभा) को स्थगित कर सकता है और न भंग ही।

मंत्रिमण्डल का प्रधान नियुक्त करता है। मंत्रिमण्डल की बैठकों में समापति का पद ग्रहण करता है।

६—विधान में सीनेट के परामर्श का उल्लेख है—मंत्रिमण्डल के परामर्श का नहीं।

७—इस संघ में वह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रेसीडेन्ट के हस्तक्षेप से बचने का उपाय वहाँ के मंत्रिमण्डल से शोभ ही निकाला। मंत्रिमण्डल की बैठकें वहाँ दो प्रकार की होने लगीं। एक तो नियमित विनका सम्मत्पक्षित प्रेसीडेन्ट स्वयं करता था और दूसरी अनियमित विनका सम्मत्पक्षित प्रधान-मंत्री करता था।

अपने वैधानिक कार्यों के क्षेत्र में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

ये अधिकार प्रेसीडेंट स्वयं काम में नहीं ला सकता। शासन-विधान में स्पष्ट निर्देश है कि प्रेसीडेंट के प्रत्येक कार्य पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक हैं। (कान्स्टीट्यूशनल ऑ, २५ फरवरी १८७५, पार्ग १)।

नोट:—फ्रांस के पठन के बाद आत्म-समर्पण की सन्धि पर २३ जून, १८४० को हस्ताक्षर हो जाने पर तृतीय प्रजातन्त्र का जन्म हो गया। नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेंट (मार्शल पैता) को सौंप दिये। १० जून, १८४० को तीन कान्स्टीट्यूशनल ऐक्ट पास हुए और पैता ने उन पर हस्ताक्षर किये। १८४४ में फ्रांस के फिर स्वतंत्र होने पर अक्टूबर १८४४ और फिर जून १८४६ में मेथन का ऐसेम्बली के चुनाव हुए। इस समय फ्रांस का नया विधान बन रहा है।

: ७ :

## स्विट्जरलैण्ड

क्षेत्रफल १५,२४४ वर्गमील।

जनसंख्या ४९,१८,००।

२९ कैन्टनों के बीच मित्रता की सन्धि के फलस्वरूप।

रोम अधिकार कैन्टनों के लिए सुरक्षित।

इन्हीं अनियमित बैठकों में ठारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा निर्णय होता था। नियमित बैठकें केवल उनकी निर्णय का नियमित रूप देती थीं। नही प्रथा (Convention) १८१३ ई. में मंत्रिमंडल प्रस्था करने के पश्चात् में संयुक्त प्रांत के कांंग्रेसी मंत्रिमंडल तथा अन्य मंत्रिमंडलों ने भी अपना ही विधान गवर्नर के सम्मुख लघु निर्णय रत्ने आ सके।

८—१८ अक्टूबर १८४६ में बन चुका।

९—१८ सन्धि १८४८ ई० में हुई। १८७४ ई० में इसमें संशोधन हुआ। उसके पश्चात् भी उसमें अनेक छोट-छोटे परिवर्तन हुए हैं।



समस्त सर्वोच्च अधिकार संघ के पास ।

फेडरल काउन्सिल

व्यवस्थापिका तथा के दोनो मन्त्र प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात्  
द्वारम्भ मिलकर चुनते हैं ।

तीन वर्ष की अवधि ।

राष्ट्रिय विधान में इस बात का कोई निर्देश नहीं कि संघ के मंत्रियों  
का चुनाव व्यवस्थापिका तथा के सदस्यों में से हो, किन्तु यही एक रीति  
विचार हो गया है ।

फेडरल काउन्सिल स्टैंडरडाइज्ड की पार्लियामेंट की  
कार्यकारिणी समिति (Executive committee) के समान  
कार्य करती है ।

विदेशी मामलों, कानूनों को लागू करने, पैना पर अधिकार, बन्द  
को तैयार करने तथा उपस्थित करने, कानून पेश करने हत्यादि के  
अधिकार इसे हैं ।

—

## जर्मनी

क्षेत्रफल २,२५,५२८ वर्गमील ।

जनसंख्या ७,८३ ७५,००० ।

राष्ट्रिय विधान ११ अगस्त १८१८ ई ; जनकरी १८३४ के 'रीज़  
निकार्म बिल' द्वारा संशोधित ।

प्रेसीडेंट का समस्त अन्तः-पूर्ण बहुमत द्वारा चुनाव करती है ।  
आयु ३५ वर्ष से ऊपर । यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो दूसरी बार में  
तात्कालिक बहुमत द्वारा । अवधि सात वर्ष । रीज़ बिल तो-निर्वाह के बहुमत  
से प्रस्ताव करे तो अन्तः बोध देकर उसे हटाने का निर्णय कर सकती है ।  
यदि अन्तः हटाने के विरुद्ध में राज दे तो राज देने के दिन से सात वर्ष  
की फिर अवधि गिनी जाती है । चुनाव चुनाव में लड़ा हो सकता है ।

प्रेसीडेंट रीज़स्वाय का सदस्य नहीं होता ।

यदि निवृत्ता मरण उसे वापिस मेमने ( Recall ) का प्रस्ताव करे तो उसे वह से मंजूर कर दिया जाता है और यदि अन्तिम प्रस्ताव के समर्थन में राय दे दो वह पद से अलग हो जाता है ।

### अधिकार

आधारभूत अधिकारों को भी, सैन्य सहायता से शान्ति स्थापित करने में मंजूर कर सकता है जैसे व्यक्तिगत अधिकार, मानव्य संबंधी स्वतंत्रता, निवास, उमा, संप्रदाय बनाने और सम्पत्ति संबंधी स्वतंत्रता—किंतु रीजिस्ट्रार को तुरत खूबना देनी होती है ।

सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण ।

रीज के पराधिकारियों को नियुक्त करने तथा निकालने का अधिकार, यदि वृत्तरे अन्य ङग का विधान में निर्देश न हो । वह अधिकार वृत्तरे को सौंप सकता है ।

अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रीज का प्रतिनिधित्व करता है ।

बाउंसर के परामर्श पर रीज को मंग कर सकता है । प्रेसीडेण्ट अधिवेशन को मग करने के सिवाय उसे किसी प्रकार व्यक्ति नहीं कर सकता । ( दुसना कीजिये, ईंग्लैण्ड, अमेरिका, मध्य से ) ।

प्रेसीडेण्ट को आका पर बाउंसर अथवा संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं । हस्ताक्षर करनेवाला उस कार्य के लिये उत्तरदायी समझा जाता है ।

बाउंसर तथा मंत्रिगण प्रेसीडेण्ट बाउंसर को नियुक्त करता है और उसकी राय पर मंत्रियों को ।

नोट १—इस समय पराधिकृत अर्मेनी विभिन्न राज्यों के नियंत्रण में है । उसका विभाजन कर विभिन्न राज्य उस पर अलग अलग शासन कर रहे हैं । धीरे-धीरे उसे फिर शासन में स्वतंत्रता दी जा रही है । अर्मी अर्मेनी का मविष्य अचकल में ही है । अर्मी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नवीन अर्मेनी की सीमा तथा शासन-विधान को हमरेला क्या होगी ।

२—दिल्लर के हाथ में शक्ति आने पर ( १९१३ १९४५ ) बरामद उत्पन्न-कर होते रह ।

बीटो केवल उस समय जबकि व्यवस्थापिका सभा के दोनों मजनों में मतभेद हो और केवल इस सीमा तक कि यदि वह चाहे तो, रीज़ल्टेंट के विरोध के रहते भी रीज़ल्टेंट द्वारा किसी मसविदे को दो तिहाई बहुमत से पास कर देने पर, उसे जनता की राय जानने के लिये भेज सकता है।

झागून लागू करना प्रेसीडेंट झागूनों को शासन विधान के निर्देश के अनुसार 'कॉर्नल आर्गुजॉ' में एक माह के भीतर प्रकाशित करा देता है। उसके १४ दिन पश्चात् वे लागू हो जाते हैं।

प्रेसीडेंट के अन्य अधिकारों के लिये पार्लर, मंत्रिमंडल, व्यवस्था सचिबी अधिकार, निम्नले तथा ऊपरी मजनों की परीक्षा के अंतर्गत देखिये।

: ६ :

## स्लावों, कोटों तथा सर्वों का राज्य१०

सीमित ( वैधानिक ) राजतंत्र।

६५,६२८ वर्गमील।

राजा।

१० :

रूस

रूसियन आर्गु सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक

क्षेत्रफल : ८,६८,०६१ वर्गमील।

जनसंख्या १६,२५,६५, ०।

१०—इस राज्य को 'यूगोस्लाविया' कहते हैं। गत द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके पश्चात् इसमें अनेक बदलाव हुए हैं। राजतंत्र नष्ट कर सर्वों पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया है और नया शासन विधान भी तैयार हो गया जो अत्यंत प्रगतिशील है।

रुस का वर्तमान शासन-विधान १९१६ ई० में लागू किया गया था। यह 'स्तालिन-शासन विधान'<sup>११</sup> के नाम से प्रसिद्ध है।

शासन विधान में सब के प्रेसीडेंट के नियुक्त किए जाने का कोई निर्देश नहीं है। अतएव रुस में कोई नाम मात्र का (Titular) प्रधान नहीं है। विदेशी सम्बन्ध अपने परिचय तथा अभिक्रम-यंत्रों को प्रेसीडीयम के उपाध्यक्ष के समुक्त पेश करते हैं और उत्तराधिकारियों का संभालन केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति (Central Executive Committee) का प्रभार करता है।

सर्वोच्च शासन सभा 'सोवमरकोना' (काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमिसारिज) को अब रुस का मंत्री कहलाते हैं।) को दी गई है जिसे सुप्रीम काउन्सिल बुनती है। किन्तु वास्तव में मंत्रिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी बुनती है और उसका नियंत्रण सुप्रीम काउन्सिल नियमित रूप से मान लेती है। इस 'सोवमरकोना' का एक उपाध्यक्ष होता है जिसे प्रधान मंत्री समझा जा सकता है।

प्रेसीडियम सुप्रीम काउन्सिल बहुत बड़ी होने से वास्तविक सभा का उपयोग नहीं कर सकती। इसके लिए १० सदस्यों<sup>१२</sup> की एक स्थायी समिति (Standing Committee) सुप्रीम काउन्सिल अपनी सम्मिलित बैठक में करती है। वह स्थायी समिति प्रेसीडीयम कहलाती है।

प्रेसीडियम अब काउन्सिल का अधिवेशन न हो रहा हो, उस समय उसका समस्त अधिकारों का उपयोग करता है। इसके कुछ विशेष

११—इसमें परबरी १, १९४४ में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसके अनुसार सब की इकाइयों को एक सीमा तक विदेशी शक्तों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने तथा समझौता करने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन्हें सेना रखने का भी अधिकार दिया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में मूल सिद्धान्त नष्ट करके ही नियंत्रण कर रहेगी।

१२—यह संख्या १९३९ में थी। उसने परबाल् अब सोवियत् रुस में नये देश शामिल हो गये, वह संख्या बढ़ा दी गई।

अधिकार भी हैं, ऐसे घुमा प्रदान, बीच कमीशन की नियुक्ति, सैन्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा अलगहदगी, पूर्ण अवकाश अपूर्ण सेन्स-संगठन की आशा, तन्त्रियों पर अन्तिम सहमति प्रकट करना, क्रमों की व्याख्या इत्यादि। यदि सुप्रीम कोर्टनितल का अधिवेशन न हो रहा हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है। इस वास्तविक व्यवस्थापिका समाप्ता जा सकता है।

: ११ :

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

क्षेत्रफल ३०,२६,७८२ वर्ग मील।

जनसंख्या १३,०२,१५,०००।

संघीय शासन विधान १७८७ ई. में बना, १७८९ ई. में लागू हुआ।

राष्ट्र अधिकार संघ की इकाइयों के पास हैं।

प्रेसीडेंट चार वर्ष की अवधि। उसके चुनाव के लिये राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय कन्वेंशन डेपूटीगेटों को नामाङ्क करते हैं और इकाइयों की व्यवस्थापिका समारोहों की आका से करता उनमें से अपने डेपूटीगेट प्रेसीडेंट का चुनाव करने के लिए चुन लेते हैं। व चुने हुए डेपूटीगेट प्रेसीडेंट का चुनाव करते हैं।

प्रत्येक इकाई को उसने ही डेपूटीगेट चुनने का अधिकार है किन्तु कि संघ की व्यवस्थापिका समा के दोनों मन्त्रों में मिलाकर उसके सदस्य हैं। किन्तु एक इकाई की एक ही बोट मिली जाती है और वह बोट उस पार्टी की ओर ही गई मानी जाती है जिस ओर उस इकाई के डेपूटीगेटों का बहुमत है।

प्रेसीडेंट पर के लिये उम्मेदवार की आयु कम से कम ३५ वर्ष और उसका राज्य के अन्तर्गत निवास कम से कम १४ वर्ष का होना चाहिये।

प्रेसीडेंट और बाइस प्रेसीडेंट या तो कॉमेस के द्वारा तार्वनिक समितियों लगाकर हटाये जा सकते हैं या वेस्टमोड अथवा रिक्थ के मुर्म में दखिस्त किये जाकर।

२,४,००० डॉलर और १०,००,००० फ्रैंक पर्यंत खर्चा तथा उत्तर  
तर्ज—४,८०,००० डॉलर।

किसी मिस को बिना हस्ताक्षर किये या बीटो किये जो ही छोड़  
सकता है। इस व्यवस्था में यदि कॉमेस का अधिवेशन चल रहा हो, तो  
इस दिन में वह बिना प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर के कानून बन जाता है।

किसी मसबिदे को मेज़ पर पड़े रहने देकर, यदि इस दिन के भीतर  
कॉमेस का अधिवेशन स्वगित हो जाय, उसका अंत कर सकता है। इसे  
'पाकिट बीटो' कहते हैं।

यह सीधे किसी मसबिदे को बीटो कर सकता और ऐसा करने के  
कारण बतते हुए उसको उस मकन को लौटा सकता है जहाँ प्रारम्भ में  
उसे उपस्थित किया गया था। किंतु यदि व्यवस्थामिका सभा के दोनों  
मवन अलग अलग हो-तिहाई के बहुमत से उसे बुधारा पास कर दें तो  
यह बीटो के रहते हुए भी नियमित रूप से कानून बन जाता है।

यह स्थल तथा नाविक सेना का कमाण्डर-इन-चीफ होता है।

यह सीनेट के हो-तिहाई के बहुमत की सहमति से उन्नि कर  
सकता है।

राजदूतों की नियुक्ति करता है—अन्य दूतों, काउन्सिलों, सर्वोच्च  
न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि की नियुक्ति भी सीनेट के परामर्श तथा  
सहमति से करता है।

सीनेट की जब बैठक न हो रही हो उस समय रिक्त स्थानों की पूर्ति  
थोड़ी अवधि के लिये 'कमीशन' द्वारा करता है। ये अस्थायी बैठक के  
समाप्त होने तक रह सकते हैं।

किसी या दोनों मवनों की बैठक बुला सकता है और दोनों में आपस  
में स्पर्शित होने के समय के प्रश्न पर मतभेद हो जाय तो स्वयं स्वगित  
कर सकता है।

यह मसबिदों का मुख्य वे सकता है, राजदूतों तथा अन्य दूतों से  
मिलता है।

प्रेसीडेंट के अधिकार किसी भी राज्य या प्रधान मंत्री से अधिक हैं।

सरकार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। १, ०, ० सरकारी कर्मचारी  
उसके आधीन हैं।

संघीय अदालतों को हटाने का अधिकार प्रेसीडेंट का अधिकार है बल्कि नियुक्त करने के।

यह शासन-विभागों के नियंत्रण के लिये कानूनों के अंतर्गत पूरक नियम बना सकता है।

समा प्रदान—कमिशन द्वारा लगाने गये अधियोगों (Impeachments) और राज्य के विरुद्ध अपराधों में नहीं।

कानून संबंधी अधिकार—१—बीजे (ऊपर देखिये),

२—कमिशन को सन्देश,

३—विशेष अधिवेशन—विशेष मसविदों पर विचारार्थ।

समा प्रदान तथा कानूनी अधिकार—शासकिक उद्देश्य अधिकार के दुरुपयोग को रोकना था। अब प्रेसीडेंट के ये अधिकार समझे जाते हैं—व्यक्तिगत उपयोग नाटकीय होता है।

प्रेसीडेंट एक पार्टी का नेता होता है, पर पार्टी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं।

उसे कोई भी हटा नहीं सकता।

उसे इसीस लोगों की सलाह दी जाती है जबकि फ्रांस के प्रेसीडेंट को एक ही लोगों की।

१२ :

## पोलिश प्रजातंत्र

क्षेत्रफल १,४९, ४२ वर्ग मील।

जनसंख्या २,९८,८९,९९९।

प्रजातंत्र १५ मार्च १९२१ ई और १९२४ ई का संसोधित विधान।\*

- 
- \* पोलैण्ड के शासन विधान में मुझ के पश्चात् काफी उलटपेच हुए हैं और नई शासन व्यवस्था पहले से अधिक प्रगतिशील है।

प्रेसीडेंट कायमि तात वर्ष ।

नेशनल असेम्बली द्वारा सम्मिलित बैठक में चुनाव । डाइट १/५ के बहुमत से उस पर अमियोग लगा सकती है ।

कोरम १/२

ट्रिबूनल ऑफ स्टेट<sup>११</sup> के द्वारा अमियोग का निश्चय होता है ।

डाइट को भंग कर सकता है, यदि सीनेट की सहमति हो या डाइट स्वयं १/५ के बहुमत से इसके पक्ष में अपनी सहमति दे ।

कोरम १/२

प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और उसके द्वारा अन्य मंत्रियों को ।

प्रेसीडेंट का जमा प्रदान करने का विशेषाधिकार मंत्रियों को दिये गये दख पर लागू नहीं होता ।

ग्राम रिहाई करने का अधिकार नहीं है ।

: १३ :

## जैकोस्लोवाकिया

क्षेत्रफल ४४,२५४ वर्ग मील ।

जनसंख्या १,४७,२८,२३३ ।

( बोहेमिया, मोरविया, स्लोवाकिया, सिस्लीस्त्रिया का भाग, कार्पेथिया रुथेनिया का भाग, कार्पेथियनस का दक्षिण भाग <sup>१२</sup> )

प्रजातंत्र—केवल कार्पेथियन रुथेनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र से संघीय है । उसकी अपनी डाइट तथा सरकार है । सरकार की नियुक्ति प्रेसीडेंट करता है किन्तु वह डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है ।

नवम्बर १४, १९१८ ।

११—ट्रिबूनल ऑफ स्टेट—सर्वोच्च न्यायालय का एक विभाग ।

== न्यायाधीश डाइट के द्वारा नियुक्त ।

४ न्यायाधीश सीनेट के द्वारा नियुक्त ।

१४—गत महापुरुष के परराष्ट्र दफ्ती सीमा में भी परिवर्तन हो गया है ।

वह सोवियत रुठ से जून, १९४५ ई० की सन्धि के अनुसार हुआ ।



प्रेसीडेंट नेशनल असेम्बली-सम्मिलित बैठक में—सात वर्ष के लिये चुनती है।

सोमता चेम्बर ऑफ रिपुब्लिक के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उम्र १५ वर्ष से अधिक हो। ३/५ बहुमत से चुना जाता है—एक बैठक में, फोरम—पूर्व बहुमत; नामों को बोलकर उपस्थिति देनी पड़ती है। यदि दो बार के बोटिंग में उपरोक्त बहुमत न मिले तो तीसरा बोटिंग निर्धारक होता है। उपरोक्त पक्ष के लिये दो बार चुना जा सकता है; उत्तरवात् एक अवधि के विराम के बाद चुना जा सकता है। प्रथम प्रेसीडेंट पर यह बात लागू नहीं की गई।

प्रेसीडेंट व्यक्त्यापिका समा को केवल एक माह के लिये वर्ष में केवल एक बार कर सकता है। उसे मग भी कर सकता है किन्तु अंतिम वर्ष के अर्पीश में नहीं।

प्रेसीडेंट किसी भी किस को एक माह के भीतर पुनर्विचार के लिये छोड़ा सकता है।

यदि दोनों मकन पूर्व बहुमत से उपस्थिति बोलकर उसे फिर पास कर दें तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा यदि चेम्बर ऑफ रिपुब्लिक उसे उपस्थिति बोलकर ३/५ के बहुमत से पास कर दे तब भी वह कानून हो जाता है। (यदि पहिले से अधिक फोरम और बहुमत की आवश्यकता होती है, तो केवल दुबारा निर्वास प्रकट करने के लिये।)

अधिकार विदेशी मामलों में प्रतिनिधित्व करता है, और वन्धि—वाणिज्य—अर्थ संबंधी प्रश्नों—सैनिक मामलों—सीमा संबंधी विषयों पर उसके अधिकार हैं।

राजपूतों को नियुक्त करता है और उनसे मिलता है।

शुद्ध को पोषणा करता है और नेशनल असेम्बली की सहमति से शान्ति-वन्धि करता है।

नेशनल असेम्बली को बुलाता है, रणगित तथा मंग करता है।

कानूनों को वापिस मेजने का अधिकार उसे है।

नोट—द्वितीय संशोधनानुसार महायुद्ध के पश्चात् तथा शासन विधान बन रहा है।

मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पद से उन्हें अलहदा करता है तथा उनकी संख्या निर्धारित करता है।

उच्च शिक्षा के प्रोफेसरो को नियुक्त करता है और उन्हें अलहदा करता है।

छठी बेची से ऊपर के अफसर, राज्य अफसर तथा म्यामापीश की नियुक्ति।

खरकर के तुम्हाव पर छायायता होता है तथा वेन्चने होता है।

समस्त सेना का कमान्डर-इन-चीफ होता है। क्षमा प्रदान करता है।

: १४

## आस्ट्रिया

क्षेत्रफल १०,७,६६ बगमील।

जनसंख्या ६१,११,४५५।

सर्व सरकार

रा्य अधिकार—शासन संबंधी तथा कानूनी प्रांती के वस्त है।

प्रेसीडेंट

नेशनल काउन्सिल तथा फेडरल काउन्सिल की सम्मिलित बैठक चुनाव करती है।

चार वर्ष की अवधि; लगातार केवल एक बार ही और चुना जा सकता है—अमेदवार की उम्र कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिये। यदि नेशनल काउन्सिल का मतदाता भी हो। गत राजशाही परिवार या शासन करनेवाले परिवारों का व्यक्ति प्रेसीडेंट नहीं चुना जा सकता।

प्रेसीडेंट यदि कार्य करने योग्य न रह तो कसम्भ मार संघ के पातलर पर पकटा है।

उच्च विदेशी मामलो—राजदूत—संघीय अफसरों की नियुक्ति—रा्य अफसर—परो मन्त्री तथा अफसरों की उपाधि के संबंध में अधिकार प्राप्त है।

## युनिया के विधान

। समा प्रदान करने—नागरिक संतानों को कानूनन घोषित करने का अधिकार है। किन्तु सभ सरकार के कानून पर ही यह ऐसा कर सकता है।

नोट—पार्थी ई सम्पि की बारा ८० के अंतर्गत जर्मनी इसके लिये बाध्य था कि “आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता का पूर्ण रूप से आदर करे।” किन्तु बीमर विधान की ११वीं बारा में आस्ट्रिया को “जर्मन रीझ के साथ मिल जाने पर” रीझ स्टाट में प्रतिनिधित्व देने का निर्देश किया गया था।

सुप्रीम कौन्सिल ने इस बारा को व्यवैधानिक घोषित कर दिया और जर्मनी की एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें १० अगस्त १९१६ ई० से आगे बीच वर्ष तक के लिये इसी प्रकार की घोषणा करनी पड़ी। जर्मन-आस्ट्रिया के मिल जाने का प्रश्न बराबर यूरोपीय राजनीति में उठता रहा और १९१८ ई० में यह मिशन हो ही गया।

स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् नया शासन विधान बन रहा है।

: १४ :

## स्वीडन

क्षेत्रफल १, ७१, १५० वर्गमील।

जनसंख्या ६३, १०, ० ।

शासन विधान १८ ६ ई० में बना।

राजा।

पेट्रुक गरी। ईबैंगलिक धर्म में विश्वास रखनेवाला। राजा तथा उच्चराजिकारी राजकुमार के वासिदा होने की आयु—१८ वर्ष।

राजा कीज का कमायदर-बन-बीऊ होता है।

समा दख में कमी कर सकता है।

सम्पति वासिदा से सकता है।

किसी भी अक्षर को राजा निहाल सकता है, पर संबंधित मन्त्री विशेष प्रकट कर सकता है।

राजा के पास बीये का अधिकार है।

राजा व्यवस्थापिका समा हस्त कमिषीयन लगावे जाने पर भी हस्ता कर सकता है, किन्तु पुन नौकरी नहीं दे सकता।

१६

नार्वे

क्षेत्रफल १,२४,५५६ वर्गमील।

जनसंख्या २६,१७, ००।

स्वतंत्र, स्वाधीन, अभिमान्य, अद्वेष राज्य।

सीमित, पैतृक राजतंत्र

यदि उत्तराधिकारी न हो न राजा बूरे नाम को प्रस्तावित कर सकता है अन्तः (unborn) उत्तराधिकारी भी राजगद्दी के अधिकारी होते हैं।

बिना किसी पर राजा स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान नहीं करता, ये अस्वीकृत समझे जाते हैं।

१७

ऐस्थोनिया

क्षेत्रफल १८,१५१ वर्गमील।

जनसंख्या ११,१४, ।

प्रजातंत्र

तिथि १५-४-१९२० ई०।

२-५-१९२० ई०।

१५—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक भाग में (१९४० ई०) हो ऐस्थोनिया सोवियत रुस का एक भाग बन गया और अब भी है। वहाँ अब सोवियत शासन है।

१८ :

## इंग्लैण्ड

खेनपत्र ६५,२७६ वर्गमील ।

जनसंख्या ४,६२,१३,००० ।

राजा बैधानिक प्रधान ।

उस पर ब्रिटिश बजट का १/५ प्रतिशत ब्यव होता है ।

प्रिंसी काउन्सिल—संख्या लगभग ३५०—केवल राजगद्दी के आब  
 तर का आब विशेष उत्सवाधिक कार्यों क लिये मिलती है ।

लॉकास्टर की इन्हीं से होने वाली उसकी व्यक्तिगत आय है और  
 ऊपर बताये गये ब्यव के अतिरिक्त है ।

प्रिंस आल्बर्ट को इसी प्रकार कम्पारलैयन्ट से आय मिलती है ।

सरकार का वास्तविक प्रधान मधिमंडल है जो प्रधान मंत्री के अंतर्गत  
 कार्य करता है । राजा क कानूनी अधिकार विस्तृत हैं, किन्तु वे समस्त  
 अधिकार सरकार द्वारा सम्राट के नाम पर उपयोग किये जाते हैं । इस  
 प्रकार राजा केवल बैधानिक प्रधान है ।

: १९

## स्पेन

तिथि दिसम्बर ६, १८११ ।

शासन विधान राज्य-मनुष्य के अधिकार से बनना तथा स्वीकार  
 किया गया और बैधानिक कोर्टों द्वारा मान लिया गया—मन्त्रियों की  
 केमोन्ट्रेडिक प्रजासत्त । शेष अधिकार राज्य के पास । किन्तु वे डेलीयेट  
 किये जा सकते हैं । अधिकार विस्तृत किये गये हैं ।

संघीय राज्यों क लिये व्यवस्थापिका समान है और प्रांतों के हाथ में  
 शासन-कार्य ।

प्रेसीडेन्ट

६ वर्ष की अवधि ।

कम से कम ४ वर्ष की आयु हो ।

सैनिक, पादरी, हाथन करनेवाले परिवार नहीं हो सकते ।

अधिकार

युद्ध को घोषणा कर सकता है ।

२०

## बेल्जियम

क्षेत्रफल ११,७७५ वर्गमील ।

जनसंख्या ७,८१,८१, ०० ।

शासन विधान नवम्बर १० १८३१ ।

७-२-१८३१

संशोधित अक्टूबर १५, १८२१ ।

राजा

पेट्रुस, पुत्री को गद्दी नहीं मिलती । राजकुमार राजा की सम्मति के बिना यदि विवाह करता है तो गद्दी पर से अधिकार लो देता है ।

क्रिश्चियनवापिका समा के दोनों भवन पुनः उस गद्दी पर बैठा सकते हैं ।

वैधानिक अधिकार

राजा हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव ( निचले भवन ) को मंत्र कर, नये मुद्रा की घोषणा कर सकता है ।

राजा के स्वर्गवास पर, स्ववस्थापिका समा के दोनों भवन बिना मुलावे दसवें दिन मिलते हैं, उस समय तक अधिकार मंत्रिमंडल के पास रहते हैं ।

राजा को दोनों भवनों के सम्मुख शपथ लेनी होती है ।

२१ :

## जापान

क्षेत्रफल १,४८,७५६ वर्गमील ।

जनसंख्या ७,२२,२१, ० ।

राजा अधिवेशन बुलाता है और अधिक से अधिक दो माह के लिये उसे स्वतंत्र कर सकता है।

राजा बिलों को रीतसरगा के सम्मुख निम्नार्थ उपस्थित कर सकता है।

धर्मा प्रदान तथा आम रिहाई करने का अधिकार उसे प्राप्त है।

राजा कानून के अनुसार मुद्रा बना सकता है।

: २३

## मैक्सिको

क्षेत्रफल ७,६१,८४४ वर्ग मील।

जनसंख्या २,१८,५६, ०।

नया शासन विधान—प्रजासत्ताकीय—संघीय प्रेसीडेन्ट।

१९ जनवरी १८१७।

पात्रियों को मुगिया देने तथा विदेशियों द्वारा शोषण के विरुद्ध निवृत्त है।

सर्वोच्च तथा प्रेसीडेन्ट में निहित है, प्रेसीडेन्ट का सीधा चुनाव होता है।

बोम्बता मैक्सिको का नागरिक हो—उत्पत्ति से या उसके माता-पिता मैक्सिको निवासी हो—आयु १५ वर्ष से अधिक हो। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दंग अथवा सरकार को सैनिक शक्ति द्वारा पतन के पक्ष में भाग न लेना हो।

अथवा प्रथम दिसम्बर से चार वर्ष।

कभी पुनरा नहीं चुना जा सकता।

अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनेवाला—अगले अवसर पर प्रेसीडेन्ट नहीं चुना जा सकता। अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति कायम करती है। यदि उसकी बैठक ११ महीने हो, तो उसके तत्काल भत्ता देकर चुनाव करते हैं। यदि बैठक न हो पाई हो या स्थायी समिति (Permanent Committee) चुनती है और नियम चुनाव के लिये प्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाती है।

अस्यकालीन रिक्तता—यदि अवधि के प्रथम दो वर्षों के भीतर हो तो अस्यकालीन प्रेसीडेंट फिर कभी प्रेसीडेंट नहीं बन सकता।

प्रेसीडेंट बिना कांग्रेस की सहमति के त्याग-पत्र नहीं दे सकता और यह सहमति केवल गम्भीर कारणों के उपस्थित रहने पर ही दी जानी चाहिए।

### अधिकार

विचारार्थ मसविदा उपस्थित कर सकता है।

बीरो क उसे उठने ही सीमित अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि अमेरिकन प्रेसीडेंट को।

### अधिकार और कर्तव्य

कानूनों को लागू करता है।

सेक्रेटरियों को नियुक्त करता और अलग-हटा करता है। इसी प्रकार के अधिकार एजेंटों, जनरलों और गवर्नरों के संबंध में प्राप्त हैं।

सीनेट की स्वीकृति से समस्त मंत्रियों, राजदूतों तथा काउन्सिल जनरल को नियुक्त करता तथा अलग-हटा करता है।

यही अधिकार सेना के कर्नलों और फ़ौज के ऊँचे अफसरों के संबंध में प्राप्त हैं।

अन्य अफसरों की नियुक्ति।

सैन्य तथा स्थल सेना का प्रधान।

नेशनल गार्ड का समुचित प्रबन्ध। (देखिये धारा ७६, उप धारा ४)।

कॉंग्रेस के प्रस्ताव पर युद्ध की घोषणा।

योग्यता-पत्रों को खान करता है।

कूटनीति सम्बंधी पत्र-व्यवहार तथा सम्बन्ध करता है।

कॉंग्रेस के विशेष अधिकारों का मुकाबला है।

न्याय विभाग को काम करने में आवश्यक महाबत्ता प्रदान करता है।

ताम्रद्रिक व्यापार पर तथा अन्य सवनेवाली धुंगियों के भवन कोसता है।



समा प्रदान करता है। आविष्कार तथा खोज संबंधी सुविधाओं के लिये एकाधिकार देता है।

शासन-विधान द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करता है।

२४

## इटली

क्षेत्रफल १,१२,००० वर्ग मील।

जनसंख्या ४,४५,१७, ० ।

राजा नाम साव का प्रधान।

मुख्यस्थिती वास्तव में प्रधान था।

नोट—मुद्र में पराक्रम के परचास इटली में अनेक परिचर्तन हुए। इटली जनता के मत जानने के परचास प्रचारार्थ खोपित कर दिया गया। राजा देश से बहा गया। मया शासन विधान बनाने के लिए विधान निर्मात्री परिषद का चुनाव हो चुका है।

: २ :

## कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

१

### आयरलैण्ड

#### प्रबन्धक-विभाग

धारा ११—इसे एक्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं—कच्चा पौंच से सात तक—प्रेसीडेंट के द्वारा नियुक्ति, डेल की मामूलीदारी पर। अन्य मंत्री प्रधान मंत्री और राज्य मंत्री के परामर्श पर नियुक्त किये जाते हैं। ( कैनेडा के ढंग पर व्यवस्था )।

प्रेसीडेंट बाइस प्रेसीडेंट का निर्वाचन करता है। डेल आपरन के समुदाय पर अतिरिक्त मंत्री नियुक्त किये जा सकते हैं, किन्तु वह विभागों के प्रधान मात्र होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से डेल आपरन के प्रति उत्तरदायी होते हैं—वह मया १९२७ ई० से लगभग उठा ही दी गई है।

प्रेसीडेंट जनता द्वारा चुना जाता है।

अर्थ संबंधी विषय वह हैं जिन्हें डेल आपरन का समायोजि ऐसा घोषित करे। किन्तु व्यवस्थापिका तथा का कोई भी मन्त्र वह मोंग कर सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय नुविषासों की कमेटी (Committee of priveleges) करे।

सभी डेल आपरन के सदस्य होने चाहिये।

वह चीनर आपरन ( उच्च मन्त्र ) में उपस्थित हो सकते हैं तथा मापण दे सकते हैं।

: २ :

## कैनेडा

मन्त्री, यदि पहिले ही व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न हो तो तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। वह एक वैधानिक प्रथा (Convention) है।

दोय बाते इन्सैबर के समान।

विरोधी दल के नेता को बही बैठन दिया जाता है जो प्रधान मन्त्री को—१०० वोट्स वार्षिक।

३

## आस्ट्रेलिया

बैठन १२, ०० वोट्स को सात मंत्रियों को दिया जाता है।

लेबर पार्टी का मंत्रिमंडल बनाती है तो मंत्रियों के नामों का मुख्य पार्टी कोकस<sup>१८</sup> करती है।

कैबिनेट सम्पूर्ण शासन कार्य चलाती है और पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अवश्य होने चाहिए।

यदि पहिले से ही वह सदस्य न हो तो (यह नियम है) उन्हें तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए।

१८. कोकस (caucus) व्यवस्थापिका सभा के पार्टी सदस्यों की बैठकों को कहते हैं जो बनेको शासन-संबंधी विषयों पर पहिले से विचार करने के लिये होती हैं। पार्टी के सभी सदस्य उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें किये गये साधारणतया पार्टी के व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्यों को मानने होते हैं।

४

फ्रान्स

मंत्रियों का वेतन ६,००० फ्रैंक है। सरकारी मजदूरी इसके साथ अलग से मिलता है। यदि प्रधान मंत्री स्वयं म्याम विभाग नहीं सम्हालता तो म्याम मंत्री का पद उसके बाद जाता है।

मंत्री तथा उनके सेक्रेटरी साधारणतया कैबिनेट के सदस्य होते हैं।

मंत्री सम्मिश्रित रूप से उत्तरदायी हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। साधारण अपराधों के लिये साधारण न्यायालयों द्वारा दण्डित किये जा सकते हैं किन्तु राजद्रोह के विषयों में न्यायस्थानिका समा उन पर अभियोग लगाकर उन्हें दण्डित कर सकती है।

कैबिनेट के मंत्रियों के इस्तेफार प्रत्येक मामले में आवश्यक है। नये मंत्रियों की नियुक्ति-पत्र पर प्रधान मंत्री इस्तेफार करता है।

मंत्रियों की काउन्सिल की बैठक में प्रेसीडेन्ट सम्मिलित करता है किन्तु कैबिनेट बैठक में नहीं करता। कार्यवाही का विवरण प्रकाशित होने के लिये समाचार पत्रों को दे दिया जाता है किन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर उसमें कुछ नहीं कहा जाता।

प्रधान मंत्री को सदस्यों के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिये सहमति लेने में कभी कभी कई सप्ताह लग जाते हैं। कोई भी मंत्री त्याग-पत्र देने की बगल केवल अन्य मंत्रियों की स्थिति को भी इनसे से जाल सकता है।

मंत्रिमंडल का प्राण पुनर्संगठन होता रहता है, नये मंत्रिमंडल कम बनते हैं। प्राण बही प्रधान मंत्री फिर पद सम्हाल लेता है।

इंग्लैण्ड में कैबिनेट की स्थिति देश की विचार-धारा पर निर्भर है, यौत में पार्लियामेंट की हथ्का पर।

## दक्षिणी अफ्रीका

### कैपीनेट

गवर्नर-जनरल चुनता तथा मुलाका देता है। संख्या इस से अधिक न हो। कैबिनेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी की इच्छा पर उसकी प्रवृत्ति निर्भर है। दक्षिणी अफ्रीका में कैबिनेट को एक्जीक्यूटिव काउन्सिल करते हैं।

### ६

## जर्मनी

कैबिनेट रीज़रवाग के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रेसीडेंट के अधिकार १९३० ई० के परचास बहुत विस्तृत हो गये हैं। जर्मन शासन विधान ने प्रेसीडेंट को कानून बनाने में सहयोग देने का अधिकार दे दिया है। उसे यह अधिकार है कि रीज़रवाग की कार्यवाही का विवरण उसे दिया जाय। वह कार्यवाही के समय सम्भव पर प्रहरण कर सकता है; वह कैबिनेट के संगठन के बारे में बलों की मींगे मालुमा अवसीकृत कर सकता है।

पार्लियामेंट की शक्ति प्रेसीडेंट की बढ़ती हुई शक्ति से कम होती जा रही है। प्रेसीडेंट पार्लियामेंट को भंग कर सकता है।

१९१९-१९२४ के काल में ४८वीं धारा के अंतर्गत १३० 'एमेजेंसी डिक्री' (Emergency Decrees) जारी की गईं।

कानून बनाने के सम्बन्ध में पहल (Initiative) का अधिकार है।

(अ) रीज़र सरकार रीज़रवाग की सम्मति पर बिल उपस्थित कर सकती है।

(ब) बिना सहमति के भी ऐसा किया जा सकता है। किंतु

भास्विक अवस्था पर प्रकाश डालने के लिये एक बक्तव्य निकालना आवश्यक है।

(घ) रीज क्यूट के ज़ोर देने पर, अपनी सहमति के बिना भी। किन्तु एक बक्तव्य से अपना इतिवृत्त स्पष्ट कर देना चाहिए।

प्राप्तिकार तथा मन्त्रियों को उपस्थित होने तथा भाषण देने का अधिकार है। उन्हें उपस्थित होने के लिए आज्ञा दी जा सकती है।

यदि भी धारा के अंतर्गत समयमा समस्त कानूनी अधिकार प्रेसीडेंट को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

कमेरियो कन्ता के सामने कुली बैठकें करती हैं।

विदेशी मामलों की कमेटी गुप्त बैठकों में काम करती है। किन्तु उक्तका वो सिद्दाई बहुमत कुली बैठकों की माँग कर सकता है।

### ७

## स्विटज़रलैण्ड

### फ़ेडरल काउन्सिल

सात सदस्य, अस्थि-तीन वर्ष। व्यवस्थापिका सभा के दोनों मन्त्रों द्वारा चुनाव होता है।

(निर्वाचन इस प्रकार होता है कि किसी भी सेशन के एक से अधिक सदस्य न हों)

संघ का प्रेसीडेंट फ़ेडरल काउन्सिल का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है।

प्रेसीडेंट तथा वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव फ़ेडरल असेम्बली द्वारा १ वर्ष के लिये होता है। वह फ़ेडरल काउन्सिल (मंत्रिमंडल) के सदस्य होने चाहिए। कोई सदस्य उक्त पदों पर लगातार दो वर्ष कार्य नहीं कर सकता।

### कोरम ४

सब मंत्रियों का चुनाव हो जाता है तो वह व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं। रिक्त स्थानों के लिये नये चुनाव होते हैं।

प्रेसीडेंट को एक प्राथमिक मत और दूसरा कारिगम वोट देने का अधिकार होता है ।

पाउलर कैबरेल काउन्सिल का सदस्य नहीं होता ।

वह मुख्य सेक्रेटरी होता है—जर्मन पाउलर यह नहीं होता ।

प्रत्येक कैबरेल काउन्सिल का सदस्य एक शासन-विभाग का प्रधान होता है—उपमुख्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, यह विभाग, सैन्य विभाग, डाक विभाग, राजनैतिक विभाग, प्रकाशन ।

कानून बनाने के लिये मतभिन्ने तैयार करती है और व्यवस्थापिका समा से कानून बनाने की प्रार्थना करती है ।

कैबरेल काउन्सिल किसी एक पार्टी से नहीं बनाई जाती । उसके सदस्य विचार-निमित्त के समय व्यवस्थापिका समा में भी विरोधी विचार प्रकट कर सकते हैं ।

व्यवस्थापिका समा में उसका काफ़ी प्रभाव है किन्तु उनका मत नहीं होता ।

कैबरेल काउन्सिल प्रेसीडेंट, पाउलर, कैबरेल बोर्ड के स्वाभाविक, कमान्डर-इन-चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्यों की नियुक्ति करती है ।

: ८ :

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

### कैबिनेट

कैबिनेट इससेबल शक्ति के समान शासन कार्य नहीं करता । प्रेसीडेंट के अंतर्गत यह शासन विभागों के प्रधानों की समिति है । उसका वह कर्तव्य नहीं कि उनसे परामर्श करे, किन्तु ऐसा ही बताना हो गया है । प्रेसीडेंट कैबिनेट की स्वीकृति से उन्हें नियुक्त करता है, किन्तु वे कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । न कांग्रेस में उनका कोई स्थान होता है । योग्यता का कोई प्रश्न नहीं । प्रेसीडेंट जब चाहे उन्हें

अज्ञात कर सकता है। केवल पार्टी के हितों का ध्यान रखा जाता है। अठनी-अनरत तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून के विरोध (वकील) होते हैं। नये कैबिनेट सदस्यों की प्राप्ति कोई परिशिष्ट से प्रसिद्ध नहीं होती। यह उच्चरवाही मंत्री न होकर उसके व्यक्तिगत परामर्शदाता के समान होते हैं।

विभिन्न शासन विभागों के प्रधान हात हैं।

: ६ :

## सोवियत रूस

**केंद्रीय शासन समिति (Central Executive Committee)**—इसमें २०० सदस्य होते हैं जो आसत रशियन कमिश्न द्वारा चुने जाते हैं। यह पार्ष्वत्य पार्लियामेन्ट के समान कार्य करती है। यह कमिश्न के प्रति उच्चरवाही होती है और कमिश्न की बैठकों के अवकाश काल में वही कानून संशुद्धी, शासन संशुद्धी तथा नियंत्रण करनेवाली शक्तें सत्ता होता है। सदस्यों को "प्रैसीडेंट आथवा अध्यक्ष की सहमति के बिना" क्रेड नहीं दिया जा सकता। अवस्थिति अनिवार्य है। सदस्य किसी सोवियत में जा सकते हैं और सूचना माँग सकते हैं।

**अधिकार**—समस्त सरकार के अंगों का निर्देशन, भूमिका तथा रूपकों की सरकारों का नियंत्रण। यह समस्त कानून संबंधी तथा शासन कार्यों का एकीकरण करती है और उनमें सामंजस्य स्थापित करती है। आसत रशियन कमिश्न की आज्ञाओं (decrees) तथा सरकार के केंद्रीय अंगों की आज्ञाओं का निरीक्षण करती है और कमीशनरों (commissars) की या विभागों की आज्ञाओं पर अपनी अनुमति देती है। यह कमिश्न का अधिबेशन बुलाती है। कार्य का विवरण, अपनी नीति के संबंध में बहस्य देती हुई, देती है। विभिन्न विभागों तथा शासन के



विभिन्न भागों में नियुक्तियों करती है। और भी अधिकतर हैं, किन्तु उनका जाल एशियम कमिश्न के साथ सम्मिलित रूप में उपयोग होता है।

केंद्रीय शासन समिति कामूनों, रिपोर्टों को देखती है। ग्वाय तथा शासन के कामों में माय होती है। प्रत्येक सदस्य को सरकार के किसी न किसी केंद्रीय अथवा स्थानीय काम में भाग लेना होता है। इसकी बैठकें इस प्रकार से इन विभिन्न विभागों के जवाबदार पुनर्वित्तन के रूप में होती हैं और इनके सदस्य के होने हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय शासन समिति के सरकारी प्रतिनिधि होते हैं।

काउन्सिल ऑफ पीपुलस कमीटार 'जाल एशियम सेंट्रल रेक्यू क्यूटिब कमेटी' को नियुक्त करती है। यह सम्मल आशक्तों तथा विदाक्तों को प्रचलित करती है और केंद्रीय शासन समिति को इसकी सहायता देती है। केंद्रीय शासन समिति इनमें मंजूर कर सकती है या रद्द कर सकती है। किन्तु यदि आपत आवश्यक हो तो कमीशनरों द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता है। विदेशी मामलों, मुद्रा चलसेना, रद्द, ग्वाय, भूमि सामाजिक मसाले, शिक्षा, डाक तथा तार, राहों, सम्पत्ति, बसावात, कृषि, विदेशी वाणिज्य मोहन ( राज्य निर्वाचन ), सर्वोच्च न्यायिक काउन्सिल और स्वास्थ्य विभागों का भार इसके सदस्य सम्भालते हैं।

प्रत्येक सदस्य के साथ एक बोर्ड होता है। बोर्ड के सदस्यों के नाम केंद्रीय शासन समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। कमीशनर को मामले तय करने के अधिकार होते हैं। किन्तु बोर्ड यदि असहमत हो, तो किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी विषय प्रेसीडियम अथवा केंद्रीय शासन समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, किन्तु इसमें किसी आज्ञा का लागू होता दलता नहीं।

१ १० १

## आस्ट्रिया

### शासन विभाग

हमने पीपुलस कमिशनर होते हैं—एक प्रेसीडेंट, राष्ट्रीय मंत्री,

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, प्रांतीय सरकार के सदस्य—यह ज्ञाता के सहाय  
तथा प्रांतीय प्रतिनिधि चुनते हैं।

सह्यीय याचक समस्त निर्यातों को सरकारी रूप में लागू करने के  
लिए उत्तरदायी है। यह फ़ैब्रल असेम्बली के निर्णय पर हस्ताक्षर  
करता है। फ़ैब्रल कौंसिल का समापतिव याचक करता है। फ़ैब्रल  
कौंसिल याचक, वाइस-चायलर, और सहाय गंत्रियों से मिलकर बनती  
है। ये सबके सब नेशनल कौंसिल द्वारा प्रिस्तिपल कमेटी के प्रस्ताव पर  
उसी के सदस्यों में से चुने जाते हैं। यदि नेशनल कौंसिल की बैठक न  
हो रही हो तो अस्थायी रूप से प्रिस्तिपल कमेटी स्वयं चुनाव कर लेती है।  
नेशनल कौंसिल का अधिकार का प्रस्ताव गंत्रियों या किसी भी  
मंत्री को अल्लइका कर देता है।

बकट फ़ैब्रल कौंसिल द्वारा नेशनल कौंसिल के सम्मुख उपस्थित  
किया जाता है।  
सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट सरकारी पार्लियामेन्टरी सहायक होते हैं और  
गंत्रियों के आधीन होते हैं।

११

## जैकास्तोकिया

प्रत्येक कानून स्पष्टतया यह बतायेगा कि उस कानून को बनाने के  
लिए कौन सा सरकारी सदस्य उत्तरदायी है।  
गंत्रियों को व्यवस्थापिका समा के दोनों भवनों में उपस्थित होने तथा  
माध्यम देने का अधिकार तथा बुलाये जाने पर ऐसा करने का कर्तव्य है।  
बैठकों के अवकाश काल में और व्यवस्थापिका समा के मंग होने  
पर नये चुनाव के परिणाम तक—२४ सदस्यों की एक कमेटी ( जिसके १६  
सदस्य चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज द्वारा तथा ८ सदस्य सीमेट द्वारा चुने जाय  
हैं ) एक वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है। इन अवसरों पर यह  
आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करती है। इनमें कानून बनाना, सरकारी  
तथा राजन सचिवों पर नियंत्रण भी सम्मिलित है। चुनाव होने के  
पश्चात् तुरंत बना दी जाती है।

प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportioned Representation) कमेटी में चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ के चेम्बरमैन तथा डिपुटी वाइस-चेम्बरमैन सीनेट के वाइस-चेम्बरमैन भी सम्मिलित होते हैं। यह समस्त वैधानिक मामलों में भाग लेती है। किन्तु प्रेसीडेंट का बका डिपुटी प्रेसीडेंट का चुनाव नहीं करती और न वैधानिक कानूनों में संशोधन कर सकती है। न यह शासन विभाग की शक्तियों को परिवर्तित कर सकती है। यह राजस्व सम्बन्धी या सैनिक भार को भी नहीं बढ़ा सकती। न यह सम्मति दे सकती है और न कुछ की ही घोषणा कर सकती है। धारा ५४।

## १२

## स्वीडन

## शासन विभाग

कॉन्सिल ऑफ़ स्टेट—राजा के सम्मन्धी सदस्य नहीं हो सकते। इसमें विभागों के अध्यक्ष वरु की संख्या एक होते हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से दो ने पहिले पद ग्रहण किया हो। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विदेशी मामलों में विशेषतया विवरण रक्खा जाता है। जिन सम्झौतों की अवसंध आवश्यकता हो वह रीजलरग की अनुमति के बिना भी किये जाते हैं किन्तु उनको उपरवात् रीजलरग के समुक्त पेश किया जाना चाहिए।

यदि राजा का निर्णय विरुद्ध हो तो कौन्सिल विरोध कर सकते हैं, नहीं तो उल निर्णयों के लिये मंत्रियों को उत्तरदायी समझा गया है।

कोई आवश्यक नहीं कि वे किसी भी मन्त्र के सदस्य हो।

यदि किसी मंत्री का परामर्श राजा द्वारा कॉन्सिल ऑफ़ स्टेट के मुख्यालय पर भी ठुकरा दिया जावे तो वह त्यागपत्र दे देता है। उसे तब तक बैठना पड़ता है जब तक कि रीजलरग निर्णय न करे।

: १३ :

## नार्वे

### शासन विभाग

मंत्री की आयु कम से कम १० वर्ष है। संख्या सात। इसे कॉंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। मंत्री या स्टोर्निंग के सदस्य न हों कॉंसिल ऑफ स्टेट में लिये जा सकते हैं। कॉंसिल ऑफ स्टेट का प्रथम सदस्य दो मत दे सकता है। कोरम संख्या का आधा होता है। एक्ज-वर्से का अनुवासी होना आवश्यक है, नहीं तो सदस्यता के अनोख समझा जाएगा। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विवरण में विरोध का निर्देश होना आवश्यक है किसे कोई मंत्री राजा के साथ मिलकर पकड़ कर ले के अमिशन से बच सके।

इस प्रकार मंत्रीगण स्टोर्निंग में उपस्थित नहीं हो सकते। वह लैगसि के कुछ अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है और वे स्टोर्निंग के गुप्त अधिवेशन में भी जाता मिलने पर उपस्थित हो सकते हैं।

: १४

## ऐस्थोनिया

### शासन विभाग

मंत्रिमण्डल का चुनाव होता है।

१५

## स्पेन

स्थायी समिति (Permanent committee) जिसके २१ सदस्य होते हैं, और वे पार्टियों द्वारा अनुपात से चुने जाते हैं। यह

वैधानिक अधिकारों और विपुलियों के क़ेद तथा अभिप्राय में लगाने के मयभ में आ गारटी है, उसे मंजूर कर सकती है ।

१ १६

## वेल्जियम

मयियों को अधिक से अधिक परबन्धित किया जा सकता है ।

कानून से सेना की संख्या निबत है । यह कानून हर वर्ष जगते एक बार की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है ।

मन्त्री यदि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय के संबंध में मत दे सकते हैं । किंतु उनकी उपस्थिति व्यवस्थानिष्ठ सभा में आवश्यक है और उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहाँ भाष्य द्वारा करने का अधिकार है ।

१७

## इंग्लैण्ड

### कैबिनेट

इसमें मन्त्री सम्मिलित होते हैं—किंतु सभी मन्त्री कैबिनेट में नहीं बैठते ।

प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र देने पर राजा जाम्ब नेता को बुलाता है बशनि यह आश्चर्य नहीं कि वह किसी पार्टी का मान्य हुआ नेता हो ( उदाहरणार्थ १८३४ ई० में लार्डरोल्लरी, १६९२ ई० बोनर का ) वह प्रधान मन्त्रित्व इस शर्त पर ग्रहण कर सकता है जब पार्टी द्वारा नेता चुन लिया जावे । अल्पेक अवधियों पर ऐसा ही हुआ ।

कैबिनेट को आर्डर-इन-कौंसिल जारी करने का अधिकार है । ये किन्हीं ही उद्य के होते हैं । इनमें से कुछ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जाते । कभी कभी ४० दिनों तक पार्लियामे-

मेंट क सम्मुख रखे रहने हैं। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती है कि व्यवस्थापिका सभा के दोनों मजनों द्वारा ये स्वीकृत कर लिये जावें। कुछ क लिये साधारण कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है।

फौज तथा जल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर पोतलर ऑफ एस्टेब्लिश के पास जाते हैं।

मंत्रियों का सम्मिश्रित उच्चरामित्व होता है।

वेतन २००० पीएड वार्षिक से १०००० पीएड तक है। प्रधान मंत्री को ५००० पीएड<sup>१</sup> वार्षिक वेतन मिलता है। प्रत्येक साठ<sup>२</sup> पोतलर रिटायर्ड होने पर जीवन भर के लिए ५००० पीड वार्षिक पेन्शन पाता है।

प्रत्येक मंत्री को या तो व्यवस्थापिका सभा के किसी मजनों का या तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्तु पौच सैक्रेटरी आफ स्टेट से अधिक किसी एक मजनों के सदस्य न हों और न दूसरे मजनों से पौच से अधिक सांख्यिक-सैक्रेटरी लिख जा सकत हैं।

प्रधान मंत्री सलाह के नाम से कामगार सभा को मंग कर सकत है और ठोक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को भी बलगत कर सकत है (उच्चारणार्थ मोन्टेम्पू १९२२ ई में हटा दिवें गय थ) कैरीनेट का उच्चरामित्व है, किन्तु २९१२ में यह ठिकांट प्रथम बार ठोककर व्यक्तिगत मंत्रियों को जिनमें आपस में मतभेद था, व्यवस्थापिका सभा में उन मतभेदों को प्रकट कर लेने दिया गया और वे पद पर बने रह। (सर एच सेम्पुबल रिजिलिप स्लोडैक: ल-कर नीति पर। उन्होंने ओटावा पैक के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया)।

कमेडिबा के अवरमैन शोम्पता का ध्यान रखकर चुने जाते हैं—  
व्यार्षिक लिख नीच ग्यारी कमेडियों के पास जात हैं—कमेडियों के पास जान बाल सभी लिख विचार के बाद बापिल आन चाहिये—स्थावो

१—यू १९१७ का 'मंत्रियों का वेतन कानून' स्पष्ट है करता कि "यह प्रथम जो प्रधान मंत्री और कोष का अध्यक्ष है" १,००० पीएड वार्षिक पावेगा।

वैधानिक अधिकारों और विपुलियों के दौड़ तथा अभियोग में जमाने के समय में जो गारंटी है, उसे मसूमा कर सकती है।

१ १६ १

## घेरिजयम

मंत्रियों को अधिक से अधिक परख्युत किया जा सकता है।

कानून से सेना की संख्या नियत है। यह कानून हर वर्ष अगले एक वर्ष की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है।

मंत्री यदि व्यवस्थापिका समा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय के समय में मत दे सकते हैं। किंतु उनकी उपस्थिति व्यवस्थापिका समा में आवश्यक है और उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहीं माध्यम द्वारा करने का अधिकार है।

१७

## इंग्लैण्ड

### कैबिनेट

इसमें सभी सम्मिलित होते हैं—किंतु सभी मंत्री कैबिनेट में नहीं बैठते।

प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए पर राजा अथवा नेता को बुलाता है बशर्ते वह आवश्यक नहीं कि वह किसी पार्टी का माना हुआ नेता हो (उदाहरणार्थ १८६४ ई० में कार्लोत्तरी, १८९२ ई० बोन्स का) वह प्रधान मंत्री इस शर्त पर प्रस्ताव कर सकता है जब पार्टी द्वारा नेता चुन लिया जावे। उपरोक्त अन्तरों पर ऐसा ही हुआ।

कैबिनेट को चार्जर-इन-कौंसिल जारी करने का अधिकार है। वे कितनी ही तरह के होते हैं। इनमें से कुछ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जाते। कभी कभी ४० दिनों तक पार्लिया

मेंट के सम्मिल रहले रहते हैं। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती है कि व्यवस्थापिका समा के दोनों मण्डलों द्वारा वे स्वीकृत कर लिये जायें। कुछ के लिये साधारण कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है। कोष तथा बल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर मंत्रियों का सम्मिलित उपस्थित रहता है।

बेनन २००० पौण्ड वार्षिक से १०००० पौण्ड तक है। प्रधान मंत्री को ५००० पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है। प्रत्येक साइड पार्लियामेंट होने पर जीवन भर के लिए ५००० पौण्ड वार्षिक पेन्शन पता है।

प्रत्येक मंत्री को या तो व्यवस्थापिका समा के किसी मण्डल का या तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्तु पॉय सेक्रेटरी आफ स्टेट से अधिक किसी एक मण्डल के सदस्य न हो और न दूसरे मण्डल से पॉय से अधिक साइड-सेक्रेटरी लिये जा सकत हैं।

प्रधान मंत्री सम्राट के नाम से कामगार समा को भग कर सकता है और ठीक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को भी असह्य कर सकता है (उदाहरणार्थ मोन्टेग्नु १९१२ ई में हटा दिया गया वे) बेरीनेट का उपस्थित है, किन्तु १९१९ में यह सिद्धांत प्रथम बार लोकतन्त्र व्यक्तिगत मंत्रियों को किन्हीं कारणों में मतभेद या व्यवस्थापिका समा में उन मतभेदों को पकड़ कर लेने दिया गया और वे पद पर बने रहे। (सर एच सेम्पुलस प्रिंसिपल स्प्रैडिंग; तद-अन नीति पर। उन्होंने ओटावा पैक के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया)।

कमैटियों के बेरमेन बोम्बरा का ध्यान रखकर चुने जाते हैं— वार्षिक विधि नीति स्थायी कमैटियों के पास जाते हैं—कमैटियों के पास जाने बाल मनी मिल विचार के बाद वापिस आन चाहिये—स्थायी

२ —मार्च १९१७ का 'मंत्रियों का वेतन कानून' स्पष्ट है कहता कि "यह पुरुष जो प्रधान मंत्री और कोष का अध्यक्ष है" १०,००० पौण्ड वार्षिक पावेगा।



कमेटियों में सरकारी दल का बहुमत होता है लेकिन ग्राइवेट विलों<sup>१</sup> पर विचार करनेवाली 'सिलेक्ट कमेटियों' में सदस्यों को चुनते समय पार्टीबन्दी का ध्यान नहीं रखा जाता—ग्राइवेट विलों पर विचार करने वाली कमेटी में बार कामन्स सभा के सदस्य, पॉपुलर पार्टी सभा के सदस्य तथा एक प्रेसीडेंट होता है—यह तरीका सही होता है।

हाउस ऑफ़ कॉमन्स की एक 'ग्राइव कमेटी' होती है जो बार विभागों में बंटी रहती है; उसमें दो कानून बनाने के सम्बन्ध में और अन्य दो कार्यिक विलों को जोड़कर दोपहरी विलों पर विचार करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण मन्त्र की एक कमेटी होती है जो 'कमेटी ऑफ़ सफ़ाई' और 'कमेटी ऑफ़ केज पेयड मीम्स' कहलाती है। पार्टी प्रतिनिधियों की चुनी हुई ग्यारह सदस्यों की एक 'कमेटी ऑफ़ सलैय़शन' होती है जो 'सेल्य़स कमेटी', 'सिलेक्ट कमेटी' और अन्य कमेटियों को, जो विलों तथा ऐसे पापसों की जाँच करती है जो स्पष्टता राजनैतिक है। 'सेल्य़स कमेटी' के तीन विभाग होते हैं—पब्लिक एकाउन्ट, पब्लिक पिटीशन (प्रार्थना पत्र) और किचिन (kitchen) विभाग कहलाते हैं। 'सिलेक्ट कमेटी' के पार्लम सदस्य होते हैं किन्तु ग्राइवेट विलों पर विचार करनेवाली 'सिलेक्ट कमेटी' के केवल बार सदस्य होते हैं।

१ १८ ३

## डेनमार्क

### काउन्सिल ऑफ़ स्टेट

राज्य उत्तराधिकारी इसमें भाग लेता है। राजा समस्तलिख करता है। राजा की अनुपस्थिति में राजा द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री समस्तलिख

११—ग्राइवेट विल उन विलों को कहते हैं जो विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा विशेष स्थान के लिए होते हैं। यह समस्त बेरा वासियों और समस्त बेरा पर लागू नहीं होते।

## युनिटा क विधान

का शासन ग्रहण करता है। प्रधान मंत्री कार्यवाही का निरूपण राजा के पास स्वीकृति के लिए भेजता है और यदि राजा स्वीकृति न दे तो काउन्सिल आफ स्टेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। मंत्रियों पर राजा का कांसुलीन अधिनियोग लगा सकती है। रीगल्यूट अर्थात् म्यायालय अधिनियोग की सुनवाई कर अपना निर्णय देता है।

१६ :

## जापान

**कैबिनेट**—सम्राट को परामर्श देती है किन्तु (प्रमाणित) वाइड के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन विधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। राज के मंत्री संख्या में बस होते हैं। निदेशी मामलों, यद्वा, राजस्व, युद्ध, नौ सेना, म्याव, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, संदेश के साधन।

राजमन्त्र का भी एक मंत्री होता है किन्तु वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। मंत्री व्यवस्थापिका समा के किसी भी मन्त्र के सदस्य हो सकते हैं। और दोनों में ही भाषण दे सकते हैं। उनकी वाइड के प्रति उत्तरदायित्व की प्रथा १८९४ ई के पश्चात् से स्थापित हो चुकी है।

**मिथी काउन्सिल**—प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, पचीस काउन्सलर, एक चीफ सेक्रेटरी, और पाँच सेक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं।

काउन्सलरों में पराधिकारी होने के नाते राज के वे समस्त मंत्री होते हैं किन्तु कैबिनेट बनती है। काउन्सिल सम्राट को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देती है—

- (१) शासन विधान की उन धाराओं के विषय में किन्तु म्याफमा के सर्वज में संदिग्ध होता है।
- (२) देश में संकट-व्यवस्था प्रचारित करने के संबंध में।

( १ ) वैधानिक राजशाहों के संबंध में ।

( ४ ) सदियों के नियम में ।

( ५ ) प्रिंसी काउन्सिल के संगठन के नियम में और उन विषयों पर विचार को विशेष रूप में उठ लड़े हों ।

राजनीतिक संकट के समय कैबिनेट बनाने के संबंध में इससे परा मर्श लिया जा सकता है । कैबिनेट के समस्त कार्य तथा कानूनों के संबंध में शाह के सम्मुख उपस्थित किए जाने से पहले अपना शाह द्वारा स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव इसका परामर्श लिया जा सकता है ।

यह संघटन की वैधानिक परामर्शदाताओं की सर्वोच्च समिति है । इस प्रकार इसने आधिकारिक रूप में कैबिनेट का स्थान ले लिया है । ऐसा माना जाता है कि कैबिनेट के अधिकारों को इसने बढ़िया किया है और उन्हें सीमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

नोट—जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं जापानी शाह अन्तर मन्त्रिपरिषद् के निरीक्षण में बनाए गए नये शासन विधान के मसविदे<sup>११</sup> पर विचार कर रही है ।

२० :

## इटली

मंत्री व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में बैठ सकते हैं और मायब भी हो सकते हैं । उनके जंजर-सेक्रेटरियों को भी यह अधिकार प्राप्त है । ( इङ्ग्लैण्ड में ऐसा नहीं है ) ।

सदियों की संख्या पौरुष होती है । प्रत्येक का एक जंजर-सेक्रेटरी होता है जिसका प्रधान मंत्री नियुक्त करता है ।

सदियों को मन्त्रिमण्डल पार्टीयों से चोखा पड़ाने की ( मत के समान ) आवश्यकता नहीं होती ।

११—यह शासन विधान स्वीकृत किया जा चुका है पर अभी उसकी अंतिम रूपरेखा तामने नहीं आई ।



विवादालय ग्रन्थ व्याख्या के लिए 'कमेटी ऑफ प्रिन्सिपल्लेज' (इसमें दोनों पक्षों के तीन तीन सदस्य रहते हैं) को र्णित दिये जाते हैं। इसका प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जैसा व्यावधीय होता है।

१९१७ ई० से हाउस का स्पीकर निर्बिरोध पुनर्निर्वाचित हो जाता है।

२ :

## कैनेडा

### हाउस ऑफ कामन्स

हाउस ऑफ कामन्स का संगठन किसी भी समय निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है—

कैनेडा की जनसंख्या

क्यूबेक की जनसंख्या<sup>१०</sup>

प्रेसीडेंट इस अनुपात को रखते हुए मन्त्र की संख्या बढ़ा सकता है।

### राजस्व तथा बजट

व्यक्तिगत वित्तों की पहल कामन्स मन से ही की जा सकती है। किंतु उन पर गवर्नर-जनरल की छहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक रहता है। सभी उन पर विचार हो सकता है।

१४—इसका तात्पर्य यह है कि क्यूबेक प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ ही रहेगी। इस संख्या के क्यूबेक की जनसंख्या में विभाजन करने के प्रति लीड के पीछे जनसंख्या का अनुपात निश्चय आयेगा। बड़ी अनुपात से अन्य प्रांतों को भी लीड दे दी जावेगी।

केन्द्रीय सरकार विशेष कार्यों के लिये प्रांतों को नियुक्त रख  
 देती है।  
 १,८०,००० क्यूबिक, मार्बल मूर्तविक, और जोका स्कानिया  
 को भी।

: ३ :

## ऑस्ट्रेलिया

निचला मरुत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।  
 जबकि तीन बर्य यदि इसके पूर्व मंग न कर ही जाय।  
 मताधिकार योग्यता बालिग मताधिकार।  
 सीटों की संख्या ७५ इकाइयों की जनसंख्या के अनुपात से।  
 प्रत्येक को कम से कम ५ सीटें मिलती हैं।  
 यदि बिना आभा कोई बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सीट के रिक्त  
 हो जाने की घोषणा कर दी जाती है।  
 यात्रा की सुविधाएँ राज्य की ओर से बिना व्यय मिलती हैं।  
 कुछ अन्य बातें

स्पीकर केवल एक कारिंदग बोट देता है।  
 जनसंख्या की गणना में मूल निवासियों को नहीं गिना जाता।  
 पार्लियामेण्ट की सत्ता की व्याख्या स्वयं कैनेडा की पार्लियामेण्ट  
 कर सकती है। किंतु यह सत्ता ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स की सत्ता  
 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कामन्स मरुत के स्पीकर का केवल एक  
 कारिंदग बोट होता है।  
 मरुत शांति, व्यवस्था, सुरासन के लिये कानूनों को बनाता है।  
 ये कानून केवल उन विषयों से संबंधित हो सकते हैं जो प्रांतों के पास  
 उपस्थित नहीं।  
 राज्य युद्ध के समय मृतक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर  
 पाता है।

मकन केनौमेड पर नियंत्रण रक्ता है। इसकी सहा, कार्यवाही के निमित्त आदि ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्स के समान ही है।

१ ४

## दक्षिणी अफ्रीका

### हाउस आफ् असेम्बली

अबधि पाँच वर्ष, यदि इसके पूर्व भंग न कर दी जाय। सीधे प्रांतों से चुनाय होता है। संख्या १५०<sup>११</sup>।

केप कासेनी ५१, नैटाल १७, ट्रान्सवाल २६, ऑरेंज फ्री स्टेट १७।

यह संख्या कुल १५ तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु कम नहीं की जा सकती। प्रत्येक प्रांत के सीटों की संख्या उस प्रांत के पोस्टमैन मुख्य वास्तियों के अनुपात से निर्धारित की जाती है।

केप कासेनी में किसी को भी मताधिकार से विशेष कानून के दृष्टिकोण किसी रूप से संबंध नहीं किया जा सकता किंतु मूल निवासियों के मताधिकारी संघी कानून रिजर्व रल लिये जाते हैं।

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। स्थान प्रत्यक्ष करने के दिन से ४०० वोट्स बर्धक मिलता है। अनुपस्थिति के लिये १ वोट प्रति दिन कम हो जाते हैं।

उम्मेदवारों की योग्यता—प्रांतीय असेम्बली के सदस्य होने की

१५—यह मूल ग्रंथ का नवों का लो कथान्तर है। किंतु बोग लमाने से स्पष्ट है कि संख्या १२१ ही रह जाती है। बाद में संख्या बढ़ा देने की शक्ति का उल्लेख भी है। स्पष्ट है कि यह १५ संख्या अधिक से अधिक मिला है। वास्तव में सन् १९३४ ई. के कानून के अनुसार यह संख्या १५० ही कर दी गई है और अब प्रांतों में सीटों का विभाजन इस प्रकार है। केप ६२, नैटाल १६, ट्रान्सवाल ५७ और ऑरेंज फ्री स्टेट १६।

सोमिया आवश्यक—५ वर्ष से राज्य का निवासी हो। योरोपीय जिटिया प्रका हो। कोरम ५ ।

प्रेसीडेंट की केवल एक कार्टिया बोट होती है। सम्राट के प्रति राजमणि की शपथ ली जाती है।  
बैठक में गैर कानूनी तौर पर भाग लेने पर १० पौण्ड प्रति दिन का दण्ड। सदस्यों के अधिकार, सुविधाएँ इत्यादि प्रेसीडेंट नियंत्रित करता है।

राजस्व बजट संबंधी आर्थिक बिल केवल आसेम्बली में प्रारम्भिक रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं किंतु अधिवेशन के समय में अन्य संबंधी बिलों पर गवर्नर की स्वीकृति ले लेना आवश्यक है।  
पार्लियामेंट की सम्मिश्रित बैठक में सीनेट का प्रेसीडेंट समा पत्रित करता है। कानूनों पर गवर्नर-जनरल हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर किये हुए बिल सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कर दिये जाते हैं।

५

## न्यूजीलैण्ड

हाउस आफ प्रिन्सेडेन्स।

बालिय पुण्य मताधिकार, प्रत्येक पुण्य का एकमत। जब किया का भी समान मताधिकार दे दिया गया है।

मीटों की संख्या—७६। इसके अतिरिक्त ४ स्थान मारिय (यून निवासिया) के लिये नियत हैं।

वेतन—१० पौण्ड वार्षिक।

कानून बनाने की शक्ति सत्ता। शासन विधान परिवर्तित कर सकता है।

कानूनों का रिपोर्टर पार्लियामेंट में उपस्थित करता तथा पात्र करता है। सभी उसका सहायक के रूप में रहता है। वही स्वीकर को तथा बकाओं को बोलने के समय में उद्घोष देता है। बजट, जिसमें अन्य बातें भी भर दी जाती हैं, को बनेटी में तीन महोने लग जाते हैं।



पार्लियामेंट में बल के पूर्ण नहीं पहुँच पाता। अतएव, प्रथम अन्वरी एक या दो माह के लिये विशेष सौंगे स्वीकृत की जाती रहती है।

**कुछ अन्य बातें**

पुलित का प्रबंध डोमीनियन सरकार के हाथों में है।

उदत्त अल्पत संतर्क रहते हैं। १५४ के समान साधारण स्थानीय उदत्तों की ही मानना से ऊँचा नहीं उठ पाते। पत्तन नहीं है। उदत्त एजेण्ट के समान समके होते हैं।

३ ६ ३

## स्विटजरलैण्ड

**निम्नलिखित मन्त्र**

नेशनल काउन्सिल।

उदत्त संस्था १८७०, प्रत्यक्ष चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व आम वार्षिक मन्त्राधिकार।

आयु २० वर्ष।

अवधि ४ वर्ष।

नारियों को मन्त्राधिकार नहीं।

मन्त्राधिकारों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष १२,००० संस्था के पीछे एक के अनुपात से चुने जाते हैं। १,००० से अधिक के माग के लिये एक छोट दे दी जाती है।

**अयोग्यता**

कोई भी मन्त्राधिकार यदि पादरी न हो तो चुनाव का उम्मेदवार हो सकता है। नारियों को मन्त्राधिकार नहीं।

केन्द्रीय विधायी के लिये आचारसूत्र अधिकारों तथा अन्य कानून के संशोधन देखिये।

## फ्रांस

निचला मजदूर—सैम्यर आफ डिपुर्टेज

आय ४ वर्ष ।

मताधिकार—रिफरेंडम मतदाता—वे जोभी जो स्वतः का मत पर काम का क्यूटी पर लगे हैं, वोट नहीं दे सकते—अक्सर भी नहीं दे सकते—वालिफ पुरुष मताधिकार किंतु नहीं इसे आम मताधिकार करते हैं । एक मत से अधिक नहीं । अनिवार्य मतप्रदान नहीं ।

सीटों की संख्या—प्रत्येक डिपार्टमेंट<sup>१९</sup> में ७५००० के पीछे एक सदस्य और अतिरिक्त संख्या पर प्रति १७, ५०० के पीछे एक सदस्य प्रत्येक डिपार्टमेंट के कम से कम १ डिपुटी होते हैं ।

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र—यदि एक डिपार्टमेंट के ५ डिपुटी हो तो ही निर्वाचन-क्षेत्र होगा । कुल सदस्य ५८४<sup>२०</sup> जिसमें १० फ्रांसीसी उपनिवेशों के प्रतिनिधि, १० अफ्रीरिया के और २५ आस्ट्रेल-ओरेन के प्रतिनिधि होते हैं ।

नये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यों के होते हैं ।<sup>२१</sup>

बैठक—मंचा दिया जाता है ।

सोम्यता—डेनिक सेवा—वे अफसर, जो रिटायर्ड होन क शिव अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, सम्मोदवार हो सकते हैं । बैंक आफ फ्रांस के डायरेक्टर तथा उप-डायरेक्टर भी लगे हो सकते हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य अफसर भी, जो मेटेटेरियट, ग्वाव विभाग, धार्मिक विभाग में

१९—'डिपार्टमेंट' फ्रांस में शासन की इकाई को कहते हैं । हमने इसी के समान समझना चाहिए ।

२०—सन् १९१८ में यह संख्या ५१८ थी । इसमें ५१८ फ्रांस क सदस्य ( २५ आस्ट्रेल-ओरेन के इसी में शामिल हैं ), १० उपनिवेशों तथा ८ अफ्रीरिया के व ।

२१—नये शासन-विधान में देखा नहीं दे ।

अथवा फोफर हों, लगे हो सकते हैं। यदि कोई डिपुटी पेटन-भागी अफसर नियत हो जाय तो वह डिपुटी पद पर नहीं रह सकता किन्तु यदि उम्मेदवार होने की योग्यता उसमें हो तो दूसरी बार चुना जा सकता है। किन्तु चुनाव पत्रों में लम्बा से अधिक मत दे दिये जाते हैं वह अनियमित घोषित नहीं किये जाते, केवल ज्ञात में अधिक नामों को काट दिया जाता है।

क्लोजर<sup>११</sup> (closure) उम्मी लागू किया जा सकता है जब हो सदस्य बोल चुके हों। किन्तु मन्त्री उत्तर दे सकता है बशर्ति अतिम शब्द वाद-विवाद में साधारण सदस्य के होते हैं। एक व्यक्ति का भाषण दूसरे व्यक्ति दे सकते हैं किन्तु संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका के समान भाषण के बिना पढ़े प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। मत बैलट<sup>१२</sup> प्रस्तुत दिये जाते हैं किन्तु बस्तुतः वह खुले ही रहते हैं। किन्तु अपना सदस्य मंच पर बैलट द्वारा मतदान की मींग कर सकते हैं। ऐसी हस्तत में कर्णातुसार (Alphabetically) सदस्यों को बुलाया जाता है। प्रश्न के बाद बहस होती है और विदेशी नीति के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर मत लिए जाते हैं। पहले इस प्रस्ताव पर मत लिए जाते हैं कि मदन अपनी कार्यवाही जारी रखे। जेम्स केक्स दिग्गज भाष<sup>१३</sup> को एक कानून बनानेवाली संस्था है।

११—क्लोजर (closure) का तात्पर्य उस तरीके से है जिसके द्वारा बहस को काफ़ी जल्दी खत्म करने से रोका जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यवाही में व्यर्थ बेटी न हो और कार्य सुचारु रूप से चल सके।

१२—बैलट (Ballot) मत-पत्र को कहते हैं। बैलट द्वारा मत-दान का उद्देश्य यह है कि मत गुप्त रूप से दिया जा सके। मत-दाता के अतिरिक्त कोई भी यह न जान सके कि मत कितने दिये हैं। मत-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते।

१३—इस कपन का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वास्तव में कैबीनेट के अत्याधिक कारण जेम्स के पास ही वास्तविक शक्ति है।

बजट चाहू और विरोध लक्षों में विभाजित रहता है। विरोध ध्वज चाहू ध्वज के भाग नहीं समझे जाते। उनके लिये धन उधार लिया जाता है। इस विरोध ध्वज में लगभग चालीस पचास हजार मरें रहती हैं। बजट कमीशन राजस्व व्ययों की सलाह और मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता है। कमीशन मंत्रों को पटा बढ़ा सकता है किन्तु बजट में मंत्रियों को स्वीकृति आवश्यक है।

बजट की पापसा दोनों मंत्रों की सहमति के बिना नहीं की जा सकती।

सदस्यों को १०,००० पाउंड व्यय ५,००० डॉलर मिलते हैं। वे अपने पुत्रों, बान्धवों और मित्रों के लिए नौकरी और पद लोकावली करते हैं। वे सम्मान विद्व नौकरी और सम्मान वेधने के लाइसेन्स, की लोक में भी रहते हैं। सदस्य भवन के सामने विचार प्रकट करते हैं, प्रेसीडेंट के सम्मुख नहीं।

जीनेट और बैम्बर काक रिपुटीन दोनों का अविवेशन पाँच महीने तक चलता रहता है।

प्रेसीडेंट एक बार में बैम्बर को एक माह के लिए स्वर्गित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में वह दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

८

## जर्मनी

### निवृत्ता भवन रीजस्टाग

अवधि चार वर्ष

आम मताधिकार, मध्यम चुनाव, आधुनिक प्रतिनिधित्व, दोष वर्ष की आयु।

२२ सीटों की संख्या—निवृत्त नहीं है।

१०, ०० मत देने वालों के पीछे एक सदस्य। मत कार्य-क्रम

नीतियों और सिद्धांतों के ऊपर दिए जाते हैं—व्यक्तिगत पर नहीं। वैसीत विधीयनों की तरह यूनिटनों की और एक राष्ट्रीय साक्षिका तैयार की जाती है और उससे इन साक्षिकाओं से कम से जुने जाते हैं। पहले विधीयन की साक्षिका से तीन सदस्य लिखे जाते हैं—उसके पश्चात् यूनिटन की साक्षिका से और अन्त में राष्ट्रीय-साक्षिका से।

( अ ) एकाधिकारी ( exclusive ) कानून सम्बन्धी शक्तियाँ

( ब ) कानून उभरी सम्मिश्रित<sup>११</sup> ( concurrent ) शक्तियाँ

( घ ) सिद्धान्त सम्बन्धी कानून।

रीज को आर्थिक विषयों में इकाइयों पर विशेषाधिकार प्राप्त ( over-riding powers ) है। रीज के कानून इकाइयों के कानूनों को इन विषयों में रद्द कर देते हैं—मतमेव का नियन्त्रण सुप्रीम कोर्ट करता है।

सैन्य अफसर यदि चुनाव लड़ रहे हों अथवा समाजों में सम्मिश्रित होना चाहते हैं तो उन्हें कुछी अवश्य देनी होती है। प्रेसीडेंट तथा व्यवस्थापिका समा को विशेष ढंग की सुविधायें मिली हुई हैं।

विदेशी मामले—सीमायें ( इकाइयों की सहमति से, तथा भी ) औपनिवेशिक मामले और डाक तथा तार—इन विषयों में केवल रीज को ही तथा प्रभु है।

प्रेसीडेंट पर अभियोग—१०० सदस्यों के इस्ताफर से और बहुमत के पास कर देने पर लगाना जा सकता है। वही ढंग शासन विधान में परिवर्तन के लिये नियत है। अभियोग सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है जो इस संबंध में अपना निर्णय देती है।

इकार्त्त राज्य रीज के कानूनों को लागू करते हैं, रीज का नियंत्रण रहता है। बैठकें प्रेसीडेंट द्वारा स्वयं या एक-तिहाई सदस्यों कीमार्ग पर बुलाई जाती हैं। मकन स्वयं अपना बैयरमैन, डिपुटी बैयरमैन तथा

११—सम्मिश्रित साक्षिका ( concurrent list ) में वे विषय होते हैं जिन पर केन्द्रीय तथा यूनिट दोनों की सरकारें कानून बना सकती हैं, पर उक्त विषयों पर केन्द्रीय कानून यूनिट के कानूनों की दृष्टि में माग्य समझे जाते हैं।

सजेस्ट्री पुनरा है और स्वयं कार्यवाही के नियम निर्धारित करता है। अधिवेशन खुले होते हैं किन्तु दो-तिहाई के बहुमत से गुप्त बैठक को मींग को का सकते हैं। यदि रीजलरस के एक-तिहाई सदस्य कहें तो कामूनों को २ माह तक लागू होने से रोक दिया जाता है। इसी अधि के अन्दर कमी भी दोनों यवन अपना निर्णय दे उन्हें कमी भी लागू करा सकते हैं।

१ ६

## सोवियत रूस

कौंसिल आफ पीपुल्स कमीसार सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी तथा अल रशियन कोंग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। पीपुल्स कमीसार तथा बोर्ड कौंसिल आफ पीपुल्स कमीसार तथा अल रशियन कोंग्रेस की सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अल रशियन कोंग्रेस तथा सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी समस्त राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर नियन्त्रण रखती है। इसमें विदेशी संबंध, सन्धियों पर अंतिम स्वीकृति, प्रादेशिक मिश्रणधर्म भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नीमाओं तथा राज्यों की अलहदगी; मुद्रा तथा शान्ति; उधार का धन तथा कर; उद्योग तथा व्यापारिक सम्झौते; न्याय कार्य; अन्न रिहाई इत्यादि भी इन्हीं के अधिकार में हैं। यह पीपुल्स कमीसारी के नेबरमैन की नियुक्ति तथा बावली (हटा देना) भी करते हैं। रशियन तथा विदेशियों के नागरिक अधिकारों का धरन; लैला तथा नारा; अपराध तथा दण्ड; मुद्रा, आर्थिक जीवन का संगठन; बजट; सना; कामून बनाना और न्याय इन्हीं के अधिकार में हैं।

प्रताधिकार—आम—आयु १८ वर्ष। निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं। १ बीबिडोनार्न किसी उदात्तन कार्य से करता हो। २ किसी यह-कार्य—व्यापार अथवा उद्योग धंधे में लगा हो। ३ अल और स्वयं सेना का प्रौढी हो। ४ नागरिक हो पर कार्य करने में अग्रमर्ष हो। न्यायीय सोवियत सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति

सं आमु संर्बनी शोम्पता को कम कर सकती है। ५. आम करने वाले सिरेली।

अयाम्पताये<sup>१३</sup> १. जा सामार्थ दूसरो सं सवा करात हो। २. जो पूजी, मूमि अथवा उद्योग की आमु पर रहते हो। ३. व्यक्तिगत व्यापारो एजेंट तथा मध्यस्थ। ४. पादरी तथा संत। ५. विप्लवी पुलिस के एजेंट और स्वामी। ६. विरुध पुलिस के दस्ते अथवा गुप्त पुलिस के सदस्य। ७. शासक आति के सदस्य। ८. नायासित तथा विकृत मस्तिष्क वाले। ९. वह किन्को किसी धुरे (infamous or mercenary) अथवा में रहत मिल चुका है।

वजहः—आल रशियन सेन्सुस एक्जोस्पूटिब कमटी जा राज्य तथा स्थानीय सोवियतो में विभाजित है। सोवियत केवल स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के सिरे कर लगा सकती हैं। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से होती है।

आल रशियन कॉंग्रेस<sup>१४</sup> नगर सोवियतो का प्रतिनिधि प्रत्येक २५०० व्यक्ति के पीछे १ के अनुपात से आते हैं। गवर्निया (प्रान्तीय) कॉंग्रेस से प्रत्येक १,२५,००० व्यक्तियों के पीछे एक। तन् १९२१ ई. में इसके १६११ सदस्य थे। वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसके पास सर्वोच्च राजनैतिक तथा है। आल रशियन कॉंग्रेस के विशेष अधिकार निम्नलिखित हैं—

(१) सोवियत शासन विधान में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार इसे प्राप्त है।

१३—सोवियत के १९१९ ई० के नवीन शासन विधान में यह अनोम्पता हटा दी गई है। पारा ११५ के अनुसार केवल वही व्यक्ति मत नहीं दे सकते किन्का या तो मस्तिष्क विकृत है अथवा म्वायास्य ने किन्से महाधिकार छीन लिया है। अनोम्पता हटाने का कारण स्पष्ट है। १९१९ ई० तक राज्य प्रकार के अनोम्प व्यक्ति या तो समाप्त हो चुके थे या उनका विचार-परिवर्तन हो चुका था।

१४—तन् १९१९ के नवे शासन-विधान के अनुसार इसके संघठन आदि में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं। विशेष शान के सिरे देखिये परिशिष्ट में-सोवियत संघ का नवीन शासन विधान।

( २ ) यह सन्धियों पर अन्तिम स्वीकृति देती है ।

आल रशियन काँग्रेस का शेष अधिकारों के बिना ऊपर की टिप्पणी पढ़िये । इसके अन्तर्गत ऐकजीन्यूटिन कम्पनी के साथ सम्मिलित रूप में है ।

स्थानीय सोवियत सत्ता का संगठन<sup>१५</sup> सोवियतों की काँग्रेस ( अ ) सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों ( प्रति ५ • मतदाताओं के पीछे २ प्रतिनिधि ) तथा ग्रामीण सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों ( प्रति २५ • निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि ) से मिलकर बनती है । समस्त प्रतिनिधियों की संख्या अधिक से अधिक ३० होती है—सोवियतों की भी वही अधिकतम संख्या है । यदि प्रादेशिक काँग्रेस के ठीक पंद्रह सोवियतों का अधिवेशन हो तो इसी में चुनाव हो जाता है ।

( ब ) ग्रामीण अधिका गृहपरमिया—इसमें नगर सोवियतों के प्रत्येक १, • मतदाताओं के पीछे १ तथा सोवियतों की काँग्रेस के ग्रामीण विवीकनों से प्रति १० •• निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि निर्वा जाता है ।

नेशनल असेम्बली ।

१०

## स्त्रावों, कोटों तथा मर्षों का राज्य<sup>१६</sup>

नेशनल असेम्बली

अवधि ४ वर्षों ।

प्रति ४०, •वासियों के पीछे १ प्रतिनिधि ।

महाधिकार आम समान प्रत्यक्ष तथा गुप्त ।

१५—इसमें भी अब अनेक परिवर्तन हो चुके हैं ।

१६—जैसा कि हम पहिल बट्ट आये हैं, यूगोस्लाविया में अनकों परिवर्तन हो चुके हैं ।



११

## जैकोस्लोवाकिया

चेम्बर आफ डिपुटीज़

आयुधि ६ वर्ष ।

मताधिकार आम उमान, प्रत्यक्ष मताधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व । वयस्क मताधिकार । आयु २१ वर्ष, उम्रदवार की आयु १० वर्ष ।

संख्या १० ।

प्रत्यक्ष चेम्बर स्वयं अपना चेयरमैन चुनता है ।

उन पर अधिनियोग—संग्राहकीय के अतिरिक्त—केवल उसके चेम्बर की सहमति से लगाया जा सकता है । उसे बिना चेम्बर वा कमेटी की आज्ञा, अतिशय १४ दिन में चेम्बर स्वीकृत कर ले के पकड़ा या कैद नहीं किया जा सकता ।

वे किसी भी ऐसे विषय में साक्षी सदस्यता से अलग हो जाने पर भी, नहीं वे सकते जो उन्हें सदस्यता के नाते बताई गई हैं ।

कानून किसी भी मकान में उपस्थित किया जा सकता है । उनमें पर स्पष्ट ठसठस होना चाहिए कि कानून का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा । कानून बनने में दोनों मकानों की स्वीकृति आवश्यक है ।

वज्रद निम्नले मकान के अधिकार में है ।

यदि सरकार एकमत होकर कोई बिल उपस्थित करे और नेशनल असेम्बली उसे अस्वीकृत कर दे तो वह चेम्बर आफ डिपुटीज़ के समस्त मतदाताओं के समस्त राय के लिये भेजा जाता है किन्तु सरकार द्वारा प्रस्तावित वैधानिक परिवर्तनों में इस प्रकार की राय नहीं ली जाती ।

असेम्बली को प्रेसीडेंट चुनाता है जबकि पूर्ण बहुमत द्वारा वह मींग की बात—जहाँ वो किसी भी चेम्बर का चेयरमैन होता कर सकता है । यदि अंतिम अधिवेशन को समाप्त हुए ४ मास बीत चुके हो तो नये अधिवेशन की मींग के लिये  $\frac{2}{3}$  का बहुमत काफी है ।

कोरस दो-तिहाई बहुमत ।

प्रेसीडेंट या काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स पर अभियोद्योग लगाने के लिये कोरम दो-तिहाई का बहुमत होता है और प्रस्ताव की स्वीकृति दो तिहाई के बहुमत से ही आनी चाहिए।

नेशनल असेम्बली के सदस्य सदस्यता समाप्त होने के पश्चात् एक वर्ष तक नौकरी नहीं कर सकते। यह नियम मंत्रियों पर लागू नहीं होता। किन्तु सरकारी नौकर जुने जा सकते हैं। उन्हें छुट्टी दे दी जाती है और उनके वेतन में कटौती भी होती रहती है। वे अवधि की समाप्ति पर फिर पदाब्द कर दिये जाते हैं। यही बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिये लागू है। डिपार्टमेंटों के प्रीफेक्ट नेशनल असेम्बली या वैधानिक स्थापनाओं के सदस्य नहीं हो सकते—जुनाव संबंधी स्थापनाओं तथा डिपार्टमेंटों को काउन्सिलों।<sup>१४</sup>

११२

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

निचला मकान

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स।

अवधि २ वर्ष।

सदस्य राज्यों (इकाइयों) की जनता द्वारा चुने जाते हैं। मत-विचार बोधमत्ता बड़ी होती है जो राज्य के निचले मकानों के संबंध में निर्धारित है।

सदस्यों की बोधमत्ता आयु २५ वर्ष। ७ वर्ष का निवास—निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए। सीटों की संख्या मतदाताओं के अनुपात से प्रत्येक राज्य में नियत की जाती है। वे मूल निवासी इतिहास, जो कर नहीं देते, शामिल नहीं किये जाते।

अयोग्यतायें-राज्यविद्रोह। अयोग्यता कौंग्रेस द्वारा हटा दी जा सकती है।

१५ जैसा हम ऊपर कह आये हैं वहाँ भी नया शासन विधान बन रहा है।

बैठकों के लिये फोरम, स्वगित नियम, सदस्यों को भवन से बाहर करने इत्यादि के संवध में मीनेट के कालम में देखिये ।

उन्हें १५० पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है ।

संख्या ४३५ ।

**अधिकार**

समस्त वार्षिक वित्त निचले भवन में प्रथम बार विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बहुत कम देना होता है कि सम्बन्ध सदस्य बैठकों में उपस्थित हो पार-समा के प्रति अन्याय प्रकट करें ।

१ १३ :

## पोलिश प्रजातन्त्र

निचला भवन बाह्य ।

अवधि ५ वर्ष ।

महाधिकार आम, गुप्त, समानमताधिकार—अनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

कमस्क महाधिकार । इसीस वर्ष की शानु—उक्ति क्यूरी पर नियुक्त फ्रीरी बोर्ड नहीं दे सकते ।

राज्य विभाग, शासन तथा ग्वाव ( केन्द्रीय नहीं ) विभागों के सकाराई अफसर उन स्थानों से नहीं चुने जा सकते जहाँ ५ वर्षों पर नियुक्त हैं । जब चुन लिये जाते हैं वे शुभितार्थ उचित छुट्टी दे दी जाती है ।

**अधिकार**

१—सेवा पर सर्वोच्च निबन्धन का अधिकार व्यवस्थापिका तथा में निहित है ।

२—बाह्य द्वारा कानून बनाने में पहल की जाती है ।

३—निर्बिरोध पुनः के सम्बन्ध में बाह्य भूमकों का फैसला करती है ।

४—ग्राम रिहाई केवल व्यवस्थापिका समा द्वारा की जा सकती है।

सुविधायें

सुविधानों और आयोम्पताएँ—

(अ) किसी बिन्दी पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता।

(ब) भूमि नहीं लूटी जा सकता।

(ग) ऐन्य सम्बन्धी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई आदर सूचक चिन्ह या पद नहीं पहना कर सकता।

(द) एक ठप्परवाली सम्पादक नहीं हो सकता।

: १४

## आस्ट्रिया

निचले मजदूर के अधिकार

नेशनल काउन्सिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक कमेटी नियुक्त करती है जो संघ के शासन कार्य में, संघीय सरकार के बनाने में सहयोग देती है और संघीय सरकार की उन आकांक्षों को जारी कराने में सहयोग देती है जिनके लिए इसकी सहमति आवश्यक है।

नेशनल काउन्सिल

मताधिकार समान, प्रत्यक्ष, गुप्त, व्यक्तिगत बीस वर्ष या उससे अधिक आयु के नर-नारियों को प्राप्त है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठप्परवालों की आयु कम से कम बीबीस वर्ष की होनी चाहिए।

अधिकांश मतदाता

सौदों की रकम नागरिकों की संख्या के अनुपात से होती है।

मजदूर की बैठक या लो वेयरमेन स्वयं चुना सकता है अथवा वह एक थोड़ा सब्सिडी की भाँति पर चुना जाता है। केवल स्थिति या भाग कर सकता है।

कोरस : १

अधिकार

दोनों मदन संघीय सरकार से कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दोनों मदनों का सदस्य नहीं हो सकता। सरकारी नौकरों को सदस्य बनने के लिए विशेष आज्ञा नहीं लेनी होती।

कानूनों को नेशनल काउन्सिल में संघीय सरकार विधायक उपस्थित कर सकती है या वह संघीय सरकार द्वारा केंद्रीय काउन्सिल में उपस्थित किया जा सकता है। २०० • मतदाता या तीन प्रश्नों के आगे मतदाता किसी भी कानून को बनाने की मांग कर सकते हैं। कानून बनाने का वह ढंग जनता द्वारा प्रारम्भ (popular initiative) कहा जाता है।

प्रत्येक कानून यदि नेशनल काउन्सिल निर्णय करे या बहुमत प्रार्थना करे तो जनमत जानने के लिए भेजा जा सकता है।

राज्य संघियों के लिए नेशनल काउन्सिल की स्वीकृति आवश्यक है। संघीय सेना नेशनल काउन्सिल के नियन्त्रण में रहती है।

कुछ की शोषणा संघीय व्यवस्थापिका समा अर्थात् दोनों मदनों का सम्मिलित अधिवेशन करता है। सम्मिलित अधिवेशन का चेयरमैन बारी बारी से नेशनल काउन्सिल और केंद्रीय काउन्सिल के अध्यक्ष होते हैं। कुछ विषयों में संघीय सरकार विद्वानों को निर्धारित करती है—प्रांत उन्हें कार्य रूप में परिचित करते हैं—प्रश्नों के शासन का संगठन—भूमि शुद्धार—बंगल—विजली की शक्ति—हमारे—प्रान्तीय अफसरों की नौकरी के सम्बन्ध में नियम।

१ १५

स्वीडन

रिफरेंडा

रिफरेंडा निम्नलिखित कमेडियों को नियुक्त करती है। वैधानिक—राज्य—मांग—बैंक—कानून—क्षति। प्रत्येक अधिवेशन सोसाइटी व्यापिकों की एक कमेटी नियुक्त करता है जिसका कार्य राजा से विदेशी सम्बन्धों पर परामर्श देना होता है।

राजा की उपस्थिति में विचार विनिमय नहीं किया जाता।

२१०—बेहात और नगरों का अनुपात—१५० ८०।

ग्राम पुरुष मताधिकार १६०६ ई. से जारी हुआ।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दोनों मजनों के चुनाव में लागू है।

अवधि चार वर्ष।

स्त्रियों और पुरुषों को २१ वर्ष की आयु में मताधिकार मिल जाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ स्थान रिक्त होने पर पूर्ति के लिए व्यक्ति भी जाते जाते हैं (छोटे मजनों के कालम में देखिए)।

दोनों मजनों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

साधारणतया व्यवस्थापिका तथा में दिये गए मापदंडों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती किन्तु मजनों के बहुमत से अधिवोग लगाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

रिकरूटिंग का अधिकार प्रत्येक बल जनवरी को प्रारम्भ होता है। राजा की उपस्थिति में रिकरूटिंग अवकाश तक कोई कमेटी विचार विनिमय नहीं करती।

१६।

नार्वे

स्टोर थिंग

मताधिकार योग्यता २१ वर्ष की आयु—५ वर्ष का निवात।

अयोग्यताएँ—किसी अपराध में दण्ड—व्यक्तिगत मामलों में मारपीत के कारण दण्ड—अपनी सरकार की बिना अनुमति के विदेशी राज्य की मौकरी—मृत तरीकने का बेचने के कारण दण्ड—एक स्थान से अधिक पर बोट दिया हो। असमर्थ व्यक्ति मत देन सकते हैं।

अवधि चार वर्ष।

सदस्य संख्या १५०; नगर और बेहात का अनुपात—१ २।

क्रियेयमाना ७ सीट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

एक तिहाई सदस्य शहरी निर्वाचक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और

बो-तिहार माले के बेरात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सम्मेलन का अनु १० वर्ष—१० वर्ष का निवात। मन्त्री और पुराने मन्त्री सबस्व जुने जा सकते हैं। अछतर सबस्व नहीं हो सकते। जुने जाने पर सबस्वता स्वीकृत करानो पड़ती है किन्तु यदि वह होबारा जुना गबा हो और वह पहले जुनाब के परभात् तीन अभिवेशनों में उपस्थित रह चुका हो तो वह अनिवार्य नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आम्य व्यक्ति जुने जा सकते हैं।

मन्त्रा १०० क्रोनन मार्ग व्यय।

निर्दिष्टा के लिए व्यय मिलता है और सेवार्थ (parliament) मन्त्रे। सबस्व और आवकाश के समय स्थान ग्रहण करनेवाला व्यक्ति मन्त्रे के सम्मन्ध में प्राप्त में उन कर लेते हैं।

विरोध उपस्थिति—१२ क्रोनन प्रतिदिन मिलता है और खदेब की भाँति मुनिवाप।

कानून पहले स्टोर रिय में प्रस्तावित किए जाते हैं तत्पश्चात् लैबरियन को भेजे जाते हैं।

कूटनीति के सम्मन्ध में रिपोर्ट की माँग की जा सकती है पर वह रिपोर्टें ६ व्यक्तियों की एक कमेटी के सामने रानी जाती हैं। समझौते की गुप्त छठे प्रकाशित छठों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

स्टोर रिय का अभिवेशन प्रतिवर्ष १० जनवरी के बाद आने वाले सोमवार को प्रारम्भ होता है। दोनों मन्त्रों में क्रोनन सबस्वों की संख्या का बो-तिहार होता है। प्रत्येक मन्त्र अपना प्रेसीडेण्ट चुनता है। स्टोर रिय क्रोननिकल आफ स्टेट से वह माँग कर सकती है कि वह अपनी रिपोर्टें इसके सम्मुख पेश करें।

व्यवस्थापिका सभा की बैठकें खुली होती हैं किन्तु यदि आने सबस्व माँग करें तो गुप्त हो सकती हैं।

११७ :

## एस्थोनिया

केवल एक मन्त्र

महाविचार : समान—गुप्त—आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

अबधि तीन वर्षों ।

सदस्य संख्या १०० ।

मरदाताओं की योग्यता

आयु २० वर्ष—ऐरवोनिया की कम से कम एक वर्ष से प्रभा हो ।  
मरदाताओं का समा के सदस्यों से सैनिक सेवा नहीं ली जाती ।

अयोग्यताएँ

विद्वत् मस्तिष्क—अध्यापन—गुणापन—बहारापन—सर्वोत्तम—  
कानूनी बली ( Guardian ) नियुक्त हो और विशेष अपराधी वर्ग  
के लोग ।

पाठ हुए कानूनों का जारी होना एक तिहाई सदस्यों की मांग पर  
हो माह के लिए स्वगित किया जा सकता है और यदि इस अवधि के  
अन्तर २५००० मरदाता मांग करें तो कानून अनमत संग्रह के लिए  
मेत्र दिए जाते हैं और कानून का निर्णय अन्तिम होता है ।

कानून द्वारा पहल कोई भी १५० मरदाता विल उपस्थित कर  
पह मांग कर सकते हैं कि असेम्बली या तो उसे स्वीकृत कर ले या  
अस्वीकृत करे ।

अस्वीकृति की अवस्था में अनमत संग्रह निर्णायक होता है ।

यदि असेम्बली की राज के विरुद्ध अनमत-संग्रह का निर्णय हो तो  
मद चुनाव ७५ दिन में होते हैं ।

बजट उपहार का मामला, कर लगानेवाले कानून, पुनः शान्ति  
और सन्निधि अनमत संग्रह के लिए मही मेत्री जाती ।

अनमत संग्रह की प्रथा ही इस प्रकार से सैन्य भवन के कार्य समा-  
हित करती है ।

मरदाताओं का समा के अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोम  
वार से प्रारम्भ होते हैं । एक-दो-तीनों सदस्यों की मांग पर भी अधिवेशन  
हुताए जाते हैं ।

मरदाताओं का समा विद्वान् चेयरमैन की अध्यक्षता में अपने चेयर  
मैन का चुनाव करती है ।

येठके चुनी होती हैं; डिप्टी दो तिहाई सदस्यों की मांग पर गुप्त  
येठके की जा सकती हैं ।



हाउस आफ कामन्स

सदस्य संख्या १४ ।

मताधिकार वयस्क मताधिकार, आयु २१ वर्ष, जो महीने से उस निर्वाचन क्षेत्र में या समीप के निर्वाचन क्षेत्र में रहता हो—अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके काम का आश्रित दुकान, गोदाम इस दीर्घ वास्ताना किराये का हो। उनमें उसके स्वयं रहने की आवश्यकता नहीं। जो निर्वाचन क्षेत्रों में निवास और मकान की योग्यता के कारण मत दे सकता है। अतएव व्यापारियों को मजदूरों से अधिक सुविधा है।

यूनीवर्सिटी—समस्त वयस्क पुरुष प्रेजुएंट।

अयोग्यताएँ—विदेशी, अकिंचन, जार्ज तथा के सदस्य और संस्थाओं में रहनेवाले विद्वत् मस्तिष्क वाले व्यक्ति।

नामजदगी का पत्रा दाखिल करने का समय एक वर्ष—२५० पौंड जमा करने पड़ते हैं। यदि किसी उम्मेदवार को पढ़ने वाले मतों का है नाम न मिले तो वह अमानत जप्त हो जाती है।

मतदाताओं की सूची पर पर बाहर तैयार की जाती है। पार्लियामेंट अपना अवधिकार केवल हाउस आफ कॉमन्स के ही रखी होने पर बना सकती है।

अनुपस्थित मतदाता यदि देश के अन्दर ही हो तो डाक द्वारा मत दे सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को बिना डाक व्यव हरेक मतदाता के साथ एक पत्रा मेजमे का अधिकार है।

कोई सदस्य त्यागपत्र नहीं दे सकता, पर यदि कोई ऐसा करना ही चाहे तो उनके लिए नाममात्र का कोई पद दे दिया जाता है जैसे चिकित्सक इंग्लैण्ड अथवा लॉकास्टर की बंधी जिनमें कुछ नहीं करना पड़ता। यह बाकायदा निमुक्ति समझी जाती है यद्यपि केवल एक मन्त्री के लॉकास्टर की बंधी के पाने के समय के अतिरिक्त कोई बैठन नहीं देना पड़ता।

यदि हीकर वह समझे कि 'होमर' लगाने से मन्त्रिमण्डल के साथ

अप्यक्त होता है तो वह उसे न लगाए—यस वर्ष से प्रयुक्त नहीं हुआ—अब भी इच्छा हो स्वीकर अपनी आका से दर्राक गैसरी लान्नी करा सकता है।

फर लगानेवाला बिल एक पञ्जिक बिल है—किन्तु बिनका म्युनि तिपेसदियों का रेलों से सम्बन्ध होता है प्राइवेट बिल कहलाते हैं—प्राइवेट सदस्य पञ्जिक बिल विचारार्थ उपस्थित कर सकते हैं—लेकिन प्रार्थनापत्र पर आचारित प्राइवेट बिल ऊँचे या निचले किसी भी मकल में उपस्थित किये जा सकते हैं।

काम्पस तथा का कोरम ४० है—प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर के परचात् ४० सदस्यों द्वारा अकन्तोपजनक उत्तर बताकर स्थगित प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने की आका से भी जाती है। मकल अब चाहे स्थगित हो सकता है किन्तु मकलों के अभिवेदाय छाव छाव समाप्त होते हैं। चुनाव के बाद स्वीकर पार्टीबन्दी में नहीं पड़ता। अमेरिका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रथा इसके विररीत है। वहाँ चुनाव के पश्चात् स्वीकर और मो अचिक पार्टी भावना से प्रेरित हो जाता है।

१ १६ १

## स्पेन

कार्टेज़

२१ वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्य हो सकता है।

४ वर्ष की अवधि।

२० १

## फ्रान्स

इच्छे किसी मकल की बैठक अनियमित है, सीनेट केवल न्यायालय

के रूप में कार्यशील बैठक कर सकता है। ऐसे समय सीनेट स्वयं अपने अधिकार से बैठकें करती है।

बैठकें सुली होती हैं। पूर्ण बहुमत द्वारा गुम बैठकें हो सकती हैं।

एक तक कमेटी रिपोर्ट न दे, वित्तों पर चेम्बर आफ डिपुटीज़ में विचार नहीं होता। प्रेसीडेंट वीटो नहीं कर सकता किन्तु ऐसा कभी या कल्प ही नहीं किया गया। चेम्बर की २० कमेटीयों होती हैं। प्रत्येक के ४४ सदस्य होते हैं।

इंग्लैण्ड में कामगार मजदूरी को कानूनन तथा वास्तविक दोनों रूप में बज़द पर निबंधन प्राप्त है।

फ्रांस में चेम्बर को केवल वास्तव में, कानूनन नहीं।

संयुक्त राज्य में हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव को यह निबंधन न कानूनन और नाही वास्तव में प्राप्त है।

फ्रांस में सचेतक हस्तक्षिप्त नहीं होते। सदस्यों को सारी<sup>१०</sup> में कोई यह बताना नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना है, और किन्तु और मत देना है।

: २१ :

## घेर्ज़ियम

निर्वाण मजदूर हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव

मताधिकार : प्रत्येक २१ वर्ष की आयु और ५ साल की निराल योग्यता।

युनाय निर्वाण क्षेत्र का निर्वाणी होया बाहिरि जिनो को दो-तिहारी के बहुमत से एक मत दिया गया है। मत दाताओं की सभी निरमानुसार रहती है ( जेना कि आदिस्था में है ) अनुयायिक मति-निक्षिप्त। मत-दान अनिवार्य है।

१०—सादी मजदूर के समीप वाले कमरों को करते हैं जहाँ सदस्य बैठक करता है।

संख्या ४०,००० निवासियों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। २५ वर्ष की आयु आवश्यक है।

योग्यताएँ बेकिंगम का नागरिक या निवासी हो या उसे पूरी नागरिकता प्रदान की जा चुकी हो।

सदस्यों की भुविचार्यें जब तक कोई अपराध करते समय न पकड़ा जावे छेद नहीं हो सकती। यदि मजबूरी में करे तो सदस्यों पर से अभियोगों में मुक्त कर दिया जाता है।

मत्ता १९,००० फ़ाउंड वार्षिक मत्ता। मार्ग-भ्रम्य इसके अतिरिक्त रिटायर्ड होने पर देने के लिये कोष स्थापित किया जा सकता है।

सदस्यों की आजी सख्या प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाती है।

प्रत्येक असमर्थ पुरुष तथा बच्चेवाले विधुर को जो ५ फ़ाउंड का हाउस टेक्स देते हैं यदि वे १५ वर्ष की आयु के हैं एक अतिरिक्त मत दिया जाता है। इसी प्रकार उन सबों को भी जो २५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी वार्षिक आयदाद २००० फ़ाउंड के मूल्य की है अथवा जो भूमि से इतनी ही आय कमाते हैं। अथवा जिनका नाम पब्लिक डेट (ब्लूज) रजिस्टर में है एक अतिरिक्त मत दिया जाता है। जिनका इतना धन सेविंग बैंक में जमा है कि १०० फ़ाउंड व्याज मिलती हो, उन्हें भी अतिरिक्त मत प्राप्त है। तीसरा मत उन सबों को प्राप्त है जो प्रेसुएड हो, या माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके हो, या शिक्षा जैसे कार्य में लगे हों—पर तीन से अधिक मत नहीं होते। (यह सूचना सुबू मिस्सन के ग्रन्थ से ली गई है जो १८९८ ई तक ही है।)

अभिवेशन—नवम्बर में प्रति वर्ष द्वितीय मंगलवार को प्रारम्भ होकर कम से कम ४० दिन चलते हैं।

स्पर्धवापिका सभा का अभिवेशन जुला होता है किन्तु यदि प्रेसीडेन्ट या बहुमत भाई तो गुप्त हो सकता है।

सदस्यों को सरकारी सभा में जाने पर स्थान रिक्त कर देना होता है, किन्तु हुजरा चुनाव एक संकलन है। वाइस-प्रेसीडेन्ट तथा प्रेसीडेन्ट का चुनाव प्रत्येक अभिवेशन में प्रत्येक मजबूत स्वयं करता है।

यदि मत समान आँवें, तो मौनें अस्वीकृत समझी जाती है। बाव

करने के लिये कोरम मंचम का बहुमत है। बोलकर मत दिये जाते हैं या उठे रहकर तथा बैठे रहकर।

संविधानों की प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, मन्त्र को नहीं।

: २२ :

## डैनमार्क

मिथला मधन फास्फस्टीन।

सब नर-नारी को देश के निवासी हैं और भिन्ना रहने का स्थान है मठराता है यदि (१) वे किसी बुरे अपराध में दृष्टि होकर उस समय सजा न भुगत रहे हों, अथवा (२) उन्हें जन-संगठनों से आधिक सहायता आपत्ति काल में मिली हो और उन्होंने भ्रष्ट बुझावा न हो, अथवा (३) भिन्नी जाबराद समाप्त हो गई है और किन्हीं विधानिका प्रोत्ति कर दिया गया हो।

सदस्यों की संख्या १२ से अधिक न होगी।

आनुगतिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सकता है।

अवधि ४ वर्ष।

बैठन मिश्रता है।

मन्त्र में वक्तव्य कानूनी माने जाते हैं।

प्रत्येक मन्त्र अपना जेवर में स्वयं भुगतता है।

मन्त्र की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित होता है किन्तु जनता गुप्त रहने को कह सकती है।

सम्मिश्रित बैठक प्रत्येक जेवर के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों।

रीजस्त्राग राजधानी ( कोपेन हेगन ) में बैठती है।

जुने हुए सरकारी अफसरों की किसी की अनुमति नहीं लेनी होगी। विशेष अवस्थाओं में, बैठन मोगी पक्षों को प्रत्येक करने वाले सदस्य कानून बूझी बार में फिर जुने जा सकते हैं।

## दुनिया के विधान

बिना आधे सदस्यों की उपस्थिति के कोई मत नहीं लि  
सकता।

२३ :

## इटली

निबला मन्त्र सैम्बर आफ डिपुटीज़।

१९१५ सदस्य।

पुन मतदान। प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं।

सम्पूर्ण पार्टी सूची पर मत दिया जाता है।

बिना पार्टी को सबसे अधिक मत मिले वह मन्त्र की हो-विहार  
सोडो पर अधिकार कर लेता है। मत दाता बिना पार्टी को चुनना चाहते  
हैं उसके बिना पर लाइन कर देते हैं। (कासिस्तों का बिल्ड तिनके तथा  
कुस्वाही माचीन रोमन बिन्द है और पपुवारी का कास तथा लखवार)  
अन्व पटिपो को आरथ में अनुमान से सौटें मिल जाती हैं।  
अबकि ५ वर्ष। प्रधान मंत्री मन्त्र को कमी मी मत करने का  
निर्णय कर सकता है।

(बार में सुनाई १९११ ई०) कहा जाता है कि प्रधान मंत्री  
केवल मतदाताओं के पास एक सम्पूर्ण सूची विचारार्थ भेज सकता है।  
सरकार को मन्त्रबानिका समा में स्वयं काफी आर्थिकता की शक्ति  
है जो है।

कानून की केवल मोटी कपरेला बनाई जाती है—सरकार आधी  
वेगों तथा डिफिनों से उ है मर देती है—कमी कमी यह अधिकार  
नीचे के कर्मचारियों को दे दिया जाता है (बारथ में इन डिफिनों  
को बनाने में परिश्रम तथा लागू करने में कठिनाइयाँ आर्थिकजनक हैं।  
आर्थिक बिल प्रथम बार में निबले मन्त्र में उपस्थित किये जाते  
हैं सीनेट मान जाती है—न माने तो और मये सीनेटर नियुक्त कर दिये  
जाते हैं।  
स्वीकर निष्पक्ष होता है।

कमेडिया का चुनाव तथा प्रश्न करने का हक सांख्यीसी छत्र का है।

सम्बर II कमेडियों में विभाजित है। (प्रत्येक २ माह के पराम्प फिरे से बनती है) इनमें से प्रत्येक बनने वाली कमेटी में एक सदस्य भेजा जाता है।

: २४ :

## मैक्सिको

सिबिला भयन हाउस आफ रिपब्लिकेनिस।

अवधि: २ वर्ष।

छोटी की संख्या प्रत्येक ६ • • या २०० • से अधिक के विमान के पीछे एक प्रतिनिधि। किन्तु प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य के साथ उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए स्थानापन्न (substitute) भी चुना जाता है।

चुनाव प्रणाली।

योग्यताएँ १—नागरिक हो २—आयु पचीस वर्ष की हो; ३—राज्यों का निवासी हो या चुनाव के छ माह पूर्व निवासी बन गया हो; ४—चुनाव से ६ दिन पहिले एक सक्रिय सैनिक सेवा में न रहा हो;

५—किन्ना ६ दिन पहले स्थापन दिए शासन विभाग का सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अथवा राज्य का गवर्नर अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट (राजमन्त्री) अथवा राज्य का न्यायाधीश नहीं हो सकता।

अयोग्यताएँ नार्मिक मतों के पक्षी अथवा पदाधिकारी अयोग्य समझे जाते हैं।

कोरम बहुमत।

अधिकार

१—इबार और करों के सम्बन्ध के बिल केवल निम्नले मन्त्र में प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

२—साधारण कानून को निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्तावित

कर सकता है। (अ) प्रेसीडेन्ट द्वारा (ब) किसी मन्त्र द्वारा, (ग) राज्य की व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा।

टिप्पणी : वे बिल जो (अ) और (ग) और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं उन पर कमेटीयों विचार करती हैं।

जिन बिलों को मन्त्र स्वयं प्रस्तावित करते हैं उन पर मन्त्रों की कार्यवाही के नियमों के अनुसार कार्य होता है।

१—प्रेसीडेन्ट का बीटो —(१) वे बिल जो प्रेसीडेन्ट द्वारा दस दिन में वापिस नहीं भेजे जाते, पास हो गये समझे जाते हैं। (२) यदि प्रेसीडेन्ट विरोध करे तो वह उसे मन्त्र के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है जिसमें वह प्रस्तावित किया गया था। यदि वह मन्त्र दो-तिहाई के बहुमत से उसे फिर पास करे तो वह दूसरे मन्त्र के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा मन्त्र भी उसे दो-तिहाई के मत से स्वीकृत करे तो कानून पास समझा जाता है।

४—सीनेट द्वारा बीटो वह बिल जिसको सीनेट एक दम अस्वीकृत कर देती है उसकी मन्त्र में उसके समूहों सहित दोबारा जांच होती है और यदि मन्त्र फिर स्वीकृति दे तो वह प्रेसीडेन्ट के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है।

कॉमेस के अधिकार —ये अधिकार विस्तृत रूप से ७१ से ७७ पाठ्यक्रम में १२ शीर्षकों के अन्तर्गत गिनाए गए हैं।

१—नये राज्यों की शामिल होने की सहमति देना।

२—८००००० वर्ग मील के क्षेत्रफल में राज्यों को स्थापित करना।

३—वर्तमान राज्यों में से नये राज्य बनाना यदि जनमत इसके अनुकूल हो। ऐसे राज्यों की जनसंख्या कम से कम १२००० होनी चाहिये और इस विषय में राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं तथा सभ के मन्त्र के प्रेसीडेन्ट की भी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। नये राज्यों में स्वयं अपना मार सम्हालने की बिन्ता होनी चाहिये। इस प्रकार का निर्णय संघ के दोनों मन्त्रों को दो-तिहाई के बहुमत से तथा राज्य की व्यवस्थापिका सभा को साधारण बहुमत से प्राप्त होना चाहिये। किन्तु यदि सम्बन्धित राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमत न हो तो राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं के दो तिहाई बहुमत की सहमति आवश्यक है।



४—राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना ।

५—राजधानियों को परिवर्तित करना ।

६—कानून सम्बन्धी अधिकार । यह अधिकार उन संघीय प्रदेशों के सम्बन्ध में प्राप्त हैं जिन पर प्रेसीडेन्ट द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करते हैं । यह गवर्नर प्रेसीडेन्ट द्वारा हटाये जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों और प्रथम बार मुख्यमंत्रियों पर विचार करने वाले न्यायाधीशों की कमीशन मत आलाह्वर नियुक्त करती है । अद्वैत कनरल सीने प्रेसीडेन्ट के मातहत होता है ।

७—बजट के लिए आवश्यक कर लगा सकता है ।

८—उद्योगों से सम्बन्धित और श्रम तथा विदेशी व्यापार के विषयों पर अधिकार रखता है ।

९—सड़कर सम्बन्धी कानून बनाता है ।

१०—खानों, व्यापार, उद्योग उद्योगों के विषय में कानून बनाता है और मोट प्रचारित करने वाला एक बैंक स्थापित करता है ।

११—विदेशी मालों के सम्बन्ध में अधिकार है ।

१२—मुद्रा की घोषणा करता है ।

१३—राज्य के जहाजों के पकड़ने के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१४—जहाजरानी के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१५—जल और स्वच्छ सेवा के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१६—नेशनल गार्ड के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१७—नागरिकता विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने, उपनिवेश प्रवास, प्रवेश अनुरोध के सम्बन्ध में कानून बनाता है । अनुरोध परिषद प्रेसीडेन्ट के मातहत काम करती है । इच्छा कोई ऐक्सेटरी गरी होता, दण्ड्यता सम्बन्धी अधिकारी को विधायिका प्रदा है । अनुरोध परिषद द्वारा बनाने गये नियम कमीशन द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं ।

१८—सम्प्रेष के आम साधनों डाक, रेलवे, डाकघरों तारघरों और संघीय मुद्रा नुयों के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१९—मुद्रा, मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२०—विना मुद्रा मुद्रा मूल्य पर अधिकार तथा उद्योग बेचने के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२१—वैभागिक और वैधानिक कर्मचारियों पर अधिकार तथा नियन्त्रण ।

२२—धर्म के विरुद्ध अपराध और उनके लिए दण्ड ।

२३—संघीय विधियों में समा प्रदान ।

२४—खान्तरिक शासन तथा दण्ड के नियम कॉमेस में अनिवार्य उपस्थिति । उपस्थित सदस्यों को सलाह के सिद्धे दण्ड ।

२५—कोष पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कानून प्रस्तावित करना ।

२६—स्वाधीनताओं को नियुक्त करने के लिए मत देना ।

२७—स्वाधीनताओं के त्याग पत्र स्वीकार करना ।

२८—जंगल, कृषि सम्बन्धी स्कूल स्थापित करना और अनामक-पर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ स्थापित करना । इनके द्वारा प्रदान की हुई उपाधियों नियमित मानी जायगी ।

२९—अन्तरक्रांतीन या स्थानापन्न प्रेसीडेन्ट चुनना ।

३०—प्रेसीडेन्ट का त्यागपत्र स्वीकार करना ।

३१—विचार की जाँच पकड़ाना करना ।

३२—उपरोक्त अधिकारों के उचित उपयोग के लिये कानून बनाना ।

१ २५ ३

## जापान

नोट—यह एक विधान के अतिरिक्त बड़े राजनीतिज्ञों की परिषद है—इसमें वे व्यक्ति हैं जिन्होंने १८९८ ई० की नई व्यवस्था कायम की थी । यह परिषद सम्राट और मिनीकाठमिसल के नीचे है—इसने देश की बहुत सेवा की है—परन्तु इनके विचार शासन विधान से मेल नहीं खाते । सम्राट पर इनका बहुत प्रभाव है । इसके कुछ दो या तीन सदस्य अधिकृत<sup>१८</sup> हैं और इसका शीम ही अन्त हो जायगा ।

३८—इसका अन्तिम सदस्य कई वर्ष हुए स्वर्गवासी हो गया है इस प्रकार इस संस्था का अन्त हो गया था ।

**हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स—**निचला मकन । १९२० ई० का चुनाव कानून—पुरुष मतदाता २८,७०,००० अर्थात् प्रत्येक १००० निवातियों के पीछे १०९ मतदाता हैं जब कि पहले प्रति इंचर के पीछे केवल २८ थे ।

**४६४ सदस्य—**१५ वर्ष की आयु—हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के लिए एक सकते हैं । जबकि पुरुष मतदाता के विषय में विचार हो रहा है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत १९० लाख मतदाता होंगे ।

प्रेसीडेंट और वाइसप्रेसीडेंटों की नियुक्ति सम्राट उन तीन सम्मेलन बाटों में से करता है जिन्हे प्रत्येक मकन प्रतिपक्ष के लिए प्रस्तावित करते हैं । मत्ता ५००० डेन । वाइस प्रेसीडेंट को १ ०० डेन मिलते हैं । सदस्यों को ९००० डेन और मार्ग मत्ता किन्तु ओ सदस्य सरकारी नौकरी में होते हैं उन्हें यह मत्ता नहीं मिलता ।

सम्राट हाउस हाउस पास किये गए कानूनों को बीजे नहीं कर सकता, क्योंकि शासन विधान उसे यह अधिकार देता है । रिक्तों को सरकार वा दोनो मकनों में से कोई प्रस्तावित कर सकते हैं । दोनो मकनों को बजट के अतिरिक्त अन्य विषयों में समान अधिकार प्राप्त हैं । बजट पहले हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश किया जाता है ।

बजट का अधिवेशन प्रतिकर्ष होता है । अधिवेशन तीन महीने चलता है राजशा से अधिवेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है । सम्राट विशेष अधिवेशन बुला सकता है । बैठकों की कार्यवाही कुछेक काम होती है पर सरकार की माँग पर अवकाश मकन के प्रस्ताव पर कुछ बैठकें हो सकती हैं । मकन का कार्य भी सदस्य मकन में दिये गये मापदण्ड अवकाश मत के लिए बाहर उत्तरदाई नहीं उद्घारण जा सकता ।

किन्तु जनता के सामने प्रकट किये गए विचारों के लिए यह कानून उत्तरदायी है । समस्त राजप्रत्यक्ष अपराधों में सदस्यों को मारचतार नहीं किया जा सकता । किन्तु बड़े अपराधों में अवकाश आन्तरिक अव्यवस्था वा विदेश में गलत के मामलों में झूठ मारी है । मकन की अनुमति से अधिपति लगाया जा सकता है ।

: २६ :

## सोवियत रूस

प्राम्तीय कॉम्रेस या गृपरमिया में मगर सोवियतों के २००० के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं और देहाती जिला कॉम्रेस में १०,००० निवासीयों के पीछे १ प्रतिनिधि होता है। अधिकतम संख्या १०० है किन्तु प्राम्तीय कॉम्रेस के दुरन्त पहले ही यदि काठन्दी कॉम्रेस हो चुको हो तो प्राम्तीय कॉम्रेस के लिये चुनाव देहाती सोवियतों के स्थान पर काठन्दी कॉम्रेस करती है।

काठन्दी या गृज्द कॉम्रेस में ग्राम सोवियतों के प्रति १००० निवासियों के पीछे १ के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं। अधिकतम संख्या १०० होती है।

देहाती या बोत्सत कॉम्रेस में ग्राम सोवियतों के १० सोवियतों सदस्यों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होता है।

टिप्पणी (I) काठन्दी कॉम्रेस में उन मगर सोवियतों के प्रति नियम होते हैं जिनकी जनसंख्या १०० से कम है।

(II) जबकि ग्राम सोवियतें, जिनकी जनसंख्या १००० से कम होती है, भारत में मिलती हैं और काठन्दी कॉम्रेस के लिए बैलगेद चुनती हैं। वे ग्राम सोवियतें, जिनकी सदस्य संख्या १० से कम है देहाती या बोत्सत कॉम्रेस को प्रतिनिधि भेजते हैं।

सोवियत कॉम्रेस या तो स्वयं एकत्रिकमूडिक कमेटी चुनाती हैं अथवा ऐसी स्थानीय सोवियतों की मींग पर चुनाई जाती है जो जनता के कम से कम एक-तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आस रशियन कॉम्रेस के मर्बे अधिवेशन के निरन्तरतुवार समस्त कॉम्रेस वर्ग में एक बार चुनाई जाती है—आवरयकता के अनुसार विशेष अधिवेशन चुनाये जा सकते हैं।

मेसीडियम—विशेष अधिवेशनों और नये चुनावों के लिए आह्वान दे सकती है।

प्रत्येक कॉम्रेल स्वयं अपनी एकत्रीक्यूटिब कमेटी चुनती है। प्रादे-  
शिक और प्रांतीय कॉम्रेल की एकत्रीक्यूटिब कमेटियों की अधिकतम  
संख्या २५ हो सकती है। देशी कॉम्रेल में वह संख्या १० होती है और  
काठमंडी या मुख्य कॉम्रेल में शहरों की वह अधिकतम संख्या बीस तक  
हो सकती है।

एकत्रीक्यूटिब कमेटी उस कॉम्रेल के प्रति उत्तरदायी होती है जो  
उसे चुनती है। अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के अन्दर कॉम्रेल  
सर्वाथ सत्ता होती है। बैठकों के अवकाश-काल में यह सत्ता एकत्री-  
क्यूटिब कमेटी के पास रहती है। आम खोजियों की भी अपनी  
एकत्रीक्यूटिब कमेटियां होती हैं। इनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक  
पांच होती है।

---

: ४ :

## ऊँचा मवन

१

### आयरलैण्ड

#### ऊँचा मवन सीमद् आयरलैण्ड

यह उदर्यों की नामावलिओं से निर्मित किया जाता है ( उदर्यों की न्यूनतम आयु १५ वर्ष) इन नामावलिओं में निर्वाचित उदर्यों की संख्या के ठिगुने नाम रहते हैं। इनमें दो-तिहाई डेल आयरलैण्ड द्वारा और एक-तिहाई चीनर आयरलैण्ड द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं। इन नामावलिओं से १५ वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु वाले मतदाता आयुपात्रिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं।

अवधि १२ वर्ष।

वे मिल जो चीमद् आयरलैण्ड द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आयरलैण्ड द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (घ) परिवर्तित किये जा सकते हैं जब कि वे डेल आयरलैण्ड द्वारा प्रस्तावित समझे जाते हैं; (ग) धरसोदृत किये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे उठी अधिवेशन में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किन्तु डेल आयरलैण्ड अपनी इच्छा से उन पर पुनर्विचार कर सकती है।

जुलाई १९३१ से डेल आयरलैण्ड द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिये आवश्यक विधायक काल को १८ महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।

प्रत्येक कॉंग्रेस स्वयं अपनी एकजीक्यूटिव कमेटी चुनती है। प्रादे-  
शिक और प्रांतीय कॉंग्रेस की एकजीक्यूटिव कमेटियों की अधिकतम  
संख्या २५ हो सकती है; वेदाती कॉंग्रेस में यह संख्या १ होती है और  
काउन्टी या यूजल कॉंग्रेस में सदस्यों की यह अधिकतम संख्या बीस तक  
हो सकती है।

एकजीक्यूटिव कमेटी उस कॉंग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है जो  
उसे चुनती है। अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के सम्मर कॉंग्रेस  
सर्वोच्च सत्ता होती है। बैठकों के अवकाश-काल में यह सत्ता एकजी-  
क्यूटिव कमेटी के पास रहती है। ग्राम सोवियतों की भी अपनी  
एकजीक्यूटिव कमेटियाँ होती हैं। इनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक  
पाँच होती है।

---

: ४ :

## ऊँचा मवन

१ :

### आयरलैंड

#### ऊँचा मवन सीनर आयरलैंड

यह सदस्यों की नामावक्तियों से निर्मित किया जाता है (सदस्यों की न्यूनतम आयु १५ वर्ष) हम नामावक्तियों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के सिगने नाम रहते हैं। इनमें दो तिहाई डेल आयरलैंड द्वारा और एक तिहाई सीनर आयरलैंड द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इन नामावक्तियों से २५ वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु वाले मतदाता आयुवातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं।

आवधि १२ वर्ष।

वे निम्न को सीनर आयरलैंड द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आयरलैंड द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (घ) परिवर्तित किये जा सकते हैं जब कि वे डेल आयरलैंड द्वारा प्रस्तावित समझे जाते हैं; (ग) अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे ठीकी अभिवेदन में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किन्तु डेल आयरलैंड अपनी इच्छा से ठम पर पुनर्विचार कर सकती है।

जुलाई १९९९ से डेल आयरलैंड द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिये आवश्यक दिनांक काल को १८ महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।



राजत्व—आर्थिक विज्ञान के अन्तर्गत से अस्वीकृत होकर चीन के पाठ सिद्धांत के लिए जाते हैं। इनके अन्तर्गत अस्वीकृत कर सकती है।

कुछ अन्य बातें—कोई भी स्वीकृत विज्ञान के अन्तर्गत से बहुत अधिक चीन के साधारण बहुमत की शक्ति मांग पर ६० दिन के लिये मंजूर किया जा सकता है। ६ दिन की अवधि के पूर्व यदि चीन के अन्तर्गत से बहुत अधिक या मतवालाओं का ५५ भाग मांग करे तो उसे अन्तर्गत से हटाने में जा सकता है। आर्थिक विज्ञान पर यह बात लागू नहीं होती।

दोनों मकान मिटाकर मातहत व्यवस्थापिका समारोह (पारा ४४) स्थापित कर सकते हैं और पेशेवर काठस्थलों को कानूनी अधिकार प्रदान कर (४५ पारा) के स्थापित कर सकते हैं।

२ :

## कैनेडा

### चीन

नामकृत होती है। अन्तर्गत से विज्ञान स्थापनों की पूर्ति गवर्नर-जनरल करता है।

संख्या ७९ अन्तर्गत तीन विभागों में बँटी रहती है (१) ओन्टारियो—९४ अन्तर्गत; (२) क्यूबेक—९४ अन्तर्गत; (३) लॉ के समीप वाले प्रांत—९४। इसके अतिरिक्त ९९ अन्तर्गत मार्च मूलविक के तथा अन्तर्गत ९९ नोवा स्कॉटिया के होते हैं।

कुल अन्तर्गत संख्या—३६।

इसके अतिरिक्त ६ या तीन अन्तर्गत समान रूप से नामकृत करने जा सकते हैं।

लॉ के अन्तर्गत के लिये नामकृत कर सकता है। अधिकांश के दो अधिवेशनों में अनुपस्थित सीट को रिक्त कर देती है। विधानसभा,

बन-बस की आदायगी का न होना, तथा बेरुद्रोह—यह भी तीव्र को रिक घोषित किये जाने के लिये काफ़ी है।

**अमेरिखारों की योग्यताएँ**

( क ) आयु ३० वर्ष।

( ल ) मूलि अथवा अन्य सम्पत्ति ( बचक के अलावा भी ) वास्तव में अथवा व्यक्तिगत रूप में ४० • पीएड हो।

( ग ) जिस प्रांत से चुना जाय उसका निवासी हो। क्यूबेक में उसका निर्वाचन-क्षेत्र में निवास आवश्यक है।

**कोरम १३—**

रौबर गवर्नर जनरल नियुक्त करता है।

समान मत होने पर प्रस्ताव अथवा बिल गिर जाता है।

३ :

## वर्द्धिण अफ्रीका

**सीनेट**

( क ) ८ सदस्यों को गवर्नर-जनरल १० वर्ष की अवधि के लिये नामाङ्क करता है।

( ल ) ८ सदस्यों को प्रत्येक प्रांतीय व्यवस्थापिका समा और असेम्बली में प्रांत के सदस्य मिलकर चुनते हैं।

( ल ) में चुनाव आनुनातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है।

**योग्यताएँ**

आयु तीव्र वय। असेम्बली की सदस्यता के लिये प्रांतों द्वारा निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। सय में ३ वर्ष स रहता हो।

पोरपीय प्रजा होना चाहिए। यदि सीनेट के लिये चुना जाय तो कम से कम यूनिपन में उसकी ५ • पीएड की कीमत को अधन सम्पत्ति होनी चाहिए।

अवधि — ६ वर्ष ( १ प्रति तीन वर्ष बाद रिहायश हो जाते हैं ) ।  
सदस्य संख्या ३४ ।

भत्ता — २००० फ्राँक या ३०० डालर भत्ता दिया जाता है ।

अधिकार (१) राजस्व के अतिरिक्त अन्य नियमों में कानूनों का प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने में इसके अधिकार समान हैं । (२) यह चेम्बर आफ डिपुटीज़ का विरोध करने के लिये कानूनों को कमेटीयों के सुपुर्द कर देता है और वे वहीं पड़े रहते हैं । केवल चेम्बर आफ डिपुटीज़ के ओर देने पर उन पर फिर विचार होता है । (३) सीनेट का यह अधिकार है कि बजट के मदों में कमी कर दे या किसी मद को रद्द कर दे किन्तु यदि चेम्बर आफ डिपुटीज़ सहमति न दे तो यह ठीकी की बात मान लेता है । (४) किना होनों मन्त्रियों की अनुमति के बुद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी ढंग पर केवल अकेले समी बैठक कर सकती है जब इस म्यामात्रय की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेन्ट द्वारा चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग करने में सीनेट की अनुमति आवश्यक है ।

एक सीनेट का सदस्य राज्य का काउन्सिलर नहीं हो सकता और न वह प्रीफेक्ट आफ पुलिस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रीफेक्ट ही हो सकता है ।

सब मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली संस्था है । चेम्बर आफ डिपुटीज़ में सदस्य सीनेट मन्त्रों में जाते हैं और फिर प्रेसीडेन्ट पर पर । ( ४ इस प्रकार के उदाहरण हैं ) ।

सीनेट एक म्यामात्रय मी है । यह प्रेसीडेन्ट अथवा मंत्रियों के विरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

मंत्र — यद्यपि प्रेसीडेन्ट सीनेट की अनुमति से चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग कर सकता है किन्तु मंत्र करने की आज्ञा पर एक मंत्री के मी हस्ताक्षर आवश्यक होंगे । इस कारण ३ वर्ष की अवधि में केवल एक बार चेम्बर आफ डिपुटीज़ ४ वर्ष के पूर्व मंत्र किया गया है ।

## न्यूजीलैण्ड

### काङ्ग्रेसिस्त

सरकार द्वारा नामज़र । अब सदस्य चुने जाते हैं ।  
संख्या ( १४+१२—कोई सीमा नहीं ) अब ४० सदस्य हैं ।  
४ वार्षिक प्रतिनिधि,  
१ वार्षिक प्रतिनिधि नामज़द होते हैं ।

अबधि ७ वर्ष ।

( १९२०—बीकन से )

केटन २०० पोस्ट वार्षिक ।

परिवर्तन राज्य के अतिरिक्त अन्य दिनों कांग्रेसी कृत कर  
सकती है ।

राजस्व राज्य तकभी कोई शक्ति नहीं ।

गति अवरोध

होनों की सम्मिलित बैठक होती है और बोट लिए जाते हैं । यदि  
विष स्वीकृत न हो तो दोनों मकनों को मंग कर चुनाव होते हैं ।

७

## जर्मनी

### रीज़रूट ऊँचा मकन

प्रत्येक राज्य प्रति दस लाख की जन संख्या के पीछे १ प्रतिनिधि  
युनायट से सदस्य मेकते हैं । प्रत्येक राज्य का कम से कम एक  
व शक्ति है । यदि अतिरिक्त जन संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले  
से अधिक हो तो उसे १० लाख मानकर एक प्रतिनिधि उन  
के लिये दिया जाता है । कोई राज्य अधिक से अधिक पूरी  
संख्या के २/५ सदस्य मेक सकता है ।

अवधि — ६ बर्य ( १ प्रति तीन बर्य बाद रिहाय हो जाते हैं ) ।  
सदस्य संख्या १०४ ।

मत्ता — २७०० फ़ॉक का १०० बालर मत्ता दिया जाता है ।

अधिकार (१) राजस्व के अतिरिक्त अन्य विषयों में कानूनों को प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने में इसके अधिकार समान हैं । (२) यह चेम्बर आफ डिपुटीज़ का विरोध करने के सिवे कानूनों को कमेटियों के सुपुर् कर देता है और वे यहीं पड़े रहते हैं । केवल चेम्बर आफ डिपुटीज़ के ओर से ही उन पर फिर विचार होता है । (३) सीनेट को यह अधिकार है कि बजट के मदों में कमी कर दे वा किसी मद को रद्द कर दे किंतु यदि चेम्बर आफ डिपुटीज़ सहमति न दे तो यह ठीकी की बात मान लेता है । (४) बिना दोनों मदनो की अनुमति के कुछ भी घोषणा नहीं की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी रंग पर केवल अकेले समी बैठक कर सकती है जब इस स्वायत्तत्व की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेन्ट द्वारा चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग करने में सीनेट की अनुमति आवश्यक है ।

एक सीनेट का सदस्य राज्य का काठस्थितर नहीं हो सकता और न वह प्रीजेन्ट आफ पुसिठ के अतिरिक्त अन्य कीर्ति प्रीजेन्ट हो हो सकता है ।

सब मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली संस्था है । चेम्बर आफ डिपुटीज़ में सदस्य सीनेट भवन में जाते हैं और फिर प्रेसीडेन्ट वह पर । ( ४ इस प्रकार क उदाहरण है ) ।

सीनेट एक न्यायालय भी है । यह प्रेसीडेन्ट अथवा मंत्रियों के निरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के निरुद्ध अपराधों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

भंग — यद्यपि प्रेसीडेन्ट सीनेट की अनुमति से चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग कर सकता है किंतु भंग करने की आज्ञा पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक होंगे । इस कारण १० बर्य की अवधि में केवल एक बार चेम्बर आफ डिपुटीज़ ४ बर्य के पूर्व भंग किया गया है ।

१ ६

## न्यूज़ीलैण्ड

### कार्गिलिस्त

सरकार द्वारा नामज़द । अब सदस्य चुने जाय हैं ।

संख्या ( ३४+१२—कोई सीमा नहीं ) अब ४० सदस्य हैं ।

४ धार्मिक प्रतिनिधि,

३ मारिच प्रतिनिधि नामज़द होते हैं ।

अवधि ७ वर्ष ।

( १९२०—जीवन से )

वेतन २०० पौण्ड वार्षिक ।

एम्बेडमेंट राज्य के प्रतिष्ठित अंग्य दिनों कोमलसी कृत कर सकती है ।

राज्य राज्य कर्षी कोई शक्ति नहीं ।

गति अवरोध

बोनों की सम्मिलित बैठक होती है और बोट लिए जाते हैं । यदि विष स्वीकृत न हो तो दोनों मन्त्रों को मंग कर पुनराव होत है ।

७

## जर्मनी

### रीखस्ट्राट काँधा मन्त्र

प्रत्येक राज्य प्रति दस साल की कम संख्या के पीछे १ प्रतिनिधि का अनुपात से सदस्य मिलते हैं । प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होता है । यदि प्रतिष्ठित कम संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य से अधिक हो तो उसे १० साल मानकर एक प्रतिनिधि उस संख्या के बिये लिया जाता है । और राज्य अधिक से अधिक पूरी कक्षा संख्या के २५ सदस्य में न बढ़ता है ।

रीजस्ट्रार की बैठक उसके सदस्यों के रिक्त स्थानों पर सदस्यों की मांग पर बुलाई जाती है। इसकी कमेटियों का समायोजन कोई सरकारी सदस्य करता है।

अभिज्ञों का यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि वे रीजस्ट्रार में मापदंड दें।

नागरिकता के समय कभी भी रीज के सदस्यों को उनके विचार सुनने का अधिकार है।

प्रतिभा की अनसंख्या यद्यपि कर्मन अनसंख्या का है किन्तु रीजस्ट्रार में उसे केवल है प्रतिनिधित्व प्राप्त है (सदस्य तथा ११) इस प्रकार इसके अधिकार काफी कम कर दिये गये हैं। कमेटियों में जिसमें उन्हीं के सदस्य होते हैं, किसी राज्य की एक से अधिक मत नहीं दिया जाता।

### गति अवरोध

रीजस्ट्रार किसी भी कानून का विरोध कर सकती है। ऐसी हालत में सरकार उन्हें रीजस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करती है। यदि वह भी अचलमत हो तो प्रेसीडेन्ट अन्तः से निर्णय को अपील कर सकता है। यदि प्रेसीडेन्ट ऐसा न करे तो कानून लागू नहीं होता। यदि रीजस्ट्रार का निर्णय रीजस्ट्रार के विरुद्ध हो-सिद्ध के बहुमत से ही तो प्रेसीडेन्ट का तो कानून को लागू कर देता है अथवा अन्तः से निर्णय करने की अपील कर सकता है किन्तु रीजस्ट्रार का निर्णय तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि बहुमत ने मत देने में मांग न किया हो।

### भग करण

कर्मन प्रेसीडेन्ट वास्तविक के परामर्श पर रीजस्ट्रार को मंग कर सकता है किन्तु वह ऐसा केवल एक बार ही कर सकता है। वह रीजस्ट्रार को स्थापित नहीं कर सकता और न उसके अधिकारों को हट कर सकता है, केवल भग कर सकता है। इसीलिए वे कैबीनेट के परामर्श पर सहायक पार्लियामेन्ट को स्थापित कर सकता है। सहायक उन्हीं भग अथवा विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

## स्विटज़र लैण्ड

ऊँचा मधन काठमिस्त आप स्टेट

प्रत्येक कैप्टन से दो सदस्य और प्रत्येक कैप्टन से एक सदस्य चुना जाता है। सदस्यों में ८ प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त होते हैं। चुनाव का ढग, सदस्यों का वेतन तथा कार्यकाल का निर्णय कैप्टनों पर निर्भर है। कार्य काल एक वर्ष से चार वर्ष तक है।

चार कैप्टन सदस्यों को व्यवस्थापिका समझा जाता चुनने हैं और शेष जनता के सीधे मतदान द्वारा। इसकी सत्ता कम है किन्तु वह कानूनों पर अधिक उदारता से विचार करती है।

इसके अधिकार नेशनल काउन्सिल या निचले मन्त्र के समान हैं। केवल काउन्सिल व्यवस्थापिका समा के विरोध अपिबेधन चुका सकती है किन्तु किसी मन्त्र को न तो मंत्र कर सकती है और न अपि बेधन ही बन्द कर सकती है।

विचला मधन चैरमैन और बाइस चैरमैन चुने हुए होते हैं। लगातार कोई चैरमैन नहीं हो सकता। यदि मत बराबर हो तो उसका कार्टिंग मत हाजि है।

## सोवियत रूस

ऐक्रीक्यूटिब कमेटी उन सोवियतों के प्रति जा उन्हें चुनती है ठग हावी होती है। ऐक्रीक्यूटिब कमेटी या तो सोवियतों के बैठक स्वयं चुनती है या आधे सदस्यों की मांग पर चुना सकती है। यह बैठक नगरों में अग्रा में एक बार और देहातों में अग्रा में दो बार होती है।



**योग्यताएँ** (क) प्रत्येक नागरिक को किन्हीं आयु १८ वर्ष हो चुकी, है चुनाव के अधिकार प्राप्त है।

(ख) निम्न स्थान के सम्बन्ध में योग्यता आवश्यक नहीं किन्तु अधिकतर उही स्थान के निवासी होते हैं।

(ग) उत्साहक कार्य से जीवन उपार्जन करता हो।

(घ) घरेलू कार्य में लगा हो, किसानों का सेती, उद्योग, व्यापार में व्यवसाय करता हो ( किसान और मजदूर कक्षा ) (ङ) क्लब या खेल सेना का सदस्य हो।

(च) नागरिक हो पर कार्य करने में असमर्थ हो।

(छ) इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति जिन्हें डी अध्याय भाग २ पैराग्राफ २० में निर्दिष्ट किया गया है। इसका सम्बन्ध विदेशी व्यक्तियों से है।

**टिप्पणी** —स्थानीय लोकियते केन्द्रीय सत्ता की स्वीकृति से आयु कम स्थिर कर सकते हैं।

**अयोग्यताएँ** (धारा ३५) (क) जो नाम के लिए वृत्तों से सेवा करते हैं।

(ख) जो पूँजी या उद्योगों से ध्वज की आम्बनी पर जीवन निर्वाह करते हैं।

(ग) व्यक्तिगत व्यापारी ऐजेंट और मजदूर।

(घ) पारसी या शूद्र।

(ङ) विद्युत्ती गुप्त पुलिस या विशेष पुलिस के दस्ते का एजेंट या स्वामी।

(च) शासक काल का सदस्य।

(छ) वे जिन्हें किसी दुरे अपराध में दण्ड मिल चुका है।

प्रारम्भिक या अल्पकालिक काल में इसमें नगर लोकियतों के ५०० मत दाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और मजदूर के २५० निवासियों के पीछे एक डिप्टी होता है। अधिकतम संख्या ३०० हो सकती है।

इन कमिटी की उम्मीद बैठकें नहीं हुई किन्ती का विधान में निर्दिष्ट है क्योंकि प्रत्येक सत्ता स्वयं हाथ में रखना चाहते थे।

**अयोग्यताएँ** गृहनिर्माण मजदूर बोर्डर काल में।

बजट, राजस्व नीति लोकियत के वन अपहरण के आधारभूत

सिद्धांतों की सहायक है—समस्त साधन द्वारा रशियन कमिश्नर अथवा अन्त रशियन सेन्ट्रल ऐक्यूजिस्मेटिक कमेटी को सौंप दिये गए हैं। अन्त रशियन सेन्ट्रल ऐक्यूजिस्मेटिक कमेटी कर्तव्य को निर्धारित करती है। आम्बानी के जरियों के नियम में निर्णय करती है और राज्यों तथा स्थानीय सोवियतों में आप का वितरण करती है। सोवियतों केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लगा सकती है। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से की जाती है।

१०

## स्लावों, कोटों तथा सर्वों का राज्य

### फाउन्डेशन आफ स्टेट

फाउन्डेशन आफ स्टेट एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। इसके आधे न्यायाधीश राजा द्वारा नेशनल असेम्बली द्वारा नामित सदस्यों में से चुने जाते हैं और शेष आधे नेशनल असेम्बली द्वारा राजा के नामित सदस्यों में से चुने जाते हैं।

११

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

### ऊँचा मण्डल सीनेट

प्रत्येक राज्य से हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स की भांति दो सीनेटर चुने जाते हैं। कार्य काल ६ वर्ष। एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष बदलत रहते हैं। अन्तरकालीन रिक्त स्थानों की पूर्ति अस्वार्थ रूप से राज्य की व्यवस्थापिका तथा द्वारा की जाती है।

### सम्मिश्रधारों की योग्यताएँ

आधु तीस वर्ष—कम से कम मो वर्ष की नागरिकता—और निश्चय सम्बन्धी योग्यता।

बाइल प्रेसीडेन्ट सीनेट का समापत्रिष करता है और दोनों पक्षों के समान मत होने पर आपमा निर्णायक मत देता है। जब बाइल प्रेसीडेन्ट प्रेसीडेन्ट का पद संभालता है तो सीनेट स्वयं अपना प्रेसीडेन्ट चुन लेती है। वह अपने अन्य अफसरों का भी चुनाव करती है।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव राज्य की व्यवसायिका मध्याह्नों द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों भूखण्डों का अधिवेशन पहली दिसम्बर को प्रारम्भ होता है। प्रत्येक सदन अनुसूचित सम्बन्धी नियम बनाता है और हो-तिहाई बहुमत की सहमति से किसी सदस्य को निकाल सकता है। प्रत्येक भवन में कोरम के लिये सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन कम संख्या होने पर बैठक आगले दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है।

कोई भी सदन कांग्रेस के अधिवेशन काल में बैठकों को तीन दिन से अधिक स्थगित नहीं कर सकती। कभी कभी बैठकें गुप्त होती हैं।

तुर्नियार्ण और मते — कोई भी सीनेट का सदस्य इसी नये गैर सैनिक व्यक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न किसी ऐसे ही पद ही पर नियुक्त किया जा सकता है जिसका वेतन बढ़ाया गया है। कोई अफसर सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। सीनेट घाय सम्बन्धी विषयों में सहोचन प्रस्तावित कर सकती है जबकि उनसे सहमति प्रकट कर सकती है।

सदस्यों को वेतन मिलता है।

इस पद को प्राप्त करने के लिए लोगों की बहुत इच्छा रहती है क्योंकि अधिक में स्थायित्व है और इसे नियुक्ति तथा संप सम्बन्धी शासन-सत्ता प्राप्त है।

म्याब सम्बन्धी अधिकार — सीनेट को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव कमिशनरों पर विचार करने का अधिकार है। विचार करते समय सदस्यों को राय प्रकट करनी पड़ती है। जब प्रेसीडेन्ट पर कमिशन लगाया जाता है उस समय भी वह अनुरित समापत्रिष करता है। इसके उपस्थित सदस्यों के हो-तिहाई के बहुमत की राय से दिया जाता है।

## जैकोस्तोवाकिया

ऊँचा भवन सीनेट ।

मताधिकार आम प्रत्यक्ष समान मताधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

वयस्क मताधिकार=२५ वर्ष की आयु ।

सदस्यों की आयु=४५ वर्ष ।

सदस्य-संख्या=१५ ।

अवधि = ८ वर्ष ।

कानूनों को दोनों ही मण्डलों में प्रस्तावित किया जा सकता है । कानूनों पर दोनों ही मण्डलों की स्वीकृति आवश्यक है ।

यदि चेम्बर आफ डिपुटीज प्रस्तावित करे तो सीनेट को १—एक सप्ताह में पुष्टि कर देना चाहिए ।

२—आर्थिक बिलों की एक माह में पुष्टि कर देनी चाहिए । यदि सीनेट द्वारा प्रस्तावित हों

तो चेम्बर आफ डिपुटीज को उनकी पुष्टि १ माह में कर देनी चाहिए । टिप्पणी — किन्तु यदि इसी बीच में किसी की अवधि समाप्त हो

जाय तो वह दोष समझ नहीं बैठक में गिना जाता है ।

( i ) यदि चेम्बर आफ डिपुटीज द्वारा प्रस्तावित हो, और सीनेट उसे अस्वीकृत कर दे तो चेम्बर आफ डिपुटीज के द्वारा पूर्ण बहुमत से

द्वारा पुष्टि किये जाने पर बिल पास हो जाता है । ( ii ) किन्तु यदि सीनेट तीन-चौपाई के बहुमत से अस्वीकृत कर दे, तो चेम्बर आफ डिपुटीज के १/५ बहुमत की विन को पास करने के लिये आवश्यकता

होती है । ( iii ) यदि सीनेट प्रस्तावित करे और चेम्बर आफ डिपुटीज अस्वीकृत कर दे तो सीनेट द्वारा पुष्टि कर उसे फिर विचारार्थ भेज सकता है; और यदि चेम्बर डिपुटीज भी अस्वीकृत कर दे, तो विन को एकदम त्याग दिया जाता है । इस प्रकार अस्वीकृत बिल दुबारा १ वर्ष

के भीतर प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किसी भण्ड द्वारा संशोधन का कार्य एक प्रकार से अस्वीकृति होता है।

कॉन्फ्रेंस कमीशन को शिक्षा, तथा स्थानीय सरकार के संघ में स्वतंत्रता प्राप्त है और उसे राष्ट्र-संघ को आपील करने का अधिकार है।

: १३ :

## पोलिश प्रजातंत्र

ऊँचा भवन सीनेट।

जुनी हुई समा।

अधिकार —

सीनेट में संशोधन ३० दिन के बाद प्रस्तावित किये जा सकते हैं। वे बिल द्वारा पास किये जा सकते हैं या ११/१२ के बहुमत से अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी हालत में वे अस्वीकृत समझे जाते हैं।

४ प्रांत प्रत्येक प्रांत से एक-बोयार् सदस्य किये जाते हैं। आनुवांशिक प्रतिनिधित्व।

सीनेट के सदस्यों की संख्या—बाह्य की संख्या की एक-बोयार्।

मतदाता—आयु ३० वर्ष।

सदस्य—आयु ४ वर्ष।

बिल स्वयं अपने को दो-तिहाई के बहुमत से अपना प्रेसीडेन्ट उसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के १/५ के बहुमत की सहमति से मंजूर कर सकता है। ऐसी बैठकों का कोरम सदस्य संख्या का आधा होता है। सीनेट भी साथ में मंजूर कर दी जाती है।

१४

## स्वीडन

ऊँचा मजल सीनेट ।

संसदा १५ सदस्य । अल्पसंख्यक रूप से चुने जाते हैं ।

सदस्य के पाठ चुने जाने के तीन वर्ष पूर्व से इतनी वास्तविक सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका कर लगाने का मूल्य ५०, ० क्रोन ( २, ००० पीरड ) हो या वार्षिक आय १ ० क्रोन ( १९५ पीरड ) हो ।

अवधि ८ वर्ष । प्रति वर्ष ३ सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं । ये सदस्य कान्टन्टी कान्टसिलों और १ नगरों के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं जो ८ समूहों में विभाजित हैं । प्रति वर्ष इनमें से एक समूह में चुनाव होते हैं ।

सन् १८९१ ई० के बाद से स्त्रियाँ अपना स्वीकार चुनती हैं ।

दोनों भवनों को समान अधिकार प्राप्त हैं ।

जब दोनों चेम्बर अलग अलग मत देते हैं तो दोनों चेम्बर में अलग अलग मत-संयोजना कर निर्णय कामा जाता है । दोनों का बहुमत किसी विषय का निर्णय करता है ।

१ १५ १

## नार्वे

ऊँचा मजल स्तेगटिंग

स्तेगटिंग का निर्माण स्टेथिंग के एक-बीयाई सदस्य चुने जाकर होता है । शेष तीन-बीयाई प्रथम मजल जो 'अडलरिंग' कहलाता है, के सदस्य होते हैं ।

लैबर्टिंग तथा सुप्रीम कोर्ट, अथवा दोनों के तीस सदस्य मित्राकर दोनों के प्रेसीडेन्टों सहित रीलस्क्रूट का निर्माण करते हैं। रीलस्क्रूट काठमिन्स आफ स्टेट के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों पर विचार करती है। अथवा स्टोर्पिंग का सुप्रीम कोर्ट अडेल्हर्टिंग के अभियोग पर विचार करता है। लैबर्टिंग का प्रेसीडेन्ट सम्भाषित्व करता है। अभियुक्त एक तिहाई तक को चुनौती दे सकता है किन्तु न्यायस्थान की सदस्य संख्या न्यूनतम पंद्रह होती है।

यदि दो बार उपस्थित किने कामे पर लैबर्टिंग दोनों बार अस्वीकृत कर दे तो स्टोर्पिंग द्वारा दो-तिहाई के बहुमत से उस विषय का निपटारा हो जाता है। इनमें से प्रत्येक विचार निमिषत्र में कम से कम १ दिन का अवसर दिया जाना चाहिए। पाठ होने पर राजा तो स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा उसे वापिस भेज देगा। इस हानत में उसे राजा के सम्मुख हुबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

यदि बिना परिवर्तन लगातार तीन स्टोर्पिंग ( चुनत्र ) से पाठ हो जाता है, तो एक दूसरे से दो लगातार होने वाले अभियेसनों से दूर होते हैं और फिर राजा के सम्मुख राज्य के सिबे साम्राज्यक बतमा बाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वीकार कर लिया जाता है।

१६

## आस्ट्रिया

### ऊँचा मण्डल फेडरल काउन्सिल

विधान तथा लोअर आस्ट्रिया को १२ सीटें दी गई हैं और अन्य प्रांत अपने नागरिकों की संख्या के अनुपात से सदस्य भेजते हैं। न्यूनतम संख्या तीन है। प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्वाम्यात्मक मी नियुक्त किया जाता है। कम से कम एक सीट उस पार्टी को दी जाती है जिसके दूसरे मन्बर एक से ऊँचे मत पड़े हैं। प्रांतीय बाइटों द्वारा बास्तुनातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। चुनात्र ऐसे व्यक्तियों में से होता है जो प्रांतीय बाइट के सदस्य नहीं हैं।

समापत्यिक जारी जारी से प्रांती के बात छह माह के लिये बर्तमाना के अनुसार मध्य पर रहता है। यह वह प्रांत के उस व्यक्ति को मिलता मिलते अधिकतम मत मिले हैं।

कोरम के नियम नेशनल काउन्सिल के समान हैं।

यह नेशनल काउन्सिल के पास कानूनों में संशोधन आठ सप्ताह में केवल आवश्यक द्वारा भेज सकती है। किन्तु नेशनल काउन्सिल द्वारा पुनरा पुष्टि (परिष्कार सप्ताह की अवधि में केवल काउन्सिल फिर संशोधन न करें) कानूनों को प्रमाणित कर देता है और कानून जारी कर देने करते हैं।

केवल कोरम नेशनल काउन्सिल के कार्यवाही के नियमों को संशोधित नहीं कर सकती। न वह नेशनल काउन्सिल को मंजूर कर सकती है और न संघ के अनुमानों को स्वीकार कर सकती है। यह संघ के श्रुतों और संघ की सम्पत्ति का रक्षण भी नहीं कर सकती। उनमें वह परिवर्तन भी नहीं कर सकती।

केवल काउन्सिल संघ के अनुमानों अथवा श्रुतों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

१७

## इंग्लैण्ड

ऊँचा मजबूत हाउस आफ लार्ड

(1) इसमें मिटिश पीयर (peers) होते हैं। (ii) १६ स्कॉटिश पीयर होते हैं। (iii) जीवन भर के लिये जुने हुए २० आयरिश पीयर होते हैं। (iv) थोके तथा कैबलररी के आर्क बिशप, तथा २४ सेंट अर्थ बिशपों के लिये होती है जिनमें लन्दन बिम्बेस्टर, ब्रिज के पादरी आचार्य रहते हैं। (v) और ६ कानूनी लार्ड।

लो-पीयरों को आर्थ-मैन में बैठने का नियम नहीं।

पीयर—यह जो स्थाया नहीं जा सकता, लेकिन जब प्रथम बार पर प्रथम बिशप आ रहा हो, ठीकी समय उसे आसीन बिशप जा सकता है। पार्लियामेंट के कानून द्वारा अथवा बिशप कार्यों से जूझ हो सकता है।



एक पीयर यह मॉग कर सकता है कि बेइज्रोह आपका मोर अपराध के अभियोग में पीयर हो उसका विचार करें।

सार्ज—मकन पर सार्ज बांसतर समापतिस करता है किन्तु उस अनुशासन के कोई अधिकार प्राप्त नहीं। यदि वो व्यक्ति बोसना चाहे तो उसे यह भी निश्चय करने का अधिकार नहीं कि कौन बोसोगा।

मकन स्वयं निर्णय करता है। वह मकन को स्वमिष्ठ भी नहीं कर सकता।

कोरम १। बुधवार तथा बृहस्पतिवार को बैठकें होती हैं। कभी कभी सोमवार तथा शुक्रवार को भी होती है।

कानून पास करने के लिए १० सदस्य उपस्थित होने चाहिये।

तीन अधिकार—(i) कोई भी सदस्य कांग्रेस की मॉगकर बाद विवाह प्रारम्भ कर सकता है। (ii) विशेष श्वाय अधिकार। (iii) सदस्यों के लिए स्वाबालन। आपील कोर्ट है और हाऊस आफ कॉमन्स द्वारा लागू किये कमिमीया पर विचार तथा निर्णय करता है।

हाऊस आफ सार्ज एक म्यायालय है जिसके सदस्य १ कानूनी सार्ज, सार्ज बांसतर तथा वे अन्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी कोई ठेका कानूनी पर मार लगाया हो।

पीयर के अभियोग पर सम्पूर्ण मकन विचार करता है। यदि उसका अभिवेदन हो रहा हो कानून तथा कर्मों दोनों बारे में नहीं तो मकन केवल कर्मों पर विचार करता है और सार्ज बांसतर कानून के सम्बन्ध में निर्णय करता है।

गति अधरोध—समस्त साधारण जिस जो हाऊस आफ कॉमन्स में १ सप्ताह अभिवेदनों में, जिसके बीच का अंतर प्रथम तथा अंतिम विचार में २ वर्ष हो, पास किये गये हैं स्वतः ही पास होगये लयके जाते हैं।

सरा —यह १ सार्जों के एक कमीशन द्वारा किया जाता है जिनमें सार्ज बांसतर भी एक होता है।

वे राजा का भाषण, मंज करत हुए, पढ़ते हैं।

१८

## डैम्पार्क

ऊँचा भवन लैब्ररी स्टेशन—

लैब्ररी स्टेशन—७६ तहसल होते हैं—इनमें से ५६ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक मण्डलों द्वारा चुने जाते हैं—और १९ तहसल लैब्ररी स्टेशन से व्यवस्थाग्रह करने वाले तहसलों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। ५६ तहसलों में से आधे का हर चौथे साल नया निर्वाचन होता है। १९ सीटों का भी हर चौथे साल चुनाव होता है।

प्रत्येक साठवें वर्ष हटा दिये जाते हैं।

सम्मेलनार्यों की योग्यताएँ —

फाकेटिंग के प्रत्येक मतदाता की आयु १८ वर्ष होनी चाहिये। उसे निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये लेकिन लैब्ररी स्टेशन द्वारा चुने गये १९ तहसलों के सम्मेलन में निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं।

केवल वही है जो फाकेटिंग के तहसलों को मिलता है। प्रत्येक भवन अपने क्षेत्रमें का स्वर्ण चुनाव करता है।

कोई भी भवन कानूनों को प्रस्तावित कर सकता है।

जब फाकेटिंग मिल को पास कर देता है तो वह लैब्ररी स्टेशन के पास अधिवेशन के सम्पन्न होने के तीन महीन के अन्दर में ही होता है।

वहाँ यदि वह पास न हो सम्पन्न होने में भवन किसी सम्मेलन पर न पहुँचे तो एक जोइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी नियुक्त की जाती है जो इस सम्मेलन में अगली रिपोर्ट देती है और अपने मुकाम उपस्थित करती है।

यह पश्चात् प्रत्येक भवन अपना निर्णय करता है।

और जब फाकेटिंग आम चुनाव द्वारा नये सिरे से चुन जाता है तो वह अपने सम्मेलन अधिवेशन में मिल को फिर एक बार स्वीकृत का

लैबरेटिंग के पास भेज देता है। यदि फिर भी कोई समझौता न हो सके तो राज्य लैबरेटिंग को भंग कर देता है। इस अवस्था के अतिरिक्त लैबरेटिंग केवल सभी और भंग होती है जब शासन विधान में संशोधन किया जा रहा हो।

राजा फाबेरिंग को भंग कर सकता है।

**टिप्पणी —**

सन् १९३८ ई. में एक मिल डेम्पार्ड की अवस्थापिका समा में प्रस्तावित किया गया था जो बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था। इसमें शासन विधान में दो बड़े परिवर्तन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम यह कि छँदा सकन छठा बिना जब, दूसरा यह कि मतदाताओं की आयु बढ़ा कर २१ वर्ष कर दी जाय; नये शासन विधान में अन्यतम गवना (Referendum) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सन् १९३५ ई० के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव जनता की राय जानने के लिये ली गये किन्तु प्रस्तावों के १५ में कुछ रजिस्टर्ड मजदूरों के ४५ प्रतिशत के बहुमत से मत नहीं आये जो कि आवश्यक था। अतएव यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

• १६

## वेल्लियम

**ऊँचा मकन सीनेट।**

प्रत्येक प्रांत से ठसकी जनसँख्या के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं। (१) आष हाइस आफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य (२) प्रांतीय काउन्सिलरों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा २००,००० निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुसार से चुने जाते हैं। प्रत्येक १,२५० निवासियों के नाम के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य होता है। (३) सीनेट आधी सँख्या को मिला सकती (co-opt) है। (४) आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुत्र, यल्लियम के राजकुमार, यदि

१८ वर्ष की आयु के हो, किंतु विचार-विनिमय में वे उस समय तक मग्न नहीं होते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो।

नोम्बराये (1) में वेस्मिन्सम के नागरिक जिन्हें नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। (2) मेंधियो, यूनीवर्सिटी के प्रेजु एटो, प्रांतीय गवर्नरों, पुराने सैम्ब आफसरों, प्रोफेसरों, व्यापारिक कम्पनियों के मैनेजर और वे प्रचुर काठस्थलों के प्रतिनिधि जो २ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये लगे हो सकते हैं। हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी लगे हो सकते हैं।

व्यापारिक व्यापारियों के स्थायी सदस्य और राबल एकेडेमी के पुराने सदस्य और प्रांतों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं। मंत्री तथा जेलीगेरानों के पुराने सदस्य भी चुने जा सकते हैं। एटोम-इरमेंट के पुराने कमिश्नर भी लगे हो सकते हैं। प्रांतीय काठस्थलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य जो कम से कम दो बार काठस्थल रह चुके हों किन्तु मास्टर (Bingo masters) पुराने एस्टर मैन, (aldermen) और प्रधान नगरों के एस्टरमैन भी चुने जा सकते हैं। वेस्मिन्सम कांन्वो के पुराने गवर्नर-जनरल तथा बाइस-गवर्नर जनरल, उपनिवेशिक काठस्थलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के सदस्य हो सकते हैं। डायरेक्टर-जनरल और पुराने इन्स्पेक्टर जनरल ऐसी वास्तविक कृष्यदात, जिसका व्यय गया मूल्य १२, ०० फ्रैंक है और जिस पर १ फ्रैंक की कीमत का कर लगता है, के मंत्री, स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये लगे हो सकते हैं। ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर जिन्की पूंजी १० लाख फ्रैंक है। औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख जिनमें १० व्यक्ति काम करते हैं और ऐसे कृषि-शालों के प्रमुख जिन में १० व्यक्ति काम करते हैं। ऐसे कृषि तथा उद्योग संबंधी समुदायों के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी जिन्की सदस्य संख्या ५० या अधिक है। ऐसे चेयरमैन कामर्स के प्रेसिडेंट जिन्की सदस्य संख्या १०० है। ऐसे मंत्रियों के निमागों की परामर्श परिषदों के सदस्य जो चुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य

लैबर्टिज्म के पास भेज देता है। यदि फिर भी कोई समझौता न हो सके तो राजा लैबर्टिज्म को मंजूर कर देता है। इस अवस्था के अतिरिक्त लैबर्टिज्म केवल सभी ओर भग होती है अब शासन विधान में संशोधन किया जा रहा हो।

राजा फ्रांसेटिग को मंजूर कर सकता है।

द्विपक्षी —

सन् १९६८ ई. में एक बिल बेन्गमार्क की व्यवस्थानिका सभा में प्रस्तावित किया गया था जो बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था। इसमें शासन विधान में जो बड़े परिवर्तन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम यह कि खंभा गवन उठा दिया जाय; दूसरा यह कि मन्त्रालयों की आयु घटा कर २६ वर्ष कर दी जाय; नये शासन विधान में जनमत गणना (Referendum) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सन् १९१५ ई० के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव जनता की राय बनाने के लिये सौंपे गये किन्तु प्रस्तावों के पक्ष में कुछ रजिस्टर्ड मन्त्रालयों के ४५ प्रतिशत के बहुमत से मत नहीं आये जो कि आवश्यक था। अतएव यह प्रस्ताव प्रायः नहीं हुए।

१६

## वेल्लियम

ऊँचा मकान सीनेट।

प्रत्येक प्रांत से उच्चतम अनर्सेन्स के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं।

(१) आगे हाइस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य (२) प्रांतीय काउन्सिलरों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा १००,००० निवासी के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुसार चुने जाते हैं। प्रत्येक १,२५ निवा-  
 तियों के भाग के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य होता है। (३) सीनेट  
 आधी सँघना को मिला सकती (co-opt) है। (४) आनुपातिक  
 प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुत्र, वेस्त्रियम के राजकुमार, यदि

१८ वर्ष की आयु के हो, किंतु विचार-विनिमय में वे उत उमर तक माम नहीं होते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो।

योम्पतायें (i) वे बेसिक्पम के नागरिक जिन्हें नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। (ii) मंत्रियों, यूनीवर्सिटी के प्रेसिडेंटों, प्रांतीय गवर्नरों, पुराने सैन्य अधिकारियों, प्रोफेसरों, व्यापारिक कम्पनियों के मैनेजर और वे मजदूर काउन्सिलों के प्रतिनिधि जो २ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं। हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी लड़े हो सकते हैं।

व्यापारिक व्यापारियों के स्थायी सदस्य और रायल एकेडेमी के पुराने सदस्य और प्रांतों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं। मंत्री तथा डेपुटी गवर्नरों के पुराने सदस्य भी चुने जा सकते हैं। एरोम्डा-इचमेंट के पुराने कमिश्नर भी लड़े हो सकते हैं। प्रांतीय काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य जो कम से कम दो बार काउन्सिलर रह चुके हों, सिनो मास्टर (Bingo masters) पुराने एस्टर मेन, (aldermen) और प्रधान मयों के एस्टरमेन भी चुने जा सकते हैं। बेसिक्पम काउंट्री के पुराने गवर्नर-जनरल तथा बाइस-गवर्नर जनरल, उपनिवेशिक काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के सदस्य हो सकते हैं। हायरैक्टर-जनरल और पुराने इम्पैक्टर जनरल ऐसी वास्तविक ज़ायदाद, जिसका मूँका गया मूल्य १२, ० ग्रेड है और जिस पर १०० ग्रेड की कीमत का कर लगता है, के मंत्री, स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं। ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर जिनकी पूंजी १० लाख ग्रेड है। औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख जिनमें १० व्यक्ति काम करते हैं और ऐसे कृषि-कामों के प्रमुख जिनमें ५० व्यक्ति काम करते हैं। ऐसे कृषि तथा उद्योग संबंधी समुदायों के चैबरमेन तथा सेक्रेटरी जिनकी सदस्य संख्या ५० या अधिक है। ऐसे चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसिडेंट जिनकी सदस्य संख्या १०० है। ऐसे मंत्रियों के विभागों की परामर्श परिषदों के सदस्य जो चुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य

मिनको व्यवस्थापिका सभा के दो-तिहाई के बहुमत से स्थापित किया गया है।

सीनेट के सदस्य उसी समय की असेम्बली तथा आये हो वर्ष तक असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते। कोई बैठन नहीं होता, किन्तु ४०० फ्रांक क्षति-पूर्ति के दिये जाते हैं, और साथ में मार्ग-भ्रष्ट भी मिलता है।

प्रत्यक्ष चुनाव। उम्मेदवारों के लिये सम्पत्ति संबंधी योग्यता नहीं है।

अवधि ४ वर्ष। पूर्ण रूप से बदली जाती है।

यदि सीनेट को मैन किया गया है, व राजा प्रांतीय काउंसिलों को भी मग कर सकता है। बैठ उसी समय हो सकती है जब हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की बैठकें हो रही हों।

• २० •

## इटली

### रॉया मदन—

इसे हाउस आफ लार्ज तथा कैनाडा की सीनेट को सम्मिश्रण सम्मिलित। इसके कुछ सदस्य (राजकुमार) वंशायत (hereditary) होते हैं। अन्य सदस्य, जो संख्या में २१ होते हैं, इन बार समुदायों में से चुने जाते हैं —

१—विशेष अवस्था तथा वर्ष-व्यवधिकारी।

२—सरकार से सम्बंधित व्यक्ति—जस और स्थल सेना से संबंधित।

३—किन्होंने विज्ञान अवस्था साहित्य में उपाधि प्राप्त की हो।

४—वे व्यक्ति जो निर्धारित न्यूनतम कर देते हैं।

सीनेट इस कारण पर किसी नियुक्ति को अस्वीकृत कर सकती है कि वह हम समुदायों के अंतर्गत नहीं आता।

सदस्य संख्या—निर्धारित नहीं। वर्तमान संख्या ४०० है—मिश्रणों को सरकार के साथ संबंध विगड़ जाने से रवाना नहीं मिला। मूलनिर्दिष्टों तथा एकेडेमियों को सम्बन्ध प्रतिनिधित्व मिला गया है। वैज्ञानिकों तथा विद्वानों को कम स्थान मिले हैं।

अधिकतर के सदस्य राजा द्वारा नामकृत हैं, चीनेट उन्हें स्थान प्रदान नहीं करने देती। संविधानसभा चीनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं, केवल आंक विपरीत के प्रति है। अब वह कुछ करना चाहता है, तभी दिग्गज पैदा हो जाती है।

० ७१

## जापान

ऊँचा भवन—हाउस आफ पीयर्स।

इसे निचले भवन पर उन्नत उच्च प्राप्त है। इसमें बजट में ठान मंदों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त कर सिद्ध है किन्हीं हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स तथा देता है। सम्राट प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति करता है। बाइस प्रेसीडेन्टों की भी कभी सदस्यों में से नियुक्ति ७ वर्ष की अवधि के लिये करता है।

प्रेसीडेंट—५००० वैन पाता है।

बाइस प्रेसीडेन्ट ३००० वैन पाता है।

सदस्य—२०० वैन पाते हैं। (वैन = हाउस) मार्ग मत्ता अक्षय मिसला है।

इसमें १—सम्राट के परिवार के सदस्य होते हैं।

२—कुलीनता की अवधि प्राप्त सदस्य होते हैं।

३—सम्राट द्वारा नामकृत सदस्य होते हैं—राजकुमार और मार्किसेज़—आयु २२ वर्ष—वयस्क होने पर स्थान ग्रहण करते हैं। काउन्सिल बाइकाउन्सिल और वैन की उम्मीद के अन्तर्गत सम्राट द्वारा चुने



जते हैं—(आयु २५ वर्ष—समुदाय के १)। प्रत्येक शहर और प्रीक्वेयर में कर-दाताओं द्वारा एक सदस्य चुना जाता है। अन्तिम प्रकार के सदस्य संख्या में १५ होते हैं और उनकी आयु १० वर्ष या अधिक होनी चाहिये। वे निर्धारित अधिकतम राष्ट्रीय प्रत्यक्ष करों को देने वालों द्वारा अपने समुदाय में से ही चुने जाते हैं।

४—सम्राट द्वारा नियुक्त सेवा आयका विभूता के कारण मामल—  
आयु १५ वर्ष—इस प्रकार के सदस्य संख्या में दो से अधिक नहीं हो सकते।

सदस्य संख्या—१०४।

यह मकान प्राविणील कानूनों को रोकता रहा है।

हाउस आफ रिजिस्ट्रेशन—१५ वर्ष की आयु से अधिक वाले सब पुरुष उम्मेदवारी के लिये कहे हो सकते हैं। केवल कुलीन परिवारों के प्रमुख, जहाँ आयका स्वतः सेना की सक्रिय सेवा में निरुक्त व्यक्ति, विद्यार्थी, सिन्टों मरामतगामी पावरी, सन्नी, समस्त प्रकार के जमी के पावरी तथा शिक्षक, सरकारी अफसर, सरकारी ठेकेदार और वे पुरुष जो कानूनी रूप से अयोग्य हैं, सदस्यता के लिये कहे नहीं हो सकते।

महाधिकारियों की योग्यता—आयु २२ वर्ष। उस विभाग में मरामतगामी की सूची बनने से कम से कम एक वर्ष पहले से उस विभाग में स्वामीरूप से निवास करते हों, और कम से कम १० केन प्रत्यक्ष राष्ट्रीय करों के रूप में देते हों।

मरत गुप्त बैठक (मरतग) द्वारा दिया जाता है। माम लिये करते हैं।

• २२

## मैक्सिको

हाउस आफ रिजिस्ट्रेशन को निम्न किलित अधिकार प्राप्त है :—

१—प्रीक्वेयर के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल की तरह बैठक।

१—रूप के नियन्त्रक के कर्तव्य पालन की वेत्तमास करना और उसके लिए बाफर निम्न करना ।

२—बजट की स्वीकृति प्रदान करना ।

४—पब्लिक बाफरों के विरुद्ध अभियोगों पर ध्यान देना, उन पर अभियोग लगाना और ग्राह्य गृही की तरह कार्य करना और उन समस्त बाफरों का उपयोग करना जो उसे शासन-विधान द्वारा दिये गये हैं ।

उत्तरदायित्व—

१—हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य चीनैट की सदस्यों की मौलि ही समस्त साधारण अपराधों और पदाधिकारों के रूप में किये गये अपराधों के लिये उत्तरदायी हैं ।

२—राज्यों के गभरनर और राज्यों की व्यवस्थापिका समार्यों के सदस्य शासन विधान और फेडरल कानूनों की मंग करने के अपराधों में उत्तरदायी होते हैं ।

३—प्रेसीडेंट राजप्रीह और और अपराधों के लिए उत्तरदायी होता है ।

जंथा मधन सीनेट

इसमें प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि होते हैं और प्रत्येक फेडरल जिले के दो प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं । उनके साथ स्थानापन्न भी चुने जाते हैं ।

अवधि ४ वर्ष ।

योग्यता हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समान ही है । आयु ३५ वर्ष । बिना सदस्यता लिये अन्य सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता ।

कोरम = दो—तिरार ।

स्थानापन्न को रूप अधिकेशन में उपस्थित होने की सूचना दिये बिना यदि कोई इस दिन या अधिक के लिये धन्य हो अनुपस्थिति के दिनों का वेतन प्राप्त

**बजट**—अंग्रेज पहली सितम्बर को आम सभा बैठ कर बजट की जांच पड़ताल करती है। बजट पर विचार करती है और अन्य विषयों पर निर्णय करती है।

**स्थगित करना**—कोई भी बिल बिना दूसरे बिल की सम्मति के तीन दिन में अगले के लिये अधिवेशन स्थगित नहीं कर सकता।

**सीनेट के मुख्य अधिकार —**

१—उन सन्धियों और समझौतों को स्वीकार करना जिन्हें प्रेसीडेंट ने अस्वीकृत कर दिया है।

२—प्रेसीडेंट द्वारा नामकृत राजदूतों तथा काउन्सिलों की नियुक्ति की पुष्टि करना।

३—राष्ट्रीय सेना को बाहर जाने और विदेशी सेना को अन्दर आने की आज्ञा देना।

४—प्रेसीडेंट द्वारा मेजबानगारों को बाहर मेजबान के सम्बन्ध में सहमति देना।

५—प्रारम्भिक करकारों के सम्बन्ध में आवश्यकों की घोषणा करना।

६—निर्धारित विषयों में प्रारम्भ बिलों की तरह बैठ कर कार्य करना।

७—राज्यों के आपस में राजनैतिक मत मतों को सुलझाना।

## प्रान्त और न्यायालय

१

### आयर लैण्ड

कुछ अन्य बातें—

कोई भी पाठ हुआ मिला, डेल आपरन के सदस्यों के  $\frac{1}{2}$  के बहुमत द्वारा वीनेट के साधारण बहुमत की सिद्धि माँग पर २० दिन के लिये संसूत्र किया जा सकता है। किन्तु इस २० दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही वीनेट आपरन के  $\frac{1}{2}$  के बहुमत की माँग पर वा मतदाताओं के  $\frac{1}{2}$  की माँग पर (आर्थिक विलों के अतिरिक्त) उक्त बिल पर अनुमत-संक्षेप (Referendum) की आज्ञा दी जा सकती है।

घोनों मकन मिलकर ओबरेचत (Oireachtas) करलाते हैं। यह अपने मातृहत व्यवस्थापिका समाजों और पेशेवर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार देकर स्थापित कर सकता है।

न्यायालय सुप्रीम कोर्ट।

सर्वोच्च अपील का न्यायालय—इसके निर्णय अन्तिम होते हैं किन्तु प्रिवी काउन्सिल के लिये अपील की छूट दी जा सकती है। न्यायाधीशों को ऐक्सीक्यूटिव काउन्सिल नियुक्त करती है पर दिलाने को वे सर्वोच्च-अन्तराष्ट्र द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

हाई कोर्ट की किसी कानून की वैधानिकता के सम्बन्ध में जीव कर सकती है।

: २ :

## कैनेडा

सभ की इकाइयाँ आस्ट्रेलिया में 'राज्य' और कैनेडा तथा दक्षिणी अफ्रीका में 'प्रान्त' कहलाती हैं।

सरकार के प्रमुख की उपाधि—लैफ्टीनेंट गवर्नर—दक्षिणी अफ्रीका में उसे भीषट कमिश्नर कहते हैं। आस्ट्रेलिया में गवर्नर कहते हैं। उनका कार्य राज गवर्नर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है। वे उन केन्द्रीय सरकार नियमित करती हैं।

कैनेडा—क्रीमेटेरियो तथा क्यूबेक की ऐक्सीक्यूटिव कमेटिबों केता गवर्नर-जनरल ठावित समझे समा सकता है।

लैफ्टीनेंट गवर्नर—प्रान्तों का केवाध्व—सरकारी भूमि का कमिश्नर—कृषिक तथा प्राइवेट निर्माण का कमिश्नर यदि उस समय नियमित किया गया हो जब वह पर पर बा छो पद प्राप्त करता है वह सकता है क्यूबेक में लेक्सिलेटिव काउन्सिल के स्वीकार तथा सोसीसिटर-जनरल के सम्मुख में भी यही नियम है। केवल नेवा स्कानिया और न्यू ब्रुनस्विक में पुरानी तरह काम चल रहा है।

क्यूबेक—ये एक लैफ्टीनेंट गवर्नर तथा व्यवस्थापिका समा के हो प्रकन हैं।

काउन्सिल में लैफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त १५ सदस्य होते हैं। गोम्बता हीनेट के सदस्यों के समान ही हैं। कोरम १० है। स्पीकर मत बैठा है, किन्तु दोनों पक्षों में बराबर मत होने पर प्रस्ताव मिला सम्मत्ता जाता है।

लेक्सिलेटिव असेम्बली में १५ सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्यानी बिषकी आयु २१ वर्ष हो चुकी है, क्रीमेटेरियो की लेक्सिलेटिव असेम्बली में मत दे सकता है। अवधि ४ वर्ष है।

केवल क्यूबेक में ऊँचा भवन है। क्यूबेक में स्थितों की मताधिकार और व्यवस्थापिका की सदस्यता नहीं हो जाती।

राज्यमण्डि की शपथ लेनी होती है। प्रान्तों में सीमित क्षेत्र में आनुशासक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है। लेफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा गवर्नर सम्राट के प्रतिनिधि होने हैं और सम्राट के विरोधाधिकारों का उपयोग करते हैं। प्रान्तों के एजेन्ट-जनरलों का सम्बन्ध के सामान्यन आदित्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट—कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। प्रेसीडेंट को एक कृपा बनाये रखने के लिये सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखने तथा नागरिक अधिकारों के लिये लाने के कार्य विधि कृपि प्रवेश इत्यादि के सम्बन्ध में केवल उही समय और सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है जहाँ तक वे प्रांतीय कानूनों के विरोधी न हों। कौन्सिलों ने भी स्काटिया और म्यू इन्सविज में इनको लागू करने के पूर्ण प्रांतीय व्यवस्थापिका समानता द्वारा कानून की स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। न्यायाधीशों को हाउस आफ कामन्स की प्रार्थना पर गवर्नर कन्सल परच्युत कर सकता है।

राज्यों के न्यायाधीशों से प्रिवी काउन्सिल को अपील की जा सकती है जबकि पहिले सुप्रीम कोर्ट में जाने के परचाल उचकी कूट पर अपील प्रिवी काउन्सिल को जा सकती है।

कैनेडा ने सुझाव दिया था कि प्रिवी काउन्सिल एक भ्रमसातक मरवा हो, और कैनेडा में कैनेडा के न्यायाधीशों को भिन्ना लिखा करे।

• ३

## आस्ट्रेलिया

गवर्नरों का सम्राट नियुक्त करता है। गवर्नर बहुमत पार्टी के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त कर देता है। और व्यवस्थापिका मन्त्र से ५ सदस्य नियुक्त करता है जो व्यवस्थापिका द्वारा से प्रति उत्तरदायी होते हैं।

राज्यों का सम्राट की सरकार से सीधा सम्पर्क है। उत्तर परामर्श पर गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वे कामन्सवैध सरकार बनवा गवर्नर



बानो चाहिए। वे समस्त आर्डीनिम्स जो पास किये जायें गवर्नर जनरल के पास मेरे जाये चाहिए।

शासनकर्ता तथा वे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलों में भाग्य देने तथा उसकी कापवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

शासनकर्ता को एक्जीक्यूटिव कमेटी में 'कास्टिंग वोट' मिली हुई है।

### सुप्रीम कोर्ट

इसमें चीफ जस्टिस साधारण अपील के न्यायाधीश तथा प्रांतों के न्यायालयों के निमित्त विभागों में अनेक न्यायाधीश होते हैं।

अरोबवाले विभाग से प्रिंसो काउन्सिल को जारी आती है।

चीफ जस्टिस—अनुचित व्यवहार अथवा अनोम्पता के लिए पार्लियामेंट के एक ही अधिवेशन में दोनों सदन के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है।

अरोल के न्यायालय—चीफ जस्टिस तथा दो साधारण न्यायाधीश तथा २ अरील के न्यायाधीश।

६

### फ्रान्स

#### सैन्सूत (कमेटी)

सेनर आफ डिपुटीज़ के ११ व्यूरो और सीनेट के ८ होते हैं। सभी पक्ष डालकर (allot) चुने जाते हैं। सेनर आफ डिपुटीज़ के ११ कमीशन हैं जिनमें से प्रत्येक के १४ सदस्य हैं। सीनेट की ११ कमिटियाँ हैं जो गुप्तकर से कार्य करती हैं। निम्न का रक्षिता उपरिष्ठ हो सकता है।

कुछ पार्षे—हाउस आफ कॉमन्स—इंग्लैण्ड—की रामस पर पूर्ण अधिकार कानून में तथा बाउंस में प्राप्त हैं। सेनर आफ डिपुटीज़



एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापनाधीन और एक-एक सदस्य स्वामी तथा अधिकार का होता है ।

कार्य-काल १ वर्ष के लिए होता है । २० वर्ष के समय में बिना इजाजत किसे आबका मजदूरों से अधिक काम सिने मजदूरी बड़ी है ।

५

## दक्षिणी अफ्रीका

शासनकर्ता का कार्य-काल १ वर्ष है और उनका बैठन प्रेसीडेन्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है । नियुक्ति में प्रांतीय विधानों के साथ नियोजन विचारों की जाती है ।

एक्सीक्यूटिव कमेटी में शासनकर्ता तथा ४ अन्य सदस्य होते हैं—वे काउन्सिल के सदस्य हो सकते हैं पर बाहर से भी सिने जाते हैं—काउन्सिल द्वारा चुने जाते हैं—उस समय तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उच्चविकारी में चुन सिने जायें—कार्य-काल निश्चित नहीं—इच्छाकामना रिक्त स्थान की पूर्ति या उसे काउन्सिल चुनाव से करती है या दोष सदस्य स्वयं मिताकर (co-opt) कर लेते हैं । चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है ।

कौंसिल उसने ही सदस्य होते हैं जिसने कि उस मान्य के हाउस आफ् असेम्बली में सदस्य होते हैं किन्तु म्यूनिसिपल संख्या २५ है ।

मंग नहीं की जा सकती ।

काउन्सिल स्वयं चेयरमैन चुनती है—स्वयं अपने नियम बनाती है किन्तु गवर्नर जनरल उन्हें अस्वीकृत कर सकता है ।

मंचा के नियम में गवर्नर जनरल की परिषद निर्णय करती है ।

शासन-सम्बन्धी अधिकार—समस्त विधायी में ओ प्रांतीय सरकारों के सिने नियत नहीं । शासनकर्ता गवर्नर-जनरल का एकमात्र एजेन्ड होता है और काउन्सिल से अलग कार्य करता है ।

आर्थिक विषयों की पहले से ही शासनकर्ता द्वारा नियंत्रित की

जानो बाधिए। वे समस्त आर्थिक जो पास किये जायें गवर्नर जनरल के पास भेजे जाने बाधिए।

शासनकर्ता तथा वे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलो में मायस देने तथा उसकी कार्यवाही में माग लेने का अधिकार रखते हैं।

शासनकर्ता को एक्जीक्यूटिव कमेटी में 'कार्डिफ बोर्ड' मिली हुई है।

### सुप्रीम कोर्ट

इसमें चीफ जस्टिस, साधारण अपील के न्यायाधीश तथा प्रांति के न्यायालयों के विभिन्न विभागों में अनेक न्यायाधीश होते हैं।

अपीलवाले विभाग से मिली काउन्सिल को जारीत जाती है। चीफ जस्टिस—अनुचित व्यवहार अथवा अयोग्यता के लिए पार्लियामेंट के एक ही अधिवेशन में दोनों मन्त्रों के प्रार्थना-पत्र पर हटाया जा सकता है।

अपील के न्यायालय—चीफ जस्टिस तथा दो साधारण न्यायाधीश तथा २ अपील के न्यायाधीश।

६

### फ्रान्स

#### सेनैट (कमेटी)

सेनैट आफ डिपुटीज के ११ मूले और सीनेट के ८ होते हैं। सभी पक्षे डालकर (allot) चुने जाते हैं। सेनैट आफ डिपुटीज के १९ कमीशन हैं जिनमें से प्रत्येक के १४ सदस्य हैं। सीनेट की १९ कमेटियां हैं जो गुमरूप से कार्य करती हैं। मिल का रचविषय उपरिष्ठ हो सकता है।

कुछ पक्षे—हाउस आफ कामन्स—ईंग्लैण्ड—की राज्य पर पूर्ण अधिकार कानून में तथा वास्तव में प्राप्त हैं। सेनैट आफ डिपुटीज

को केवल वास्तव में प्राप्त है। अमेरिका की हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव को न कानून के अनुसार और न वास्तव में।

**सुप्रीम कोर्ट**—कोई न्यायालय बार न्यायाधीशों का निर्णय बदल नहीं सकता लेकिन वा तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उस मामले को ठीकी पर के अन्य निचले न्यायालय को भेज सकता है जिससे मामला आता है। समस्त न्यायाधीशों को संविमंडल नियुक्त करता है।

**शासकवर्गीय न्यायालय**—कांठमिल काउन्सिल का कानून को इस प्रकार लागू करने से संबंध है जिससे जनता शासकवर्गी की निरंकुशता से बचाई जा सके। इसके १५ सदस्य हैं, इनमें साढ़े सरकारी कर्मचारी होते हैं। समस्त चार्जिमेस इसके पास होकर जाते हैं। कमी कमी वह उन्हें फिर से बना (redraft) देता है। सर्वोच्च शासक वर्गीय न्यायालय है। २१ अतिरिक्त विशेष काउंसिलर होते हैं। वह सरकार के एक कानूनी विशेषज्ञ परिषद के समान कार्य करती है।

## ७

## स्विट्ज़र लैण्ड

## साम्य

(१) दो कैन्टनों में और ४ ग्रैंड कैन्टनों में—कोई व्यवस्थापिक समार्वे नहीं है किंतु सभी प्रस्तावा सदस्य होते हैं। (२) घर को छोड़ कर साम्य कैन्टनों में व्यवस्थापिक समार्वे केवल एक भवन है (वे प्रायः कांठमिल या कैन्टन के कांठमिल कहलाते हैं।) वे कांठमिलें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। इस कैन्टनों में अनुसूचित प्रतिनिधित्व लागू है। (इस में १ या ४ वर्ष के लिए) प्रायः कांठमिल एक एकत्रीकृत कमीशन नियुक्त करती है जो फंडरल कांठमिल से मिलते जुलते हैं। (३) कैन्टनों को अपने शासन विधान बनाने की स्वतंत्रता है, किंतु वेब की स्वीकृति आवश्यक होती है।

सैन्य व्यवस्था कैबिनेटों के शासन में है। कैबिनेट शासन में कानून तथा न्याय संबंधी समस्याएँ कर सकते हैं। संघ को मुख्य तथा शान्ति का एक मात्र अधिकार है और न्यायाधिकार सम्पत्तियों के संबंध में भी।

दो कैबिनेटों तथा ४ सार्थ कैबिनेटों में समस्त जनता एक दफ्तार को प्रारंभ करे मेदान में समा करती है (उदाहरणार्थ ब्रिटेन)। नारियाँ तथा बच्चे कुछ उठी हुई भूमि पर पीछे खड़े रहते हैं। उन्हीं अगले वर्ष के लिये परामर्शकारियों का चुनाव होता है। उसके अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह कर लगा सकती है, व्यय कर सकती है कानून बनाती है तथा व्यवस्थापिका समा के अन्य अधिकारों का उपयोग करती है।

फेडरल न्यायालय—संघ तथा और कैबिनेटों की सत्ता में किसी मतभेद के होने पर यह निर्णय करता है।

कानून-व्यवस्था संबंधी केंद्रीकरण के साथ ही शासन संबंधी विकेंद्रीकरण (decentralisation) है। संघ के कानूनों को कैबिनेट लागू करते हैं।

दो रत्ना न्यायालय—२४ न्यायाधीश रहते हैं। वे देखभाल और कैबिनेट और संघ के विषय अन्य अधिकारों पर विचार करते हैं। तय्यों के निर्णय के लिये १२ सदस्यों की एक दूरी की सहायता ली जाती है—न्यायालय कैबिनेटों के कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं संघ के कानूनों को नहीं। किन्तु वे समस्त संघ के कानूनों पर विचार करते हैं—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दृग स प्रलना कीजिये।

फेडरल न्यायालय कैबिनेट तथा नागरिकों के अंगकों पर भी विचार कर सकते हैं, यदि वेना ही ऐसा चाहें।

सिस्टमरीसह में भी शासक न्यायिक कानून Administrative Law है। मामले फेडरल वाउमिशन के समुदाय उपस्थित होते हैं और अपील दोनों मामलों द्वारा सुनी जाती है। सन् १९१४ ई० के बाद स

एक 'एडमिनिस्ट्रटिव चार्ट' भी है। कानून इसा बकीलों की अधिकतम तथा न्यूनतम कीत नियत है।

कानून इसा बकीलों की अधिकतम तथा न्यूनतम कीत नियत है।

८ .

## जर्मनी

## राज्य

रीज़ की स्वीकृति से राज्य विदेशी राज्यों से कानूनों के संबंध में समझौते कर सकते हैं।

अन्य राज्य स्वयंसेवक निर्वाच में सम्मिलित हो सकते हैं। राज्यों में उत्तरदायी सरकारें हैं। नये राज्य तथा विभाज्य रीज़ द्वारा ठम क्षेत्रों प्रदेशों की स्वीकृति से बनाये जा सकते हैं किन्तु पर इतना प्रमाण पड़ता है यह स्वीकृति रीज़ के एक तिहाई की संख्या पर अलग होने वाले प्रदेशों के जन-मत-संग्रह ( plebiscite ) द्वारा ही जाती है और निर्वाचन मत देने के लिये बहुमत से अथवा समस्त मतदाताओं के बहुमत से होता है।

रीज़ कानून से सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर सकती है।

चुनाव संबंधी मामलों का निराकरण रीज़द्वारा तथा सर्वोच्च शासक कमीशन न्यायालय के न्यायाधीशों का एक कमीशन करता है।

सम्मति संबंधी मामले को अलग होने वाले राज्यों में ठठ कहे हों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाये जाते हैं।

राज्याध्यक्ष विधियों के निपटारे के लिये हाईकोर्ट तथा राज्यों के न्यायालय हैं।

६

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

राज्य सरकार का प्रमुख।

गवर्नर—बहुत महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है—चुना जाता है—जनता के मत द्वारा—उन पाठियों द्वारा नामज़द सरकारों में से किसी से प्रत्यक्ष

प्रारम्भिक समाप्तों Direct primary में चुनते हैं—मिलीटरी के अतिरिक्त सभी राज्यों में वही विधान है। कुछ राज्यों में कम्पैशन जुता कर उम्मेदवार नामजद करने की प्रथा अब भी है—कई वर्षों का नागरिक होना चाहिए—आयु ३ वर्ष—एक व्यक्ति से राज्य का निवासी हो। शिक्षा-सम्बन्धी तथा धर्म संबंधी कोई योग्यता नहीं। आगे के लगभग राज्यों में कार्यकाल २ वर्ष है। रोम में (१ के अतिरिक्त) ४ वर्ष है। कई राज्यों में हुकारा लका नहीं हो सकता। गवर्नर का राज्य में वही पद है जो कि प्रेसिडेंट का तथा में है। किन्तु वह प्रधान शासक नहीं है। उसके मातहत कार्य करने वाले उसका प्यान नहीं रखते। वे दूसरे राजनीतिक विचारों के हो सकते हैं और जनता के द्वारा चुने जाकर उसे परेशानों में डाल सकते हैं। उदाहरणार्थ—स्टेट कैबिनेटरी, आर्डीटर, कोषाध्यक्ष एकाउंटेंट-जनरल—जिन्हें गवर्नर हटा नहीं सकता। उसकी शक्ति उन अफसरों पर भी, जिन्हें वह नियुक्त करता है, बहुत कम होती है। वह किसी को पदच्युत नहीं कर सकता। सरकार के समान पद वाले अफसरों में ऊपर वह केवल एक होता है। व्यवस्थापिका समा-सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। नार्थ वेगोलीना के अतिरिक्त बोरो का अधिकार है। कुछ राज्यों में कांग्रेस के समान फिर से पाठ करने का अधिकार दिया हुआ है। कम्पैशन मिल सकता है—बख्त होता है—कार्यों सहित गवर्नर मेजता है—व्यवस्थापिका समा लगभग उसे पाठ करने के लिए बाध्य है। उसे आस्ताधारण अधिवेशन जुतामे का अधिकार प्राप्त है—जिससे उसके बताये गये विषयों पर विचार हो सके।

१—समा प्रदान का अधिकार। २—सैन्य शक्ति। (१) यह वह एक बोर्ड के सहयोग से उपयोग में लाता है। (२) आन्तरिक सेना का कमांडर इन-चीफ है—जो गवर्नर द्वारा बाहर जुलाई जा सकता है। यह स्थाई सेना नहीं—यहां एकाउंटेंट जनरल के मार्फत कार्य होता है। व्यवस्थापिका समा में राजनैतिक योग्यता का अभाव। गवर्नर बहुत शक्तिशाली है। १५ राज्यों में लफ्टीनेंट गवर्नर भी हैं—जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। वे सोनेट का अल्पसंख्यक ग्रहण करते हैं और प्रेसिडेंट का स्थान पिक होने पर उस पद को ग्रहण करते हैं।

केबीनेट नहीं होती—केवल प्रमुखों की नियुक्ति गवर्नर करता है।

## राज्यों के निचले मजदूर—

सदस्य संख्या १०० से १२५ तक। (ग्यूनतम ३९ तथा अधिकतम ४१२ हैं—पर ये प्रति के उदाहरण हैं।) ११ राज्यों में कम से कम २ वर्ष हैं। अधिकतम कम से कम ४० दिन तथा अधिक से अधिक ५ माह तक चलते हैं। २ या ३ राज्यों में मजदूर ४ वर्ष में एक बार अधिकतम करते हैं—शेष सभी के वार्षिक अधिकतम होते हैं। ग्रैंडीजेन्ड निर्वाचित होते हैं (हरीकर नियम संबंधी कमेटी में तथा छद्म-कमैटियों बनाने से बहुत अधिक प्रभाव रखता है। आम मतान्तरिक—गवर्नर तथा अन्य पदाधिकारियों का व्यवस्थापिका सभा में कोई स्थान नहीं होता। रंगीन नागरिकों को स्थान नहीं। किंतु उक्त का नून को सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेषित कर दिया है। कानून कमैटियों की सहायता से बना है—कानून बजाव कुछ करने के आरा भाव रह जाते हैं। केवल मैटेयूसेट्स में कुछ अधिकतम होते हैं। प्राइवेट विद्वानों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक होता है। पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तिगत लाभ (Log rolling) समझे देकर काम साधना (Block mail), हकठान, और सार्वजनिक मजदूरान की प्रभाव प्रभावित है।

## ऊँचे मजदूर

औसत संख्या ३५। जेफरीनेन्ड गवर्नर, यदि हो तो अप्रत्यक्ष पर प्रभाव करता है, नहीं तो एक ग्रेन्डीजेन्ड चुन लिया जाता है।

राज्यों के पास वे समस्त अधिकार होते हैं जो संघ को न देने गये हों। कॉन्ग्रेस के पास वही तथा है जो ही गई है। प्रांतीय मजदूरानों का चुनाव कॉन्ग्रेस के सदस्यों का चुनाव तथा नामाङ्कन इसके सदस्यों का कार्य है। कॉन्ग्रेस के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र नियंत्रण कटी है। कोई भी ११ राज्य शासन-विधान में संशोधन रोक सकते हैं। पारस-सभा के सदस्य, न्यायाधीश, गवर्नर, वैसागिक प्रमुख काठगरी तथा नगर पदाधिकारी बनता द्वारा चुने जाते हैं। इनके प्रमुख के जीवन के सभी पहलुओं से वास्ता है—व्यक्तिगत रूप से और समाज के सदस्य के माते। विवाह तथा तलाक का नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय रेलों प्रांतीय बैंक, बीमा कम्पनियों, पेरो मिलों दार्ज अथवा परिवारिक का कार्य भी है,

माई, लकड़ा ठीक करने वाले, रॉलों के बाहर, अमिक, चार्मनिक स्वाल्प—अमायालय पागल खाने, दान घर सिद्धा, लकड़े, मछली व्यवसाय, जंगली जानवरों का शिकार, मृगवा, कृषि भवन बीज गोदाम, बौध, सीबने के साधन सभी शामिल हैं।

: १० .

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

### सुप्रीम कोर्ट

प्राथमिक सत्ता

- १—राजदूत, चार्मनिक मंत्री तथा काउन्सिलों के विषय में,
- २—जहाँ एक पक्ष राज्य हो।

### अपील की सत्ता

कानूनी तथा सभी दोनों विषयों में है।

ये अपवाद हैं—

लजिबो—बीठी या मरिष्पात—के अन्तर्गत संघ के कानून।

ये समस्त मामले जो राष्ट्र-विधान के अन्तर्गत कानून अथवा अधिनियम के हों।

ये समस्त मामले जिनमें राजदूत, काउन्सिल शामिल हैं। अज्ञेयता तथा समुद्र तट सम्बन्धी मामले।

ये विवाद जिनमें संघ की एक पक्ष के रूप में हों।

ये विवाद जो राज्यों के बीच में हों।

एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिक के बीच में हों। एक दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच में हों, उसी राज्य अथवा निम्न राज्यों के नागरिकों में हों।

एक राज्य के नागरिकों के बीच में हों जो दूसरे राज्यों में प्रदान की गई भूमि के सम्बन्ध में दावा पैदा करते हैं।

एक राज्य तथा उसके नागरिक के बीच में या विदेशी राज्यों के नागरिकों अथवा प्रजा-जनों से।



न्यायाधीश प्रेसीडेन्ट पर नियुक्त किये जाते हैं और सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि करती है। अल्पसे व्यवहार तक परासीन रहते हैं। वास्तव में स्वतन्त्र हैं। संख्या में ९ होते हैं। कानूनी तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों की आलोचना करते हैं और उनकी वैधानिकता का निर्णय करते हैं और अमान्य ठहराते हैं। इस प्रकार राजनैतिक बाह-विषय में न्यायालय भी सिंच जाते हैं।

कानून तथा शासन-विधान में मतभेद होने पर अन्तरे निर्णय के कारण उन पर वह आरोप लगाया जाता है कि न्यायाधीश कानून की राय को दुबका देते हैं। ठहर यह है कि कानून-दृष्टा शासन-विधान में भी निहित है। इस प्रकार विधान अधिक सीमा तक मान्य है।

### साधारण न्यायालय

न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तथा व्यक्तिगत हितों के चलनेवाले मध्यकों में निर्णायक भाग लेते हैं—यही अमेरिका की सरकार का मूल सिद्धांत है।

उप के न्यायालय समस्त देश में बिखरे हैं। उनकी प्राथमिक (Original) तथा है, अपील की नहीं।

उपकोर्ट कोर्ट—अपील के हैं। संख्या ३।

कोर्ट आफ़ डेमर—१ अप्पेल-पर प्रहस करनेवाला न्यायाधीश, ४ सहायक न्यायाधीश। कमेिट स्थानित करती है।

कोर्ट आफ़ क्स्टन्स अपील—निर्माण सुपर के समान, ९ सर्किटों (circuits) में बैठता है। और जुड़ी के मामलों की सुनवाई करता है।

## सैकोस्लोवाकिया

वैधानिक न्यायालय में ७ सदस्य होते हैं—इनमें से १ शासन के हाईकोर्ट द्वारा चुने जाते हैं २ कोर्ट आफ़ क्स्टन्स द्वारा नियुक्त होते हैं

और ९ अल्प स्यायाधीन होते हैं। ये सदस्य तथा चेयरमैन प्रजातन्त्र के प्रेसीडेण्ट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

यह नियम करता है कि कानून शासन-विधान की प्रथम बार के समुद्देश्य हैं अथवा नहीं।

: १२

## स्लावों, कोटों तथा सर्वों का राज्य

काठमिण आफ स्टेट एक सर्वोच्च स्यायालय है। इसके आगे स्यायाधीशों की निर्णुक्त राजा उन सदस्यों में से करता है जो नेशनल असेम्बली द्वारा नामित किये जाते हैं और ये आगे नेशनल असेम्बली द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं जिन्होंने राजा नामित करता है।

१३

## पोलिश प्रजातन्त्र

### सुप्रीम कोर्ट—

यह नियंत्रण का सर्वोच्च स्यायालय है। इसका काम विधाय की रीति-रिवाज करना है।

इस सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेण्ट का यह संश्लेषों के बराबर है—किंतु इन्हें शासक में कोई स्थान प्राप्त नहीं। वे शासक की  $\frac{1}{2}$  के मत से पद प्युत किये जा सकते हैं।

युनाय सम्मन्धी अगलों (जहाँ विशेष दुष्टा है) का निरद्वय सुप्रीम कोर्ट करता है।

## स्वीडन

### सुप्रीम कोर्ट

इसमें १२ न्यायाधीश हैं जो "कार्डिनलसर्ज ऑफ कनेज़" कहलाते हैं।

राज्य सदस्यों की एक 'राशन परिषद' होती है जिसका काम राजा की सहमति के लिये क़ब्ज़ी संबंधी शायदा उन निर्णयों के विरुद्ध जोर कानूनों तब तक ले लाना हो चुके हैं प्रार्थना-पत्रों को लेना और उन पर निर्णय लेना होता है।

एक 'राशन परिषद' के निर्णयों को स्वीकार होना सभी की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है—बह क़ानून की व्याख्या करता है और ऐसी बदलावों के नियमों के विरुद्ध अपील करता है। विरुद्ध कार्य के समय जो ऐनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं और अपने विचार पेश कर सकते हैं।

### 'कानूनी परिषद'—

इसमें १ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक राशन परिषद का सदस्य होता है। इस परिषद का काम ऐसे क़ानूनों को, जो राजा के विचारार्थ लेके आते हैं बनाना, उन्हें स्पष्ट करना शायदा यह करना होता है।

### सार्वजनिक कमिशन का न्यायालय—

इसमें 'स्वी कोर्ट ऑफ अपील' के प्रेसीडेंट और राज्य भर के समस्त राशन-बोर्डों के प्रेसीडेंट-मण होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध 'राशन परिषद' के सीनियर सदस्यों द्वारा बलाये मामलों या इन सदस्यों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलाये गये मामलों में, सबसे ऊँचे ऐनिक और नाविक पराबिहारी, 'स्वी कोर्ट ऑफ अपील' के दो उच्च सदस्य और राज्य की राशन-बोर्डों में से प्रत्येक के दो सीनियर सदस्य भी बैठते हैं।

कोई भी व्यापारी बिना विशेष कारण काम करने से इन्कार नहीं कर सकता। प्रेसीडेन्ट के कार्यों पर भी आपत्ति उठाई जा सकती है।

संघी को इस कमेटी की सिफारिश पर कानून तोड़ने अथवा राजा के सामने रिपोर्ट पेश करने के अनुरोध में आवश्यक रूप से अपराधी ठहराया जा सकता है। यदि वह कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो रिक्रिमिन राजा से उसे पदच्युत करने की सिफारिश कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट और 'शान्ति परिषद' के सदस्यों की योग्यता की जाँच प्रत्येक बार वर्ष परचाट् रिक्रिमिन द्वारा नियुक्त की गई एक कमेटी करती है।

सदस्यों को वेतन का आधा पैगयन के रूप में देकर इनाम आ सकता है।

• १५

## आहिंसा

### प्रान्तीय सरकार—

प्रान्तीय काइंट द्वारा चुनी जाती है—वे काइंट के सदस्य नहीं होने चाहिये किन्तु उनमें काइंट की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए।

### व्यवस्थापिका सभा :

प्रान्तीय काइंट—प्रतापिहार नेशनल काउन्सिल के समान ही है।

प्रान्तीय कानून बनाने लागू करते हैं। यदि ऐसा करने में लक्ष्य की सहायता की आवश्यकता पड़े या सहायता मांगी जाती है, तो वह आवश्यक है कि प्रेसीडेंट असेम्बली उन्हें मंजूर करे। किन्तु सरकार की मंजूरी के पहले ही प्रत्येक कानून को राष्ट्रीय मंत्रिमण्डल के पास भेजा जाना चाहिये। यदि काइंट काइंट में कोई एतराज उठे तो प्रान्तीय काइंट (उपस्थिति है) उसे दुबारा पास कर सकती है। उसके बाद गवर्नर उसे स्वीकार कर लेता है।

### विधाना और लोअर आस्ट्रिया—

वियाना के सिधे शहर असेम्बली और लोअर आस्ट्रिया के सिधे प्रांतीय असेम्बली है—ये ही उनके सिधे प्रांतीय डाइट के काम लेती हैं। दोनों मिलकर सामान्य विषयों पर निर्णय कर लेती हैं। यही तो बाकी बातों में वे अपने आप अलग अलग काम करती हैं।

वियाना का 'बर्गो मास्टर' ही यहाँ का गवर्नर होता है। शहर की चीन्हेट म्यूनिसिपल काउन्सिल द्वारा चुनी जाती है। वह डाइट का प्रेसीडेंट होता है। मजिस्ट्रेट प्रांतीय शासकों के किलों का डायरेक्टर होता है।

सामान्य विषयों के शासन के सिधे 'प्रेडिमिनिस्ट्रेशन कमीशन' हैं—बारी बारी से गवर्नर समापवित्त करते हैं।

सामूली तौर पर डॉली की सजा नहीं दी जा सकती। म्याय संघीय कानूनएक सीमेन्ट की नियुक्ति का निर्देश कर सकते हैं। वे संघीय सरकार के सरकार म्यावाबीयों के नामों को स्वयं भी मामल्ल कर सकती हैं—वह मामल्लसिबों लाहरी स्थानों से संख्या में जुगनी या तिगुनी होनी चाहिए। म्यावाबीयों की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट या मंत्री करता है।

म्यावालय कानूनों को वैधानिकता के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते। यदि सम्बेह हो तो मामला वैधानिक अदालत को भेजा जा सकता है।

वैधानिक म्यावालय की सभी शर्तों पर विचार करने का अधिकार है। ( १ ) जो संघीय प्रांतों अथवा कानूनों पर किये जायें सामूली म्याय के तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। ( २ ) अदालतों तथा शासक बर्ग के बीच के झगड़ों का फैसला करने का अधिकार है। ( ३ ) साधारण और शासन संबंधी म्यावालयों के बीच के मामले भी इसके अधिकार में हैं। ( ४ ) शासन और वैधानिक म्यावालयों के बीच के मामले। ( ५ ) मेयरल काउन्सिल, फेडरल काउन्सिल, और प्रांतीय डाइटों या अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधि समाजों संबंधी मजदूरे तल्ल पुनारों का फैसला। ( ६ ) सार्वजनिक कमियोम लगाये जाने के प्रस्तावों पर यदि ( अ ) फेडरल असेम्बली फेडरल प्रेसीडेन्ट पर लगाने

का निर्णय करे, ( इ ) संघीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि नेशनल काउन्सिल ऐसा निर्णय करे, ( उ ) प्रांतीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि प्रांतीय काउन्सिल ऐसा निर्णय करे, ( जो ) प्रांतीय सरकार के विरुद्ध यदि वह राजनीतिक अधिकारों को छीन ले ( जी ) अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना पर ।

इस न्यायालय में एक प्रेसीडेन्ट, और एक वाइस-प्रेसीडेन्ट होता है जिन्हें नेशनल काउन्सिल ( सब सदस्य और प्रतिनिधि-वर्ग ) मिल कर चुनते हैं । बाकी के आठ सदस्य फेडरल काउन्सिल चुनती है ।

१६

नार्वे

सुप्रीम कोर्ट

बहु अपील का न्यायालय है । इसके साठ सदस्य हैं । साथ में एक प्रेसीडेन्ट होता है । इसके बाद कोई अपील नहीं ।

न्यायाधीश—आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिये ।

: १७

इंग्लैण्ड

न्याय विभाग

सन् १८७३ ई० के न्याय संघी कानून में वर्तमान न्यायालयों का होंका दिया—

I न्याय का सुप्रीम कोर्ट—दो शालाओं में विभाजित है ।

( जैसे नीचे दिलाया गया है )

( क ) न्याय का हाईकोर्ट

( ख ) कोर्ट ऑफ अपील

II हाउस ऑफ मार्ट्स या लार्ड जमा ।

III प्रिवी काउन्सिल की न्याय संघी कमटी ।

## I न्याय का सुप्रीम कोर्ट ( अब इसमें तीस से अधिक न्यायाधीश हैं )



(अ) जस्टिस विभाग । (इ) डिप्युटी चैंसलर- (ए) प्रोवेस्ट\* इसमें पौब साधारण जून । इसके १५ न्याया और एडमिरेन्सी जस्टिस- न्यायाधीश और लार्ड चीफ होते हैं । इनमें जून । इसमें दो न्याया- जस्टिसर प्रेसीडेन्ट एक लार्ड चीफ जस्टिस चीफ होते हैं । इसमें होजा है । भी होता है जो प्रेसी एक प्रेसीडेन्ट होता है । डेपुट होता है ।

न्याय के हाई कोर्ट के तीनों विभागों की अधिकार सीमा उनके मामलों से ही पता चल जाती है । इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश अलग-अलग मामलों से होते हैं और इस प्रकार सब मिलाकर यह २३ न्यायालय होते हैं—

(क) अपील कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीश होते हैं—

१—(अ) ८ कानूनी लार्ड ।

(ब) 'मास्टर आफ रोस्ट' जिसकी अदावत स्थायी होती है ।

२—तीनों उच्चोक्त विभागों के प्रेसीडेन्ट जो कभी कभी सदस्य होकर काम करते हैं ।

(३) लार्ड जस्टिसर की अपने पद के कारण सदस्य तथा प्रेसीडेन्ट होता है ।

इनमें से किसी से भी अपील कोर्ट की अपील का लफटी है । अपील कोर्ट में तीन टीम न्यायाधीश का एक न्यायालय होता है और साधारणतया "३ स्वामी सदस्यों" को दो दो इस प्रकार को बैस्ये होती है क्योंकि कभी कभी काम करने वाले न्यायाधीश और लार्ड जस्टिसर तो शायद ही कभी अतिथित होते हैं ।

\* प्रोवेस्ट ( Propate ) का तात्पर्य बसोयतनामों की प्रामाणिकता सिद्ध करने से है ।

इनके बाद काउन्सिल ( जिसका ) स्वाध्यायों का मन्तर होता है । इनके साथ ही उन नूतने बाह्य हाई कोर्ट के स्वाध्यायों का भी स्थान है जो जिलों में "एसाइज" की तरह काम करते हैं । अंत में श्रीमद्वारी मामलों पर विचार करने के लिये ( अ ) कानून काण्ड प्रीस ( कानूनिक ), ( ब ) बेरो ( स्थानीय ) स्वाध्याय ( कानूनिक ) और हाईकोर्ट का नूतने वाली बैच के स्वाध्याय होते हैं । न्यू यार्क दिन पर दिन कम होती जा रही है ।

### लार्ड सम्राट

( ii ) वह अपील का अंतिम स्वाध्याय है । इसकी बैठक उक्त समय होती है जब लार्ड सम्राट का अभिषेकन हो रहा हो । लार्ड कानून समारोह करता है । इसमें ३ अपील के साधारण लार्ड स्वाध्याय भी ( अपील कोर्ट से ) शामिल होते हैं । कभी कभी एक तीसरा ( १ ) भी होता है । साथ में नूतनपूर्व कानून और हाईकोर्ट के एक या दो ऐसे नूतनपूर्व स्वाध्याय भी होते हैं जो जब लार्ड सम्राट में बैठने के अधिकारी हो गये हैं । लार्ड-सम्राट के सम्म सदैव कमी माग नहीं होते ।

### प्रिवी काउन्सिल की स्वाय संवंधी समिती

( iii ) इसमें लार्ड कानून, अपील के साधारण लार्ड स्वाध्याय, और बाहरी डोमिनिकों द्वारा अधीन देशों का एक स्वाध्याय रहता है । भारत के लिये अंतिम स्वाध्याय यही है । क ( ए ) स्वाध्याय से भी प्रोवेड और एक निरंकुश विभाग की वह अपील सुनती है ।

: १८

## धैर्यजयम

सभी स्वाध्याय की आजीवन नियुक्ति होती है और बिना अभिषेक बलापे किसी को पदस्थ नहीं किया जा सकता; न उन्हें पद से हटाया ही किया जा सकता है और न तलाक़ा ही । ऐसा केवल उनकी लक्ष्मि से और पूर्व नियुक्ति रद्द किया जा सकता है ।



( १ ) सबसे ऊपर एक 'कोर्ट ऑफ सेलेशन' ब्रूटेस्त में है। इसके न्यायाधीशों को राजा हो चुकियों में से, जिनमें से एक न्यायालय स्वयं तैयार करता है और दूसरी को सीनेट बनाती है, में से चुनता है।

( २ ) इसके बाद तीन खानों के न्यायालयों का नम्बर आता है जिनके सदस्यों को भी राजा हो चुकियों से चुनता है। इनमें एक न्यायालयों द्वारा स्वयं ही जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषदों द्वारा।

( ३ ) इसके बाद 'प्रथम शर के न्याय जनों' का नम्बर आता है—न्यायाधीशों को राजा नियुक्त करता है। किन्तु प्रेसीडेन्ट तथा वाइस-प्रेसीडेन्टों को राजा हो चुकियों में से नियुक्त करता है। इसमें से एक न्यायालयों द्वारा हो जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषद के द्वारा।

इसके नीचे,

( ४ ) 'एलाइज' के न्यायालय कीसदारी के बिने है।

( ५ ) सेम न्यायालय।

( ६ ) व्यापार संबंधी न्यायालय।

( ७ ) और 'असिस्ट ऑफ पीठ' के न्यायालय।

इस संबंध में कोई भी शासन संबंधी न्यायालय नहीं है।

न्यायालयों की बैठकें खुली होती हैं। पर नैतिकता या सार्वजनिक हित की दृष्टि से कुछ बैठकें हो सकती हैं।

राजनीतिक और प्रेस संबंधी मामलों में जूरी का प्रयोग आवश्यक है। न्यायाधीशों को हो चुकियों में से नियुक्त किया जाता है। प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्टों का न्यायालय स्वयं आपस में से चुनाव कर लेते हैं।

## जापान

### न्याय विभाग

१—न्यायालय सम्राट के नाम पर न्याय करते हैं। सम्राट को कामूज और न्याय का स्रोत कहा जाता है। न्यायाधीशों के पद

सुपडित हैं। उन्हें बिना अभियोग बताया पदच्युत नहीं किया जा सकता।

सुइडन और उनके फेरले कुली बैठकों में दिये जाते हैं, किन्तु कुली बैठक के नियम को कानून द्वारा या म्यादालय स्वयं यदि म्यादा-लय की कार्यवाही का प्रकाशन शक्ति या वार्षिक नैतिकता की दृष्टि से हानिकर प्रतीत हो तो उसे मनसुख कर सकता है।

२—शासक सत्ता द्वारा अधिकारों पर हस्तक्षेप करने पर सुइडन में बलाया जाने पर, अथवा नागरिकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होने पर मामला 'शासन सम्बन्धी सुइडनों' के अन्तर्गत सुना जाता है—बाधारण म्यादालयों के सामने नहीं—और ग्री की सहमति से सुनाई होती है।

३—म्यादालयों को शासन-विधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है।

सत्ता सम्राट के पास है—प्रस्तावित संशोधन सम्राट के द्वारा राष्ट्र के सम्मुख उपरिषत्त किया जाता है—कोरम १।१ संख्या—प्रत्येक भवन में—संशोधनों पर विचार करने और उन्हें पास करने के लिए कम से कम उपरिषत्त सदस्यों के १।१ के बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए।

डोमिनो में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके नौ विभाग हैं। प्रत्येक में पाँच म्यादाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त सात अरीस के म्यादालय हैं। उनमें भी नीचे जिला के म्यादालय हैं। छोटे-मोटे मामलों के लिए मामूली म्यादालय भी हैं।

एक शासन-सम्बन्धी म्यादालय भी है जिसके म्यादाधीश प्रवा मंत्री की सिफारिश पर आजीवन के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

२०

## एस्थोनिया

म्यादाधीश निर्वाचित होते हैं।

२१

## डेन्मार्क

## केन्द्रीय न्याय विभाग

न्यायाधीश १५ वर्ष की आयु पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं पर उन्हें केतन मिलना पड़ता है।

## सार्वजनिक अभियोग का न्यायालय—रीगस्ट्राट

सुप्रीम कोर्ट के अब साधारण सदस्य, और उनकी ही संख्या में ऊपरी मजान के सदस्य होते हैं। न्यायालय अपने ग्रेटीडेण्ट का स्वयं चुनाव करता है। ऊपरी मजान के सदस्य अपनी सदस्यता से अलग हो जाने पर भी न्यायाधीश बने रहते हैं और कामचाली में भाग लेते हैं। मंत्री या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर राजा या क्राउनटीन न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगा सकती है। न्यायाधीश १५ वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

२२

## इटली

## न्याय विभाग

अब सरकारी कर्मचारी निजी अधिकारों—स्वाधों में नहीं—वे हस्ताक्षर करने पर साधारण न्यायालयों के सम्मुख पेश किये जा सकते हैं—झाँच से दुकान कीजिए वहाँ अधिकारों और स्वार्थों दोनों ही मामलों में एक-जा बर्तना होता है।

‘कोर्ट ऑफ सेवेशन’ (Cession) एक विशेष न्यायालय है। यह समस्त न्यायालयों के ऊपर अंतिम न्यायालय है। यह न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि कोई विशेष मुकदमा किसी न्यायालय में जाना चाहिये।

न्यायाधीशों को सम्राट मंत्रियों की ठिकानिका पर नियुक्त करता है। साधारणतया उनकी वे की जाती है। कानूनी योग्यता अवश्य होनी चाहिये। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए तबादले होते प्यते हैं और

यह से अलग भी किया जा सकता है—ये सभी नियम 'कोर्ट आफ् कंसेशन' के सामने रखे जाते हैं।

बूरी प्रथा है—किन्तु उत्तरेज्जगत् नहीं।

शासन संस्था की ट्रिब्यूनल —प्रत्येक प्रांत में है। ग्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रियों की सिफारिश पर सम्पाद करता है।

मंडल में इसी प्रकार की संस्था 'काउन्सिल आफ् स्टेट' है।

२३

## मैक्सिको

### संघीय राज्य

१—मैक्सिको के राज्य में लोक संसत्समूह किरम की सरकारें हैं और उनमें लोकप्रतिष्ठ प्रतिनिधि संस्थानें हैं। प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात से है, किन्तु न्यूनतम संख्या १५ है।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य और एक स्थानागम चुना जाता है।

सीमायें राज्य के ऐजेन्ड के द्वारा कमिश्न की स्वीकृति पर निर्धारित की जाती हैं।

इन्हें मुद्रा और विनियम अथवा अंतर्रांगीय शुल्की संरक्षी अधिकार प्राप्त हैं।

२—शासन विधान में यह निर्देश दिया गया है कि संघ तथा राज्य की व्यवस्थापिका समाने प्रकार बन्दी के लिये कानून बना सकेगी।

३—दिना कीमेत की अनुमति के कोई भी राज्य तटकर या यजनकर (Tonnage dues) नहीं लगा सकता और न स्थायी सैन्य या सुद-बोत रख सकता है।

४—राज्यों को, निर्देशी हमले से बचाव के लिये, सौकरतब की सहायता पाने का पूरा अधिकार है।

५—कोई भी व्यक्ति एक राज्य से पद, न्याय के या शासन के प्रमुख नहीं कर सकता।

## : ६ :

# आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

१

## आयरलैण्ड

### आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

निम्नलिखित विचारों को विचारार्थ रिज़र्व करने की उम्मीद को स्वीकार करता है और व्यवहारिक उपाय को मजबूत करने के अधिकार का निष्कर्ष निकालता है क्योंकि सन् १९९९ ई० तक वह प्रथा प्रचलित नहीं रही थी।

आधारभूत अधिकार और भावना —

नागरिकता — कोई भी व्यक्ति जो स्वयं, या जिसके माता-पिता या उसे आधारभूत में पैदा हुए हों या ७ वर्ष से रह रहे हों।

भाषा — आयरिश है पर इंग्लिश भी मानी जाती है।

विचार 'क्याटिचिल आउट स्टेट' के परामर्श से कोई एक्ट नहीं हो जा सकता।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता — विचार लेम्ब आधारभूतताओं के समक्ष कुछ व्यवस्था विरोध के कारण — एक को प्राप्त है।

धर्म और सामाजिक सम्बन्धी स्वतन्त्रता (आर ८)।

स्वतन्त्रता पूर्वक सोचने और समा करने का अधिकार। भावनात्मक शिक्षा का एक के लिये प्रयत्न है।

समस्त भूमि, जल, कार्ने और लमिच पर्याप्त राज्य की उपस्थिति है और कानून के मुताबिक उसका प्रयत्न होता है — कोई एक्ट (Lease) ३२ वर्ष की अवधि से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता।

२

## आस्ट्रेलिया

साम्राज्य की सरकार के अधिकार :

कोई भी ऐसा बिल जो किसी काउन्सिल को जाने वाली अपीलों को सीमित करता है या जो संघीय राज्य या किसी मन्त्र के शासन विधान को परिष्कृत करता है या जो गवर्नर के बैठन में कमी-बेसी करता है संसद की अनुमति के लिये एक लिये जाते हैं। अस्तित्व विषय में यदि सर्वान्त से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं।

निर्देश पत्र (Instrument of Instructions)—विश्वों को सुपक्षित करने के विषय में—सन् १८९६ की साम्राज्य की कांग्रेस में इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक गोमिनिशन को करने बरेख मामलों में संसद को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी बिल को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले से ही विचार-विनिमय कर लेना उचित समझा जाता है।

प्यत्रा—नौसे विधानों सहित यूनिनन बैंक वहाँ की सेना के लिये प्रयोग किया जाता है।

३

## कनेडा

आघात भूत अधिकार—इनमें शिवा भी सम्मिलित है।

४

## दक्षिणी अफ्रीका

साम्राज्य की सरकार के अधिकार

कोई भी ऐसा बिल जो प्रीवि काउन्सिल को जाने वाली अपीलों को

सीमित करता है या राष्ट्रीय राज्य का किसी मन्त्र के शासन विधान को परबर्धित करता है या गवर्नर के वेतन में कमी-बेसी करता है, सम्राट की अनुमति के बिना रण लिये जाते हैं। अन्तिम विषय में यदि गवर्नर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं।

**निर्देशपत्र (Instrument of Instructions)**—विश्वों को सुरक्षित रखने के विषय में—सन् १९१९ की साम्राज्य को कन्फ़ेर्मेट में इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक ब्रेमिनिशन को अपने धरे हुए मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी भी विषय को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले ही से विचार विनिमय कर लेना उचित समझा जाता है।

**हिताव-निरीक्षक (Auditors)**—प्रत्येक राज्य में स्वाधीन हिताव निरीक्षक हैं जिन्होंने विवाय प्रेसीडेन्ट और गवर्नर जनरल की विवृति के नहीं निकाला जा सकता। उनको गवर्नर जनरल और प्रेसीडेन्ट निर्धारित करते हैं। कोष से धन लेने के आवापत्रों पर 'शावक' के हस्ताक्षर होते हैं। उस पर हिताव-निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

**सरकारी नौकरियाँ**—प्रेसीडेन्टों को पद देने के लिये एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हुई, और उपर्युक्त गवर्नर जनरल द्वारा प्रांतों के लिये एक स्थानीय पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया।

**भाषा**—अंग्रेजी और उर्दू राज्य-भाषाएँ हैं।

**नागरिकता**—उमस्त व्यक्ति जो राज्य में पैदा हुए हैं और विदेशी नहीं है—वे क्रिश्चियन प्रजाजन जो मुस्लिम में रहते हैं अथवा जिन्हें मुस्लिम की नागरिकता दे दी गई है या वे जो मुस्लिम में तीन वर्ष से रहते हैं और मुस्लिम के मकरिकों के अन्तर्गते।

अन्ध राज्य की नागरिकता अपनाते पर मुस्लिम की नागरिकता नहीं रहती।

**धर्म**—राष्ट्रीय धर्म और मुस्लिम धर्म—अर्थात् पुरानी रिपब्लिकन धर्म।

## न्यूजीलैंड

युद्ध के पूर्व एक विधित्त सर्वित कमीशन बन गया है।  
 स्थानीय सरकारों में—प्रतियों की योग्यताएँ स्थितियों के लिये  
 पर्याप्त समझी जाती हैं। बोरो (Borough) काउन्सिलों के चेयरमैन  
 चुने हुए होते हैं। कुछ बोरो माध्यमालाएँ बनाती हैं। शिक्षा के  
 सम्बन्ध में डोमीनियन सरकार से सहमति मिलती है किन्तु प्रमुख  
 १३ बोर्ड करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है।  
 नौकरियों में प्रतियोगिता द्वारा मर्त्य होती है—आयु १४ वर्ष।  
 डाक, तार और रेल विभागों के अनिवार्य वह काम एक तैर  
 रास्तीविह सर्वित कमीशन के सुपुर्द है।  
 सरकारी पद के अनुसर ही जाती है—किन्तु विभिन्न भेदियों में  
 सरकारी हेतु समय परीक्षाएँ होती हैं।  
 आभासमूर्त अधिकार—प्रतिपादाती आसुर विवा और कनाडा  
 की मौति ही इनसे वचित हैं। प्रत्येक चीन निवासी को जो देश में  
 प्रवेश करता है १०० पीड 'कर'के रूप में देने होते हैं।  
 ध्वजा—नीले निशान का ही परिवर्तित रूप है।

## फ्रांस

प्रत्येक मंत्री का अपना एक छोटा-सा मंत्रिमण्डल रहना है जिसका  
 एक प्रधान और एक उपप्रधान होता है। प्रधान और उसके सहकारी मंत्री  
 के साथ ही आते जाते हैं—किन्तु वह आते कभी-कभी ही हैं क्योंकि  
 ही बोध में ठगड़े स्थायी पद मिल जाते हैं। विभिन्न भेदियों में बहुत  
 अचरम हैं। विभागों का प्रमुख एक डाइरेक्टर होता है। यह विभिन्न



उप-विभागों ( Dureaus ) में बँटि रहते हैं और इनका प्रभान एक स्वामी अफसर होता है। कमसे कम ५००,००० वर्गवारी हैं। प्रतिबोहिता परीक्षाएँ होती हैं। उनकी परब-बोम्बता और सिफारिश के आचार पर ही जाती है।

**म्याय विभाग—**

कानून स्वान-रवान पर अलग अलग है। प्रत्येक स्वावालय में स्वावालीशों की बैठ होती है। ६० स्वावालीश हैं जबकि ईंग्लैंड में १०० हैं। म्याय-विभाग शासन-विभाग का एक अंग समझा जाता है।

**जिज्ञा स्वावालय—५ १६**

**केन्टन स्वावालय—१ १६ १०१६।**

अपील का स्वावालय परिषद में है। इसके तीन विभाग हैं—सार्वजनिक अभियोग लगाने वालों को एक स्वावी बैठ है। केन्टन 'कोर्ट ऑफ एलाइज' में सूरि का प्रयोग होता है—केन्टन कोर्ट। सुपीम कोर्ट—४६ स्वावालीश हैं।

**१ विशेष डिप्युनस हैं—**

**स्वाथारिक स्वावालय—मजदूर स्वावालय—अतिपूर्ति स्वावालय।**  
समस्त स्वावालीश मजदूर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं—

**अक्रिबों—**लीम-बोयार्ड स्वागों पर वे पर और बोम्बता के अनुसार की जाती है, शेष की अन्य तरीकों से। कैन्टन कोर्ट स्वावालीशों के विरुद्ध दुर्भबहार सम्बन्धी मामलों की सुनवाई कर सकता है और उन्हें हटा सकता है।

**प्रीमरी कार्रवाई का डया—**प्राथमिक अपील-वद्वतल कोठरी ( केद ) में होती है—उसके बाद स्वावालीश अभियुक्त से अपील तरह बदलोकर करते हैं। लाष्टी के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। पाँच स्वावालीश अभियोग लगाते हैं। इसके बाद मामला सूरि के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसमें १६ व्यक्ति होते हैं।

बीबामी पर किनको कि हानि हुई है, गवाहों को बुलाती है। पहले स्वावालीश उनसे प्रश्न करते हैं और सूरि के सदस्य भी। इसके बाद बकील लोग अपनी मुक्तिवों पेश करते हैं। अभियोग सफाई

मकानों को पुलिसों का लम्बन, फिर सफाई। न्यायाधीश जूरी के हाथों में पूरा अधिकार नहीं सौंपती, केवल प्रश्न पूछते हैं। जूरी प्रश्नों का उत्तर मतपत्रों द्वारा देते हैं। न्यायाधीश पुलिसों के कमरे में जाता है जूरी अमेरिका की तरह कभी भी न्यायाधीश के पास परामर्श के लिये नहीं जाती। जूरी नवंबर प्रथम दफ्त के बारे में अपनी सलहों करना चाहती है—न्यायाधीश अभिसुक्त को केवल सर्व सम्मति से छोड़ सकते हैं लेकिन जूरी की छुट्टी पक्ष और छुट्टी विपक्ष में जाने पर या सप्त पक्ष और पांच विपक्ष में जाने पर वे अभिसुक्त को दफ्त नहीं दे सकते। राजनीतिक विषयों में और इच्छाल सम्बन्धी मामलों में जूरी इसका दफ्त देती है। अपराधों और आदेशों में दिये गये अपराधों के अस्तित्व कायम है।

बन्दी अपने विरुद्ध स्वयं साक्षी देता है।

७

## स्विटजरलैंड

मन्तरल शास्त्र-केन्द्रीय और राजकीय।

केन्द्रीय शासन कायम और न्याय के लिये एक दूतों से सम्मिलित कर सकते हैं। संघ को मुद्रा और शक्ति, व्यापार और सम्बन्धों के एक मात्र अधिकार प्राप्त है।

स्वाधी सेना नहीं रखी जाती। प्रत्येक केन्द्रीय में १०० सेना होते हैं। परेड फ़ौज का कार्य केन्द्रीय है, किन्तु आम फ़ौज के लिये नहीं। प्रत्येक स्थित मर को सेव्य-सेवा करना अनिवार्य है।

जन निर्माण कार्य एक केन्द्रीय विषय है। इसी प्रकार पुलिस, जंगलों और बोंबों पर केन्द्रीय नियंत्रण है। जल-शक्ति, फिर से कयल जंगल, समुद्री व्यापारमन संबंधी कायम, विज्ञान, मछली पकड़ना शिक्षा करना, जंगली जानवरों की रक्षा, रेलों संबंधी कायम, पेड़ों संबंधी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय—केन्द्रीय के वर्तमान हैं।

आधारभूत अधिकार—१—घर अन्त और परिवार संबंधी

कोई विशेष सुविधाओं नहीं । २—संघ के सदस्य विदेशियों से कोई मेट, पब्लिक इत्यादि स्वीकार नहीं कर सकते, ३—व्यापार की स्वतंत्रता सुरक्षित है—नमक, कार्बन और शराब को छोड़कर । ४—कैन्टन का प्रत्येक, नागरिक संघ का भी नागरिक होता । ५—राजनीतिक अधिकारों का उपयोग केवल एक कैन्टन में किया जा सकता है । ६—नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करने के लिये तीन महीनों का निवास आवश्यक है । ७—नागरिकता प्रदान करना एक संघीय विषय है । प्रत्येक नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है बशर्ते उसे अबोम्य पोषित न किया गया हो (अ) किसी अपराध में दण्डित होकर नागरिक अधिकार हिन जाने से, ( इ ) गम्भीर अपराधों में कारागार बंद पाने से, ( ए ) सार्वजनिक स्थान पर स्थायी बोज़ होने से, ( खो ) और अन्य स्वयं के कर्मून वा कैन्टन द्वारा उसका लर्वा ठठाने से इन्कार करने से । ८—आश्रित स्वतंत्रता है—पर इस की बाह में नागरिकता के कर्तव्यों को ठठाने से इन्कार नहीं किया जा सकता । ९—जैरुएट और इनकी कार्यवाही पर रोक लगी है । १०—नये धर्म के स्थापन और पाम्बरी लगे धर्मों को फिर से चलायाने की मनाही है । ११—विवाह की रक्षा की जाती है । १२—स्त्री को पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है । १३—विवाह से पूर्व दरमज समझाने विवाह होबाने के उपरान्त नियमित मानी जाती है । १४—कैन्टन प्रेस की स्वतंत्रता को गारन्टी करते हैं । १५—श्रद्धा के लिये कोई कन्धी नहीं बनाया जा सकता । १६—किसी भी राजनीतिक अपराध में मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता । १७—मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता ।

८

## जर्मनी

### आधारभूत और आम अधिकार

१—ज्वा—काया माल और मुनदता । अथ (१९३३ ई०) द्वादी गई है पुरानी राजशाही ज्वा । २—आगे से जर्मन वा विदेशी पर

नहीं दिये जा सकते । १—ग्यामास्यों और शिष्टा संस्थाओं में सभी विदेशी भाषाओं का प्रयोग करने की इजाजत है । ४—राजनीतिक विचारों और समुदायों को बनाने की स्वतंत्रता है । ५—संघीय राज्यों के सदस्य आपस में स्वतंत्रतापूर्वक संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । ८—अधिक संतानों वाले परिवार विरोध रहा जाता पाने के अधिकारी हैं । ९—नाजायज़ बच्चों को पाला जाना है और उनकी रक्षा की जाती है । १०—कुले ग्राम होने वाली सभायें करने के लिये चुनना बेनी होती है और उन पर रोक भी लगाई जा सकती है । ११—अफसरों के अधिकार—(क) अफसरों के विरुद्ध कोई रिमांड बिना उन्हें पदार्थ का अवसर दिये नहीं बढ़ाया जा सकता । (ख) सम्पूर्ण विवरण देखने को मिलते हैं । (ग) अफसरों को राजनीतिक समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है । १२—धर्म—सिवाय म्याम अथवा अर्द्धके संबंधी चुनना एकजिठ करने के कोई भी अपना धर्म बताने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । १३—धार्मिक संस्थाओं के संघों को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है । १४—शिष्टा—कला, और विज्ञानों की—निःशुल्क है और इनके सम्पादन के लिये नियम बने हुए हैं । १५—निजी शिष्टा संस्थामें भी राज्य के कानूनों के मातहत काम करती हैं । १६—शिष्टा का उद्देश्य चरित्र निर्माण नागरिकता, राष्ट्रीय भावना, और भाई-भारे की भावना फैलाना है । भाषा की प्रेरेतक्षपी और व्यक्तिगत कुशलता बढ़ाना भी उसका उद्देश्य है । प्रत्येक छात्र पदार्थ खोजने पर शास्त्र-विधान की एक पुस्तिका पाता है । धार्मिक जीवन की संमिट्टि किया जाता है जिससे मानव जीवन रहने बोम्ब बनाया जा सके—सम्पत्ति पर नियंत्रण है—भूमि पर नियंत्रण इजलिये किया गया है कि स्वयं पर और मित्रमयिता से गृहस्थी का काम चल सके ।

६

## सोवियत रूस

स्थानीय सरकार

१—कुन्या का टंग केवल गाँवों और मगरों में प्रचल है । १ •

व्यक्ति से कम जनसंख्या वाले गाँवों का सम्बन्ध गाँवों के साथ एक समूह बना दिया जाता है। नगरों में केवल कारखाने और बड़े गोदाम खुलने करते हैं। यह प्रतिनिधित्व ५५० व्यक्तियों के पीछे एक के अनुपात में होता है। वार्षिक चुनाव। सरकारों को मापत बुझाया जा सकता है।

२—बोसस्त सोवियत—१ गाँव के पीछे एक—इसका काम आम शासन कार्य करना है। ठाक में एक बार अविवेचन होता है लेकिन बेवस्तीनों की कम्प्लेंट्स अकसर होती रहती हैं।

३—बोसस्त काम्प्रेसे—आम सोवियतों की भुज्ज या बेहस्ती कॉम्रेस के सिने १०० के पीछे एक के अनुपात से डिपुटी मेकती है। अधिकतम संख्या १०० है। एक वर्कन विभाग है। जिनमें बुद्ध धर्म, शासन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, अन्न और स्वास्थ्य भी है।

४—ग्राम्तीय कॉम्रेस या गृहपरिषद—इसमें बोसस्त सोवियतों और नगरों से प्रतिनिधि आते हैं। बोसस्त से १० के पीछे एक डिपुटी और नगर से २०० मतदाताओं के पीछे एक डिपुटी आता है। अधिकतम संख्या १ है, १५ विभाग हैं, इनमें नये विभाग हैं ग्वान, डाक और तार और विशेष स्वाक-विभाग भी हैं जिसे एकत्र आखीनरी कमीशन कहते हैं।

५—प्रदेशिक कॉम्रेस या ओम्प्लास्ट—कॉम्रेस या तो स्वयं एकत्रीकृतिय काठस्थित द्वारा बुझाई जा सकती है या स्थानीय सोवियतों की मींग पर। यदि मींग करने वाले स्थानीय निवातियों के कम से कम एक तिहाई हो और यदि नगर की तरफ से मींग हो तो संख्या में आये हो। नगरों में सप्ताह में कम से कम एक बार और बेहस्ती में दो बार मिश्रण आवश्यक है। १५ दिन में एक बार रिपोर्ट देनी चाहिए, यदि दो रिपोर्टें न हो अथवा तो हटाना जा सकता है।

६—आल रशिया कॉम्रेस—इसमें नगर सोवियतों से ९,५०,०० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और ग्राम्तीय कॉम्रेस से १९,५०,०० निवातियों के पीछे एक प्रतिनिधि आता है।

राष्ट्रों के स्वतन्त्र संघ का एक सर्वोच्च प्रजातन्त्र है। समस्त सोवियत का अस्त कर दिया गया है। भूमि में व्यक्तिगत संपत्ति का अस्त कर दिया गया है। यह जनता को बिना 'धतिपूर्ति' के दे दी गई है। समस्त

जमल, धूमि के अन्धर के लमिज पदार्थ, अल शक्ति जानवर—आदर्श फार्म और सेना बाढ़ी को 'सार्वजनिक सम्पत्ति' घोषित कर दिया गया है। तृतीय कमिश्न ने शूनों की अस्वीकृत कर दिया और उसके बाद इस निश्चय की पुष्टि हो चुकी है। समस्त बैंकें सरकारको हस्तान्तरित कर दी गई हैं। काम करना प्रत्येक के लिये अनिवार्य है। मजदूरों को हकियत मिले जाते हैं। समाजवादियों की साल सेना ने शीघ्र को रोकने का बीड़ा उठा लिया है। गुप्त सम्पत्तियों को मालने से इन्कार कर दिया गया है।

तृतीय कॉमिश्न ने अपना क्षेत्र कुछ तक सीमित रखा है और अन्य प्रदेशों को इस बात की स्वतन्त्रता देदी है कि यदि वे चाहें तो सोवियत बनाकर उसके साथ सम्मिलित हो जाँय।

प्रतिनिधियों को वापस बुलाने ( Recall ) का अधिकार है।

सोवियत अधिकारियों की आम सम्मेलन का कार्य—

१—बड़े निर्देशों को कार्य रूप में परिचित करना।

२—राष्ट्रपतिक और आर्थिक जीवन के लिये व्यवस्था करना।

३—स्थानीय महत्व के प्रश्नों का निबटारा करना।

४—स्थानीय कार्यवाहियों को एक चुन में बाँधना।

१०

## जैकोस्लोवाकिया

ध्वजा—रबेत, लाल और नीली। राज्य भी जाती है, प्रजातन्त्र के प्रति बहादुरी—उसके कानूनों का पालन करना कर्तव्यो को यथा शक्ति और योग्यता के अनुसार पूरा करना।

११

## अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

राष्ट्रों के न्यायाधीश—छात राष्ट्रों में गवर्नरो द्वारा आजीवन के लिये चुने जाते हैं किन्तु सीनेट या लेजिस्लेटिव काउन्सिल की सम्मति

अन्तर्गत है। सार्वजनिक समियोग द्वारा इतना आ-सकता है। वीच राज्यों में एक निश्चित अवधि के लिये और बाद में जीवन भर के लिये होते हैं। चार अन्य राज्यों में व्यवस्थापिका सभा द्वारा एक छोटी या बड़ी अवधि के लिये चुन जाते हैं। छोटी में जनता द्वारा चुने गये हैं और एक में कम्यूनर के लिये। ब्रेटन १९०० पीछे से लेकर कम-कम है। विशेषताएँ हैं—

(i) कम ब्रेटन।

(ii) छोटा कार्य काष्ठ।

(iii) पार्टी लीडरों द्वारा चुनाव—इनके कारण इन पदों के लिये लोग उत्सुक नहीं रहते, राज्यों के व्यावसायिक पद में बड़ी-छोटी से नीचे समझे जाते हैं।

**सिविल सर्विस—**

बुगी और डाक—बैडानिक और कृषीविज्ञ अप्रसर—राज्य-कमिशनर—प्रेसीडेन्ट के साथ ही एक पदों को छोड़ देते हैं—यह पार्टी की छूट समझे जाते हैं और इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र के प्रति बलपूर्वक न होकर अपनी पार्टी के प्रति बलपूर्वक होते हैं। इन्हें पार्टी के कोष में चम्पा देना होता है और पार्टी के काम का पहला ध्यान रखना होता है, नहीं तो निकाले जाने का डर रहता है। न तो यह के बारे में कोई निश्चितता होती है और न तरफों के बारे में। सन् १८८९ ई० से कुछ सुधार हो गये हैं। सिविल सर्विस कमिशनर नियुक्त हो गया है—१९२१, जोकरियों इसके अंतर्गत आ पाई हैं। फिर भी राष्ट्रीय सरकार १९०,००० पर अब भी पार्टी के हाथ में रहते हैं। बैडानिकों को छोड़ कर अन्य सरकारी अप्रसर बोम्ब नहीं। एक सिविल सर्विस कमिशनर है जो ५००,००० तब की नियुक्तियों में लगभग १८ ००० नियुक्तियों से संबंध रखता है किंतु प्रेसीडेन्ट कितो भी व्यक्ति को इस अंश से निष्काश कर अलग कर सकता है।

**म्युनिस्पैलिटीयाँ**—दो प्रकार की हैं। (I) मेयर को नागरिकों द्वारा चुना जाता है; अवधि ४ वर्ष। व्यावसायिक और मजिस्ट्रेट की ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। मेयर तथा काउन्सिलरों को वैश्य मिलता।

है। काउन्सिलों के कहीं कहीं एक और कहीं दो भवन होते हैं। ( II ) कमेटी व्यवस्था—वो से छ- सदस्यों तक की एक काउन्सिल होती है—मूल बैठन दिया जाता है।

( I ) नगरों का शासन स्वयं नागरिक करते हैं—वह व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो 'शासन-परिषद्' बनाते हैं जिनको ऑब-पकताल के अधिकार रहते हैं। अगले वर्ष के अफसर चुने जाते हैं। ( II ) काउन्सी—यह ग्याव के विभाग ( क्षेत्र ) हैं। इनका शासन योकी अवधि के लिये चुने हुये अफसरों द्वारा होता है। काउन्सी काउन्सिल नहीं होती।

काउन्सिलों ( परिषदों ) का काम निरीक्षण का नहीं है। अफसर काम चलाते हैं—कामूनों से कर्तव्य निर्धारित है। उत्तर-मध्य के परिचामी राज्यों में प्रबन्ध जनता के हाथों में है। काउन्सी अफसर पार्टी के आचार पर रक्के जाते हैं।

राहों का शासन अलक्ष्य है। समीरों को दिलचस्पी नहीं। मिमित जनता रोधी से बड़ रही है और कोई कर नहीं है। नागरिक पार्टी-बाजी के शिकार हो जाते हैं। जनता के मिमित होने का कारण उनमें इतनी अधिक एकता की भावना नहीं रहती—आयरिश अर्मन, पोत स्वित्, इटेलियन, फ्रेच, स्वीडिश स्लाव मैथिल, एडिक्न मीक प्रेमिष्ठ, सीरियन, और पोलिश बहूदी। महाबिकार बिना योग्यता का ध्यान रखे दिया जाता है।

बदमाश लोग नगर के शासन और राज्य तथा रंग पर घीरे घीरे आधिपत्य बसा रहे हैं। वे अपने एक गिरोह बना लेते हैं या स्वयं 'बादशाह' बन बैठते हैं। शक्ति रेलवे बोर्डों और विधविधानों के हाथों में रहती है।

१२

## पोलिश प्रजातंत्र

आधारभूत अधिकार—यूमि को डुकके डुकक करके नहीं बाँटा जा सकता।



१३

## स्वीडन

जीवन, यश, मजदूरी, व्यक्तिगत और वास्तविक सम्पत्ति, पर की शक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता—सभी सुरक्षित हैं।

अभिमुख को क्षमा-प्रार्थना या दण्ड दोनों में से जुनम की छूट है।

विदेशियों को प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है ( बर्म शास्त्र का नहीं ), सेना में नियुक्त किया जा सकता है किंतु किसी की आवश्यकता नहीं चीनी जा सकता और आवश्यक पर दिया जा सकता है।

बिबो को पत्ररिबो के पर नहीं दिये जा सकते।

प्रत्यक्षीकृत माथरिक को समान अधिकार होते हैं, किंतु उसे काउन्सिल आफ स्टेट में स्थान नहीं मिल सकता।

बैरन ( Baron ) और काउन्ट ( Count ) की उपाधियाँ ही जाती हैं जो व्यक्तिगत और पैतृक होती हैं। साम अनिवार्य सैन्य सेवा का निवम है राजी से की गई मर्जी से बमाई गई एक स्थायी सेना मौ रहती है।

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि पहले से प्रकाशन पर निबंधन ( Censor ) नहीं होता लेकिन बाद में दण्ड दिया जा सकता है।

१४

## नार्वे

अपराधी वह कहने का अधिकार रखते हैं कि वे दण्ड भोगने का राजा से क्षमा-प्रार्थना करेंगे।

राजकुमार जब पर दण्ड नहीं कर सकते।

व्यक्तिगत दण्डना विहित पैतृक उपाधियों या गुणिवारों की अनुमति नहीं है।

स्टेडिंग विदेशियों को प्राकृतीकृत करने के लिये नियम बनाती है ।  
राष्ट्रीयता—सरकारी पद केवल राष्ट्रीय नागरिकों को ही दिये जाते हैं—  
को राष्ट्र-भाषा बोलते हों, राष्ट्रीय भाता-पिता की श्रुतान हों—अपुन  
अगम के समय राज्य की प्रजा हों अथवा उस समय विदेश में हों किन्तु  
अन्य राज्य के नागरिक न हों और इस वैधानिक कानून के परम्परात्मक काम  
से कम राज्य में १० वर्ष तक रहे हों वा स्टेडिंग द्वारा उनका प्राकृती  
कराय हो गया हो ।

अपवाद—अध्यापक (विश्वविद्यालय और कालेजों के), डाक्टरी  
अध्वर और कोन्सुल ( Consuls ) । आम आचारमूढ अधिकारों  
को माना जाता है । कोई अर्ल अथवा बैरन नहीं है । और न भविष्य  
में कोई बायीर ही जा सकती है ।

एक बार अनिवार्य रक्षा के लिये हुलाका दिया जा सकता है ।

ऐसेन्यतिक हूवर बर्म प्रचलित है—जैस्यूट्स ( Jesuits ) को  
सहन नहीं किया जाता ।

स्टेडिंग पौन विराज-निरीधर नियुक्त करता है ।

१५

## आस्ट्रिया

संघ के आध्यात्मिक का होना एक 'कोर्ट आफ एक्जल्ट'   
नीच नेशनल काउन्सिल के मातहत होता है । उसका प्रेसीडेन्ट नेशनल   
काउन्सिल की 'मुख्य कमेटी' के प्रस्ताव पर चुना जाता है—वह किसी   
प्रतिनिधि सरपा का सदस्य नहीं होना चाहिये और न मत पौन वर्षों में   
होना चाहा कोई मंत्री ही होना चाहिये । नेशनल काउन्सिल के प्रस्ताव   
पर हस्ताक्षर जा सकता है । संघ का प्रेसीडेन्ट अपधरों को नियुक्ति   
करता है ।

शासकवर्गीय न्यायालय—इसमें प्रेसीडेन्ट होता है । आध   
न्यायाधीशों को संघ सरकार नामजद करती है और पीपुल्स कमिशनर   
स्वीकृति देता है । रोष आध न्यायाधीशों को 'मुख्य कमेटी' देकर

काठस्थल की सहमति से निपुक्ति करती है। इस व्यावसायिक कार्य-शासन और वैधानिक गारन्टीयों के संघर्ष में अंतिम अपील मुनना है किन्तु इस संघर्ष में जगनेवाले समय को कम करने के लिये कानून बनाना सा संभव है किन्तु यह कार्यवाही साधारण व्यावसायिक या वैधानिक न्यायालयों अथवा सम्मिलित बोर्ड से सम्बन्धित विषयों में नहीं की जा सकती।

### स्थानीय सरकार

कम्यून स्वामीन आर्थिक इकाई है। १,००० या कम जनसंख्या होने पर स्थानीय और २,००० से अधिक होने पर जिला या शहरी कहलाता है। स्वतंत्र राजस्व, कर और आर्थिक कार्य होते हैं। वह सम्पत्ति को ले सकता है और रख सकता है। स्थानीय—“एक बाजार के काम के लायक पुष्पित—इसका स्थानीय सुरक्षा के लिये होता है।

## १६

## स्लावों, कोटों तथा सर्वों का राज्य

### आचारसूत अधिकार

समुदाय बनाने का अधिकार—बोलने—देखकी—टैलीग्राफ और डाक संबंधी अधिकार हैं।

युद्ध के समय वैयक्तिकता है अधिकारों को मंजूर किया जा सकता है। राजनीतिक अपराधियों के लिए मृत्यु दण्ड ठका दिया गया है किन्तु राजद्रोह और क्रूर के अपराधों में अब भी यह दिया जाता है।

## १७

## ऐस्थोनिया

### आचारसूत अधिकार

कोई कानून वर्ग विभाग नहीं है। कोई भी अपराधियों देशी या विदेशी नहीं मानी जाती। प्रतिक्रारी के कानून बोलने समय के लिये ठका

का लागू नहीं किने जा सकते। प्राथमिक शिक्षा त्रि-मुक्त और अनिवार्य है। भाषण की स्वतंत्रता है पर नैतिकता और देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये कुछ रोकें लगी हुई हैं। बाक़ तार रेडियोघेन के उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं विधान स्थापनाओं की आजा के। अरर संवक कतिबो को अपनी सरहति की उपति के लिये अलग संस्थापे बनाने की अनुमति है। अररसंस्थाओं की भाषाओं का प्रयोग बर्जित नहीं किन्तु राष्ट्र भाषा अवौररि है।

जर्मन-रक्षिमन-स्वोदित बालने की या लिखने की व्यवस्थापिका समा और स्थापनाओं में लूट है।

• १८

## इंगलैण्ड

### आधारभूत अधिकार

“ब्रिटिश प्रजा” शब्द के अन्तर्गत व सभी व्यक्ति आ जात हैं जो राजा को मानते हैं। यह शब्द केवल ब्रिटिश द्वीपसमूहों के निवासियों तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक संस्थाओं में पलने वाले अधिकारों की कोई निवास योग्यता नहीं होती—न कोई अयोग्यता ही होती है।

: १९

## बेल्जियम

### आधारभूत अधिकार

नागरिकता के कानून हैं—प्रकृतीकरण, कबल जब पूर्ण होता है तो, विदेशियों को समान राजनीतिक अधिकार दे देता है।

सभी बेल्जियम-निवासी समान हैं—अपभ्रगत स्वतंत्रता सुरक्षित है—पर से मही भुजा जा सकती—तत्प्राप्ती नहीं ली जा सकती और न कानून के विरुद्ध सम्पत्ति ही लीनी जा सकती है। सम्पत्ति और अग्रभिक

अधिकारों को एकदम पूरा नहीं होना जा सकता। कार्मिक स्वतंत्रता और पूँजा की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सामाजिक विवाहों के पूर्व तथा कार्मिक कृत्य किये जाने चाहिये—निजी भिन्नताओं के प्रति कोई रोक नहीं है।

मेस स्वतंत्र है—किसी समय कोई निर्बन्ध नहीं लगाया जाता—यदि दोस्तक के बारे में पता हो तो सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता पर अभिभोग नहीं लगाया जाता।

कुछ काम समा करने की स्वतंत्रता है, पर पुलिस के नियमों को मानना होता है—अधिकारों के सिरे निवेदन-पत्र देवे की छूट है—संयुक्त निवेदन-पत्र केवल कानूनी ढंग से संगठित संस्थाओं ही दे सकती है।

वेस्विन को भाषा के उपयोग में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। समस्त अधिकार राष्ट्र से प्राप्त होते हैं।

ध्वजाः—लाल पीली और काली।

राज्याभिषेक—वेस्विन शेर—एकता में ही शक्ति है।

२०

## स्पेन

कैस्टेखियन भाषा है।

बोवचा कर ही है कि स्पेन कुछ को राष्ट्रीय नीति का आज नहीं मानता।

अंतर्राष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय कानूनों का एक भाग माना जाता है।

माँठ मिखाकर राजनीतिक और शासन प्रवेश बना सकन है बराते कि उसका अधिकार-पत्र उसकी सरकारी संस्थाओं के बहुमत द्वारा पेश किया जाय वा मत-विभाजन में दो-तिहाई के बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाय और दो-तिहाई मत-दाताओं द्वारा मान लिया जाय और कोर्टों द्वारा उसके लिये सहमति दे दी जाय।

कोई मेर-भाष नहीं है और कोई राज-धर्म भी नहीं है।

आम आचार मूल अधिकार दिये गये हैं।

परिवार, आर्थिक व्यवस्था, किराना, कलायें, और संस्कृति सभी की सुरक्षा का प्रयत्न है।

२१

## डेनमार्क

पन्द्रह सदस्यों की एक कमेटी हाग जिसे व्यवस्थापिका-सभा के दोनों भवन चुनते हैं) चार दिवस निरीक्षण जुने आते हैं। ये कागज़ों को देसभास के लिये माँग सकते हैं और इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि ये कागज़ सच्चे हैं।

पुस्त्य कियों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

राजधर्म—ईबैंगलिक्न लुथरेन—राज्य इस धर्म को बलाता है।

कानून के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जा सकता है—न सेना को इधर उधर भेजा जा सकता है—न कोई सम्झौते किये जा सकते हैं—न भूमि हीरी जा सकती है।

धार्मिक कारखों से न तो किसी के अधिकार कम होते हैं और न वह कर्त्तव्यों से ही छुटकारा पा सकता है।

नागरिकों को कुछ शर्तों पर राज्य से सहायता दी जाती है

निर्धन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशन कर कर सकता है किन्तु दरख भी पा सकता है।

कोई निर्बंधन नहीं और न कोई रोक लगाने वाले कानून ही हैं।

सरकार किसी भी समुदाय को स्थायी रूप से भंग नहीं कर सकती।

२२

## इटली

प्रान्त के समान ही है—केन्द्रीय करण—मंत्रियों द्वारा निरीक्षण होता है—२२ वर्षों में—व्यवस्था में अंतर है। प्रत्येक में प्रीपैक्ट होता है जो मंत्रियों की सिफारिश पर राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है—मीन्चे के अफसरों को सरकारी बेकर प्रीपैक्ट पद दे दिया जाता है। राष्ट्रीय सरकार का स्थानीय एजेन्ट होता है। राजनीति में सक्रिय भाग

होता है—युनाय के परिषदों के अनुसार उसकी उन्नति अथवा अवनति हो जाती है—प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष (एक तरह का प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल) उसके काम में सहायता करते हैं।

प्रत्येक प्रान्त में एक शासन परिषद है जिसकी बैठकें महीनों होती हैं—प्रत्येक के समक्ष वह एक कमीशन नियुक्त कर देती है। किन्तु प्रीफैक्ट राष्ट्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रीफैक्ट और प्रान्तीय परिषद मिलजुल कर काम करती है।

जिले और कम्पून है—शहर, गाँव और गाँव विषय में कोई कानूनी मेर नहीं है—सभी कम्पून कहलाते हैं। मेयर तीन वर्ष के लिये चुना जाता है—उसे हटाया नहीं जा सकता—लेकिन प्रीफैक्ट उसे विहायते देता है और इस प्रकार वह दो स्वामियों का सेवक होता है। स्थानीय व्यवस्था में पार्टीकन्टो बहुत बलवती है।

• २३ :

## जापान

### आधारभूत अधिकार

१५ बाराधों में मिलाए गये हैं—शासन विधान में नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पूर्ण गारन्टी नहीं है—लेकिन कानूनों ने इस कमी को पूरा कर दिया है।

अधिकार का विस्तार प्रेस और भाषण की स्वतन्त्रता। शान्ति सन्धियों और राजनीतिक सङ्घर्ष बनाने के अधिकार—क्षेत्रीय कानून में सुधार—वह शान्तिजन्य अधिकारों के विकास के परिणामक हैं।

पार्टी व्यवस्था —इन्दीरी (Indiri) के पार्लो और केन्द्रित है जो कि केन्द्रीकृत व्यवस्था का अन्वेषण है किन्तु अब व्यक्तियों का स्थान नीतियों होती जा रही है। -

## मैक्सिको

### आधारभूत अधिकार और नागरिकता

( १ ) सभी व्यक्ति निम्न सुरक्षाओं का उपयोग करते हैं । ( २ ) दास-प्रथा की मनाई है । बाहर से आने वाले दास राज्य में आकर स्थायीन हो जाते हैं । ( ३ ) शिक्षा निशुल्क है किन्तु धार्मिक नहीं । ( ४ ) कोई धार्मिक तरिका अथवा धर्माधिकारी प्राथमिक स्कूलों को स्थापित नहीं कर सकता; और निम्न प्राथमिक स्कूल केवल अधिकारियों की सहमति पर खोले जा सकते हैं । ( ५ ) सभी व्यक्ति किसी भी कानूनी पेशे को अपनाने में स्वतन्त्र हैं । ( ६ ) कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून से और किसी भी तरह अपने परिभ्रम के फलों से वंचित नहीं रहता जा सकता । ( ७ ) पेशों के लिये स्थायी कानून के अनुसार दिये जाते हैं । ( ८ ) समस्त भ्रम स्वेच्छा निर्भर हैं । ( ९ ) किन्तु निम्न सेवाएँ अनिवार्य हैं ( अ ) सैन्य सेवा ( आ ) नदी कार्य ( इ ) स्थानीय चुनावों में अफसर पद ( ई ) चुनाव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेवा ( ए ) राज्य ऐसे किसी राज्नीनामे या समझौते की अनुमति नहीं देता जो ( i ) मतभूरी ( ii ) शिक्षा ( iii ) निषेधित धार्मिक पदों या ( iv ) स्वेच्छा से दिये गये उपचार के आधार पर स्वतन्त्रता को कम करते हैं । ( १० ) कोई भी भ्रम-समझौता एक पक्ष के विरुद्ध या उसके हितों के खिलाफ एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं हो सकता न उसके द्वारा किसी भी नागरिक अधिकार को छोड़ा, कम या ह्रास किया जा सकता है । ( ११ ) समझौते के मंग करने पर कोई राजा नहीं दी जाती केवल शक्तिपूर्ति की जाती है । ( १२ ) शोषण स्वतन्त्रता को मंग नहीं दिया जा सकता । ( १३ ) किसी अन्तराष्ट्र के कारण मंग को ह्रास नहीं किया जा सकता । ( १४ ) आन्दोलन मेकने का अधिकार — शान्तिपूर्ण और आदरसुक्त हो तो उसका उच्च अफसर के द्वारा दिना जना जायिग । ( १५ ) किसी भी राज्य समुदाय को विचार विनिमय का अधिकार नहीं है । ( १६ ) किसी भी वैधानिक और शान्तिपूर्ण स्वभाव के होने में कोई रोक नहीं ।



( १७ ) सिवाय पुलिस नियमों के कानून द्वारा शस्त्र रखने में कोई बकायद नहीं है । ( १८ ) कुलीनता की उपाधियाँ नहीं बाँटी जा सकती । ( १९ ) निजी कानूनों या विशेष अदालतों द्वारा अभियोग नहीं चलाये जा सकते । ( २० ) कोई विशेष सुविधाएँ या भेदन नहीं है कानून द्वारा केवल मुद्रास्फ़ा निर्धारित है । ( २१ ) ऐम्ब शिक्षा केवल मैक्सिमो के नागरिकों तक ही कर्जा के साथ सीमित रखी जाती है । ( २२ ) कानून बीती बातों पर उलटफेर लागू नहीं किये जा सकते । ( २३ ) किसी व्यक्ति का जीवन उसकी सम्पत्ति या स्वतन्त्रता को बिना पहले से बने हुए कानूनों के अनुसार अभियोग चलाये हरश नहीं किया जा सकता । ( २४ ) ऐसे अपराधियों के सम्मुख में जो अपने देश में गुनाह हो अन्य देशों से अपराधी प्रत्यर्पण ( Extradition ) के लिये तय्य नहीं की जा सकती । ( २५ ) कानूनी तरीके के अतिरिक्त किसी भी तरह किसी को व्यक्तिगत हानि नहीं पहुँचाई जा सकती । ( २६ ) सहायी नहीं होती न कर्म के लिये किसी को कम्पीण्ड ही भेजा जा सकता है । ( २७ ) सिवाय ऐसे अपराधों के लिये जो बूधरे व्यक्तियों को थोड़ा पहुँचाने से सम्भव रहते हैं और बहक के बोझ हैं और किसी मामले में पहले से ही बन्दी नहीं बनाया जा सकता । इस प्रकार के बन्दी-गृहों के स्थान बेशर्त से अलग होते हैं । ( २८ ) संघ और राज्यों की सरकारें इस आधार पर कसबास संघीय व्यवस्थाएँ और उपनिवेशों को संघठित कर सकते हैं कि परिश्रम तुल्य का माध्यम है । ( २९ ) किसी भी व्यक्ति को अपने ही विद्वत्ताधी होने के लिये नहीं कहा जा सकता । ( ३० ) बन्दी-जीवन का समय भी दण्ड के माग की तरह मान कर गिन लिया जाता है । ( ३१ ) राजनीतिक अभियोगों के लिये भृत्यदण्ड नहीं दिया जा सकता । ( ३२ ) किसी भी औद्योगिक समूहों, एकाधिकारियों को कर से बरी नहीं किया जा सकता; न उद्योग की रक्षा का आभार लेकर सिवाय मुद्रा, कृषीराष्ट्र, मोटों के अन्य वस्तुओं के आयात पर रोक नहीं लगाई जा सकती । ( ३३ ) ऐसी लोक न्याय की, जिसके परिणाम स्वयं मुख्य बहुत अधिक बड़ जाय, अनुमति नहीं है ।

टिप्पणी—मजदूर तथा और सहकारी समितियों को एकाधिकारी नहीं समझा जाता ।

निवास और जन्म—( I ) मैक्सिकन माता पिता से उत्पन्न बच्चे चाहे वे देश में उत्पन्न हुए हों या विदेश में मैक्सिकन नागरिक समझे जाते हैं । विदेशी माता पिताओं की सम्पत्ति वसूल हो जाने के एक वर्ष के भीतर मैक्सिको की नागरिकता के लिये आवेदन करने पर नागरिक घोषित कर दिये जाते हैं । ( II ) नागरिक-करण—वे व्यक्ति जो लगातार पाँच साल तक देश में रहे हों और ईमानदारी से जीविकोपार्जन करते हों और ऐसे व्यक्ति को मिश्रित रक्त के हों यदि संवीकृत नागरिक बनना चाहें तो उनका नागरिक-करण कर लिया जाता है ।

---

: ७ :

## राज्य और उद्योग तथा शासन- विधान में परिवर्तन

१ :

### आयर्लैंड

राज्य और व्यवसाय तथा सन्धि के अधिकार—

पेरिस, बर्लिन और कैबोविक पोप के साथ सम्मेलन ।

शासन विधान में संशोधन

सन्धि की शर्तों के अन्तर्गत ओ संशोधन किये जायें उन पर मत-  
गणना की जाती है । या तो समस्त मत दाताओं के बहुमत से उन्हें  
मंजूर किया जाना चाहिये या आठे जाने वाले गोटों से ३ के बहुमत से  
मंजूर किया जाना चाहिये ।

कौंसिल ने श्री बैलर के घर से कि कहीं वह उसे शपथ को उड़ा देने  
के प्रश्न को लेकर संसद में उसे १६२९ में रद्द कर दिया । अन्तर्गत की  
पहल द्वारा संशोधन पेश किये जा सकते हैं जिनको दो सप्ताह के अन्दर  
पार्लियामेन्ट की मंजूरी पड़ता है । यदि पार्लियामेन्ट ऐसा न करे तो  
७५,००० मत दाताओं के हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र जिसमें  
१५ • हस्ताक्षर एक निर्वाचन-क्षेत्र से होने चाहिये, पार्लियामेन्ट को  
बाध्य कर देता है कि या तो वह स्वयं संशोधन कर दे या ठीक  
प्रस्ताव को जनमत-गणना के लिये भेज दे ।

२ •

## कैनेडा

सन्धि अधिकार

कैनेडा के सम्बन्ध जोड़ियों और वेरिज से है ।

शासन विधान में परिवर्तन

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ही कर सकती है । यदि कैनेडा की पार्लियामेन्ट चाहे तो ऐसा शीघ्र कर देती है ।

• ३

## आस्ट्रेलिया

शासन विधान में परिवर्तन

राज्य के किसी मन्त्र प्रतिनिधियों की सभा से सम्बन्धित या उसकी सीमाओं से सम्बन्धित मामलों में पहल बोट देने वाले मन्त्रालयों के बहुमत से स्वीकृति मिल जानी चाहिये ।

१ - वैधानिक संशोधन दोनों मन्त्रों द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिये या किसी एक मन्त्र द्वारा तीन मास का अवसर देकर उसे दो बार पास कर देना चाहिये ।

२ - उत्तरदायक वह मन्त्र को जाना है और फिर जनमत गणना के सिद्धे ।

३ - राज्यों के बहुमत को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

• ४

## दक्षिणी अफ्रीका

यूनिवर्स में तब जगह निर्वाच व्यापार होता है ।

समि अधिकार—वाशिंगटन रोम और हेम के साथ सम्मान है।

हर्जोग का दावा था कि ओपीनियम के पाठ पूर्ण राजसत्ता है और उसे साम्राज्यवादी युद्धों में उद्वेग रहने का अधिकार है।

दक्षिणी अफ्रीका की पार्लियामेंट कुछ सीमाओं के अन्दर साधारण हथ से संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। विशेष मामलों में दोनों भक्तों की संयुक्त बैठक आवश्यक होती है और तत्परचाह दोनों के दो विशाई के बहुमत से उन्हें पास करना होता है।

राष्ट्रिय विधान १९२६ में संशोधित हुआ। उत्तमाशा अन्तरीप के अतिरिक्त कहीं पर एशिया निवासी उद्वेग नहीं हो सकते।

५ .

## न्यूजीलैण्ड

आस्ट्रेलिया के संघ में इस दर से सम्मिलित नहीं हुआ कि वह उसके विरुद्ध उद्वेग नहीं लगा सकेगा। मुमकिन बहती हुई आज दर वह जाता है—१ ०० पौंड पर एक वेन्स प्रति पौंड से प्रारम्भ होकर १६६००० पौंड पर पहुँच कर वह दर सात वेन्स हो जाती है। अनुप स्थित मासिकों को १०/८० कर अधिक देना होता है।

पहले देशों का प्रबन्ध तीन सदस्यों का एक बोर्ड करता था। अब एक मन्त्री करता है।

ओपरटर जेब लनिज पदाधों के मोठ कोषको की खाने (जीवन और आय का बीमा—आव अधिकतर कम्पनियों द्वारा किया जाता है) कितानों की उद्वेग दर पर कर्ष मिलता है। पर बनाने, अक्षयक्ति और जंगलश्र के मामलों में सहकारी संस्थाओं को उद्वेगता हो जाती है।

६ .

## फ्रांस

दोनों भवन अक्षय प्रस्तावों द्वारा, जो पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिये वैधानिक सुधार की आवश्यकता बतला सकते हैं। तत्परचाह ने

मिलाकर संशोधन करते हैं। यह कानून नेशनल असेम्बली द्वारा पुरो-  
बहुमत से पास होना चाहिये।

प्रजातन्त्रसमक शासन नहीं बदला जा सकता।

७

## स्विट्ज़रलैण्ड

नागरिकता - स्विट नागरिकता का दावा कोई भी ऐसा व्यक्ति  
कर सकता है जो किसी कैन्टन के कम्पून का निवासी हो। प्रत्येक कम्पून  
को इस संबंध में नियम बनाने की स्वतंत्रता है।

शासन विधान में परिवर्तन—

समपूर्ण परिवर्तन—यदि एक भवन चाहे और दूसरा न चाहे—या  
५००० मतदाता मौंग करें—तो संशोधन का प्रश्न जनमत-निर्णय के  
सिने मेम दिया जाता है। यदि बहुमत चाहे, तो संशोधन-कार्य के लिए  
दोनों भवनों का नया चुनाव होता है।

अंशतः संशोधन—जनता की पहल से या साधारण ढंग से संघ की  
व्यवस्थापिका समा कर सकती है। यदि कई संशोधन हो तो उनके लिए  
अलग अलग मौंग की जानी चाहिए। यह मौंग या तो आम दंग से  
रक्ती जा सकती है या बाकायदा विस बना कर मेमों का सकता है।

संशोधन सभी लागू होता है जब नागरिकों और राज्यों का बहुमत  
उसे स्वीकार करे। चाहे कैन्टनों का आधा मत होता है।

८

## जर्मनी

जर्मन के व्यापारिक अदालत एक बहुत बड़े समुदाय बड़े के पैमाने पर  
है। जर्मनी की राजनीतिक सीमाएँ और तट पर सीमाएँ एक हैं।

तट-पर और भू-मी का प्रत्येक रोज के हाथ में है किंतु पत्थरों के  
हित का ध्यान रखता जाता है।

ग्राम ऐसों का राष्ट्रीयकरण करके एक-सी आवागमन-सुवस्था स्थापित कर दी गई है।

**शासन विधान में संशोधन—**रीजिस्ट्रार के ३ के बहुमत से होता है। उसमें न्यूनतम उपस्थिति दो-तिहाई सदस्यों की होनी चाहिए। जहाँ जहाँ इनका निर्णय जनमत-निर्णय से होता है, वहाँ मत-व्यक्तियों के बहुमत की एक पक्ष में होनी चाहिए।

बकि रीजिस्ट्रार के बिना सहमति के संशोधन करने का निर्णय करता है और रीजिस्ट्रार को सप्ताह के भीतर नये चुनावों की मींग करता है तो प्रेसीडेंट उसे सब तक जागू नहीं करता जब तक चुनाव के बाद फिर निर्णय न हो जाय।

• ६

## सोवियत रूस

**कारमिस्त्रोफ़ आफ़ सेबर एण्ड डिप्लोमैट्स—**

एक प्रकार का मंत्रिमंडल है जिसका कार्य आर्थिक और लेबर रिपब्लिक का व्यवस्थापन और उन विभागों के कमीशनरों का काम पर नियंत्रण रखना है जो नीचे काम करते हैं; जैसे राज्य की आर्थिक योजना और राज्य के चुनाव कमीशन। वे अनेकों छोटे-बड़े कमीशनरों की रिपोर्टें देखती हैं। जो निर्णय होते हैं वे कमिशनरों द्वारा कॉमिन्स की कार्य-समिति द्वारा लोक-मत की कॉमिन्स को भेजे जाते हैं और उन्हें देख कर कमीशनरों की परिषद और उन्नत एक्जीक्यूटिव कमेटी ही कहल सकती है।

**शासन विधान में संशोधन—**

७ बी, ८ बी, ९ बी कॉमिन्सो ये (१९१९-२१ में) आकाश्यों से बेध-निक परिचयन किये।

**विशेष—**प्रीसीडिन्स को पीपुल्स कमीशनरों की परिषद के निर्णयों को मानने, पंख कर देने, राज देवे का अधिकार है। उन्नत एक्जीक्यूटिव कमेटी पुनर्निर्धार करती है।

**टिप्पणी—**सोवियत के विधान का मार्च १९१९ में सामूल-नूत परिवर्तन हुआ। नया शासन विधान 'रदालिम शासन विधान' कहलाता है।

१०

## सैकोस्लोवाकिया

युद्ध घोषणा और वैधानिक संशोधन—

इनके लिये प्रत्येक मकन में समस्त सदस्यों के १ के बहुमत की आवश्यकता होती है।

११

## पोलिश प्रजातंत्र

शासन विधान में परिवर्तन—साधारण बहुमत द्वारा दोनों भवनों की सम्मिलित बैठक द्वारा होता है, किन्तु विधान के प्रथम १० वर्षों में केवल बाइट का १ बहुमत ही संशोधन कर सकता है।

१२

## अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

साधारणभूत अधिकार

बिना दसह पाये बन्दी बनाने को रोकने वाले आकांक्ष मंजूर नहीं किये जा सकते।

कुलीनता की उपाधियों नहीं दी जा सकती।

दासता या अन्य अनजाने लग जाने के बच्चों को नहीं माना जाता।

प्रथम ११ संशोधन साधारणभूत अधिकारों से संरक्ष रखते हैं।

कानून में कांग्रेस द्वारा नागरिक अधिकारों को छीनने के विरुद्ध आदेश है और य ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं जो समझौते के अन्तर्गत से मुक्ति दे दें।



### नागरिकता

नागरिकता के उत्पत्ति मताधिकार नहीं है। मताधिकार के नियम राज्य बनाते हैं। इसके अर्थ यह हुए कि बिना राज्य में मताधिकार पाने की कोई व्यक्ति प्रेसीडेंट या कॉंग्रेस का सदस्य हो सकता है—क्योंकि विधान के अनुसार कोई भी सम्भवतः नागरिक प्रेसीडेंट हो सकता है और कोई भी नागरिक कॉंग्रेस का सदस्य।

### राज्य विधान में परिवर्तन :

जब भी दोनों घरों में १/३ के बहुमत से मॉग हो, या १/३ राज्य परिवर्तन के लिये कन्वेंशन की मॉग करें और इस प्रकार परिवर्तन के लिये प्रस्ताव हो और १/४ कन्वेंशन उसे स्वीकार कर लें। किंतु किसी भी राज्य को सीनेट के उसके समान प्रतिनिधित्व से, बिना उसकी सह मति के बंधित नहीं किया जा सकता।

इस कॉंग्रेस के कन्वेंशन के प्रस्ताव द्वारा; १/३ राज्यों की व्यवस्थापिका समारोहों की प्रार्थना पर और १/४ की स्वीकृति देने पर।

ऊपर के समान प्रस्तावित किंतु राज्यों के १/४ कन्वेंशनों द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।

वैधानिक उत्सोचन अपेक्षाकृत बहुत कठिन है।

अभी तक आम कन्वेंशन नहीं बुलाये गये।

पार्टी-संघर्ष—प्रत्यक्ष १ पार्टी-अमेरिकियों को खोदना।

२—कन्वेंशनों के लिये पार्टी-लेडीगेटों का चुनाव। ३—पार्टी के स्थानीय काम-काज करना।

१६ •

## स्त्रियों, सबों, कोटों का राज्य

### वैधानिक परिवर्तन

इसके लिये पहले राजा या असेम्बली द्वारा होनी चाहिये—व्यवस्थापिका समा औरम भंग कर दी जाती है और ४ माह के भीतर उस

का पुनः संगठन हो जाता है—नई व्यवस्थापिका समा शासन विधान पर विचार करने के पश्चात् फिर मग हो जाती है और उसका फिर पुनर्संगठन होता है ।

१४

## स्वीडन

राज्य के बैंक रिजर्वों की गारंटी में हैं । राज्य इसके प्रबंध के लिए कमिश्नर भेजता है ।

केवल वही नोट प्रचलित कर सकता है ।

शासन विधान में परिवर्तन—

परिवर्तन के लिये पार्लियामेंट को मंग करना होता है और वैधानिक प्रश्न को लेकर चुनाव लगा जाता है और नया मन्त्र एक वैधानिक सत्रोत्सव की तरह भी काम करता है ।

इसके अतिरिक्त एक निश्चित क्षेत्र और विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है ।

१५

## नार्वे

शासन विधान में परिवर्तन—

प्रस्तावों को स्टोरिंग की पहली या दूसरी बैठक में भेजना होता है । उस पर अगले चुनाव के पश्चात् पहली या दूसरी स्टोरिंग में विचार हो सकता है यदि संशोधन शासन विधान की भावना के प्रतिकूल न हो । स्टोरिंग की १ की सहमति होनी चाहिए ।

: १६

## आस्ट्रिया

शासन विधान में परिवर्तन—

संशोधन—कोरम ३। उपस्थित सदस्यों के २ के पक्ष में मत मिलने चाहिए, यदि फेडरल कांस्टिट्यूशन या नेशनल कांस्टिट्यूशन इसे चाहे।

वर्तमान शासन विधान में वर्तमान कानूनों द्वारा संशोधन किया जा सकता है यदि इसका प्रभाव संघ के विधान पर न पड़े (उपस्थिति-१, १ का अनुमति)—और उनका पुनर्निर्माण १ सत्र में हो जाना चाहिए।

• १७ •

## इंग्लैण्ड

शासन विधान में परिवर्तन—

साधारण कानून बनाने की तरह ही संशोधन भी किए जा सकते हैं।

: १८

## बेल्जियम

शासन विधान में परिवर्तन—

एक्सेम्प्टी के समग्र नैदानिक परिकल्पना मही हो सकते—यहसे व्यवस्था-मिका समा की घोषणा की आवश्यकता होती है कि संशोधन निश्चित है।

अनुरोध होने पर मंग कर दिये जाते हैं और वो महीनों में उनका पुनर्निर्माण हो पाता है और उनकी बैठकें जुलाई काठी हैं। कारा की अनुमति पर वे ठस पर विचार करते हैं और निर्णय करते हैं। कोरम ३ है। संशोधन के प्रस में ३ की राई जानी चाहिए।

१६ •

## डेनमार्क

शासन विधान में परिवर्तन—

यदि दोनों मन्त्रों की त शोधन के संवन्ध में सहमति हो और यदि सरकार उसे चाहे तो दोनों मन्त्रों के मने युनाय साय साथ कराये जाते हैं और यदि नई रीसरचिंग बिज पास कर देती है तो यह फास्कास्कीन के मतशाताओं के निर्णय के लिए ३ माह के अन्दर भेज दिया जाता है।

यदि ४५ फ्री सही मतदाता और बास्व में मतदान देने वालों का बहुमत जलते सहमत है और राजा अपनी चाही स्वीकृति इस पर दे देता है, तो यह कानून हो जाता है।

• २

## मैक्सिको

कर्तव्य—

( १ ) बच्चों और आश्रितों को जिनकी आयु १५ वर्ष से कम है उन्हें अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये भेजना होता है।

( २ ) राज्य और भूमि की रक्षा के हेतु नियन्त्रण रक्षा-दल में भरती होना और सेवा करनी होती है।

( ३ ) और स्थानीय शहरों को कर और राशें देने होते हैं।

( ४ ) भूमि-धरों और सम्पत्ति की सूची में नाम देना होता है और मत दाताओं की सूची में भी नाम लिखाना होता है, प्र वैयक्तिक रक्षा दलों में भरती होना पड़ता है, धार्मिक युनायों में योग लेना होता है। राज्य के प्रति संघ के पदों पर कर्तव्यों का पालन करना होता है जिनके लिये वेतन मिलता है और वाउन्सिलों और स्पूनिस्पैक्टियों और सूरी पर काम करना होता है।

## अधिकार—

(१) रिवायतें कमीशनरों और सरकारी पदों को देते समय जहाँ नागरिकता का होना अनिवार्य नहीं मैक्सिकन, मिवासियों को पछ्छ किया जाता है।

(२) किसी भी विदेशी को सेना, पुलिस या शान्ति कानून के तहत जनिक सुरक्षा विभाग में नहीं लिया जाता।

(३) नाविक सेना में केवल अन्य से ही मैक्सिकन ही लिये जाते हैं।

(४) विदेशियों को देश से निष्कात्ता या छुटाया है।

(५) कोई भी विदेशी देश के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

(६) मैक्सिको की नागरिकता २१ वर्ष की आयु होने पर दे दी जाती है वरुन्त वह ईमानदारी से जीविकोपार्जन करता हो। इससे निम्न विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं—(अ) सार्वजनिक पद, (आ) सार्वजनिक कार्यों के लिये समा करने का अधिकार, (इ) सेना में नौकरी, (ई) आभेदन मैकने का अधिकार।

(७) विदेशी राज्य में नागरिकता ही जामे पर मैक्सिको की नागरिकता जाती रहती है। वह या तो खुले आम विदेशी सरकार की सेवा करने पर होता है अथवा अन्य मतों के अधिकारियों के सामने अपने विचार स्थिर न रखने से।

(८) नागरिकता के अधिकार और विशेषाधिकार निम्न कारणों से संवृत्त किये जा सकते हैं—

(अ) कर्तव्यों का पालन न करने से—अन्य कारण के अभाव में वह अधिकार भी एक राष्ट्र के लिये संवृत्त किये जा सकते हैं।

(ब) दृष्टिगत होने पर या त्याग से बचने के लिये मागने पर।

(६) स्त्रियों को शारीरिक काम से काफ़ी छुट्टी मिल जाती है। प्रथम के पहले तीन महीने की और बाद में एक महीने की—लेकिन बेतन मिलता है—कुछ समय तक बच्चे के लातन-पालन के लिये हो घरे की विशेष छुट्टी बीजगती है।

(१०) स्पष्टतम बेतन इतना होता है कि वह एक मज़दूर को अपने घर का प्रपाल हो, की शिक्षा, उचित आनन्द और शौचतन आनन्द कलाओं की पूर्ति के लिये काफी हो।

( ११ ) सेटी और उद्योग की आय में भाग बढ़ाने की अनुमति है।

( १२ ) श्री पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलता है।

( १३ ) प्रत्येक म्युनिसिपैल्टी में विशेष कमीशन होता है जो म्यूनिसिपल वेतन और आय के मागों की दर निर्धारित करता है।

( १४ ) समय से अधिक काम के लिये सी प्रतिष्ठित वेतन देना होता है और वह काम एक बार में तीन घण्टे और एक सप्ताह में तीन दिन से अधिक नहीं लिया जा सकता।

( १५ ) किसी भी या सोलह वर्ष की आयु से कम बच्चे से समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता।

( १६ ) स्वच्छ बरों का प्रवन्ध है। किराया सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का आधा की सी प्रति मास के जिला से होता है।

( १७ ) मालिकों को, यदि वह किसी फैक्टरी में सी से अधिक आदमी काम पर लगाते हैं तो, स्कूल, अस्पतालों और अन्य आवश्यकताओं का प्रवन्ध करना पड़ता है।

( १८ ) यदि काम करने वालों की संख्या दो सी से ऊपर हो तो ५०० वर्ग मीटर भूमि बाजार और मनोरंजन के लिये रखनी पड़ती है।

( १९ ) शराब घरों और जुआघरों की हजामत नहीं है।

( २० ) मालिक लोग बुर्जदना या काम के कारण उत्पन्न रोमों के लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं।

( २१ ) तार्वजिक सेवा के काम में हकतालों के लिये दस दिन का नोटिस देना पड़ता है; यदि हिता से काम लिया जाय या बुद्ध का समय हो तो हकताल गैर-कानूनी समझी जाती है।

( २२ ) यह कानून गोला बाकू बनाने वाली फैक्टरियों पर लागू नहीं होते। कारखानों का बन्द होना कीमतों पर निर्भर है। दस सप्ताह में एक सम्झौते और वैधानिक का बोर्ड है जिसमें मिला मालिकों और मजदूरों के वरम्वर संस्था में प्रतिनिधि होते हैं और एक प्रतिनिधि सरकार का होता है।

( २४ ) करों में केवल किसी व्यक्ति का वेतन लिया जा सकता है। कर चुकाने के लिये पत्नी और उत्तान कवरे उत्तरदायी नहीं हैं।

( २२ ) कुछ बातें ऐसी हैं जिनके होने पर समझोते पैरकानूनी समझे जाते हैं ।

( २३ ) सर्वोच्च न्यायालयों के प्रेसीडेन्ट, सदस्यों और न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में नहीं बदला जा सकता ।

( २४ ) धर्म—कोई धर्म वर्जित नहीं किन्तु सब सरकार कानून के अनुसार दखल दे सकती है ।

( २५ ) विचार एक नागरिक-समझौता है । उस कानून से निर्धारित है ।

( २६ ) धर्म—कानून उन्हें व्यक्ति नहीं मानता । कोई भी धर्माधिकारी देश के विधान की आज्ञाचना नहीं कर सकता ।

ग्राम तौर पर धर्माधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं है और न वह पक्षों के लिये जुने जा सकते हैं ; वे राजनीतिक कार्यों के लिये समा गयी कर सकते, धार्मिक पक्षों के लिये ही नहीं शिक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा माननीय गयी है । न उस पर कोई इनाम दिया जा सकता है । उस नियम के विरुद्ध यदि किसी को ऐसा सम्झौता किया मिलती है तो वह नाज़ाकत है और कानून रंग करने वाली सत्ता को दण्ड दिया जा सकता है ।

( २७ ) कोई सामयिक या समाचार-पत्र अपने कार्यक्रम द्वारा, या नाम अथवा अपनी ग्राम धार्मिक प्रवृत्तियों द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक मामलों में विचार प्रकट नहीं कर सकता ।



: ६ :

## कुछ अन्य बातें

१

### आयरलैण्ड

कुछ अन्य बातें

डामीनिऑन पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित की गई है किन्तु वे उस पार्लियामेंट के डेप्टीमेन नहीं।

ब्रिटिश मगरिकों को बलाय किया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है। अपनी मुद्रा और मोट है—अपनी उपाधियों बेटी है और ब्रिटिश उपाधियों को नहीं मानता।

वे मुद्र की पीपला नहीं कर सकते।

२ :

### कैनाडा

कुछ अन्य बातें

सार्वजनिक श्रृणु —कैनाडा का श्रृणु निश्चित है। प्रांतों के पास भी सम्पत्ति है किन्तु कैनाडा को यह अधिकार है कि कितने बम्बी के लिये उसे ले ले।

आंतरिक कर नहीं है और कैनाडा की सम्पत्ति और भूमि पर कर भी नहीं है।



कानूनों को अंगरेजी और फ्रेंच में प्रकाशित किया जाता है। ऊपरों और निचले कैनाडा के शुरु, उच्चरायित्व, संपत्ति और माल के विभाजन और समझौता कराने का काम अंग्रेजों को क्यूबेक और कैनाडा के तीन दलों को सौंपा गया—जुनाय इन बातों की व्यवस्थापिका समझौतों को करना था।

नये उपनिवेश कैनाडा की पार्लियामेंट से प्रार्थना करने पर कुछ शर्तों और दशाओं पर बाध्यता किने जा सकते हैं। प्रवेश और लेटी होने के नियम सम्मिलित अधिकार में है किंतु केन्द्रीय कानून अपेक्षाकृत मान्य होते हैं।

जहाँ तक विचली और अज्ञान चरमने साम्यक मदियों का प्रश्न है वह करना कठिन है कि कितना नियन्त्रण प्राप्त करते हैं और कितना केन्द्र।

• ३ •

## आस्ट्रेलिया

### कुछ अन्य बातें

मजदूर क्रोडर—सीनेट के भी मोट होते हैं—वह पार्टी-संगठन के आधार पर बनाया जाता है।

४ बड़े शहरों में जनसंख्या का १/५ भाग रहता है—एक विस्तृत सत्ता प्रवेश है—शेष भूमि के मालिक बोके से व्यक्ति हैं—छोटे रूपक कैनाडा की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण हैं; मध्यम वर्ग नहीं है। न कोई स्थायी धनिक वर्ग ही है—यम ४० वर्ष से अधिक नहीं रहता—कोई पैतृक हित नहीं है—मजदूर और मालिकों के बीच कार्य-तामस्यवसी संबंध नहीं है—मेक का व्यवसाय करने वाले लान्दावसी हैं—स्थायी जनसंख्या उन लोगों की है जो ज्वालों को लाते हैं और लोने की ज्वालों में काम करते हैं और जिन्हें कोई सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं।

जहाँ कामनवेल्थ और अधिकार सम्मिलित हैं कामनवेल्थ के कानून राज्य के कानूनों की तुलना में मान्य होते हैं।

## दक्षिणी अफ्रीका

**कुछ अन्य बातें**

समस्त हर सम्बन्धी सत्ता गवर्नर-जनरल के पास है।

१—रेल और बन्दरगाह कोष।

२—एक सम्मिलित कोष जिसमें से सब प्रथम बन करबों के भुगतान के लिये लिया जाता है।

एक राजस्व कमीशन संघ और प्रान्तों के सम्बन्धों के निर्णय करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

सरकारी भूमि और खानों और खनिज पदार्थों पर गवर्नर जनरल का अधिकार समझा जाता है।

एक कानूनी रेल और बन्दरगाह बोर्ड है जिसके तीन सदस्य हैं और यह सदस्य उसका चेयरमैन होता है।

सब समस्त श्रुतों की जिम्मेदारी होगा—बन्दरगाह और रेलों की भी।

विशुद्ध केन्द्रीय और अनुसरदायी सरकार—कमल।

१—सब प्रान्तों में कानून गवर्नर जनरल के द्वारा प्रान्तों को दी गई सत्ता के मातहत बनाए जाते हैं।

२—गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी होती है।

३—सब सत्तों के लिये पहले से शासक या गवर्नर जनरल को अनुमति लेनी पड़ती है।

५

फ्रांस

**कुछ अन्य बातें**

शासन विधान का विकास :

१७९३ से १८८४ ई तक।

कोई भी सार्वजनिक और म्युनिसिपल अफसर साक्षित नहीं जा सकता ।

सीनेट बहुत आकर्षक है—किन्ती सभति कर सीनेट के सदस्य बन जाते हैं और फिर प्रेसीडेंट पर के उम्मेदवार ।

क्रॉस में बड़ी प्रभावशाली पार्टियाँ नहीं हैं । किन्तु पार्टियों के समूह हैं जिन्हें ब्लाक कहा जाता है, जिनके कई मेम्बर होते हैं । कोई निरिपक्ष सिद्धांत नहीं होता और अनुशासन का एकदम प्रभाव रहता है ।

क्रॉस में प्रजातन्त्रवादी सरकार है—सर्वोपर्य राजतन्त्रवादी है और गवर्नरों साम्राज्यवादी ।

इङ्ग्लैंड में मन्त्रिमण्डल देश की भावना का व्याप्त रहता है, क्रॉस में पार्लियमेन्ट की भावना का । क्रॉस एक लोकप्रणाली है, प्रजातन्त्र नहीं ।

फ़्रान्स

क्रॉस सदस्यों से यह कहा जा रहा है कि वे अपने मित्रों का कुछ फायदा कराने के लिये सम्मान, समर्थन, पीठे, कानों में कोयलपत्र का पर और सम्मान की किरी का साक्ष्य । प्रत्येक सदस्य अपने बहा होते हैं ।

६

## न्यूजीलैंड

कुछ अस्य बातें

न्यूजीलैंड के सम्प्रदाय निवासियों में अविद्या नहीं है ।

कानून

अर्थ-समाजवादी राज्य है ।

सम-मत-राज्य केवल एक बार शराबबन्दी के विषय की गई ।

अपराध नहीं है ।

• ७

## ज़ैकोस्लोवाकिया

**कुछ अन्य बातें**

सम्मिलित अधिवेशन प्रेसीडेंट द्वारा चुनाया जाता है—कार्यकारी का दस केबलर आफ डिप्टीज़ की तरह होता है। सीनेट का केबलर में बार-प्रेसीडेंट होता है।

• ८

## स्विटज़रलैंड

**कुछ अन्य बातें**

१८४९ ई. में सार्वजनिक पहल को प्रारम्भ किया गया यह सुनने, कौर्बग और बेसी को छोड़कर शेष सभी कानूनों में समा और कानून पर लागू होता है।

संघ विधान १६ मई १८७५।

**जनमत-गणना**—१०००० सक्रिय नागरिक या आठ कैन्टन के पाठ होने के ६० दिन के भीतर जनमत गणना की मांग कर सकते हैं। जनमत-गणना ऐच्छिक होती है या अनिवार्य, संघ में वैधानिक परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिये केवल ऐच्छिक जनमत गणना का उल्लेख है।

**सार्वजनिक पहल**—दोनों कान्टोनों में से किसी के सदस्य या कैन्टन प्रमुखद्वारा द्वारा कानून के पहल करने का अधिकार रहते हैं।

**स्वीस संघ अथवा द्विलैटिक प्रजातन्त्र** -

संघ न्यायालय, क्योंकि राजधानी बर्ग है, अतएव फ़ाप्पीटी भाषना को कुछ करने के लिये सीटोन में स्थित है और मिरान्त पीलीटेस्कीक स्कूल कूरिच में है।

श्रीवर्ग में जनमत रखना नहीं होती। कुछ दिन पहले तक सभीों पर जनमत रखना लागू नहीं होती थी किन्तु अब १९२१ से अन्य मामलों की तरह सभीों पर भी यह हो सकती है। कैबिनेटों में प्रायः अनिवार्य जनमत रखना है। यह ग्यारह कैबिनेटों में है जब कि सात में इसका प्रयोग ऐच्छिक है।

६

## जर्मनी

### कुछ अन्य बातें

किसी ट्रस्ट के लाभ बचीवत नहीं की जा सकती। अतुपायित वचन (unearned increments) सार्वजनिक कार्यों में खर्च की जाती हैं।

सामाजिक अधिकारों और अर्थव्यवस्थाओं के सिधे मारपीट की जाती है—जर्मनों को अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य रूप से प्रभाव करने होते हैं।

मजदूर संगठित हैं—यह मिला मजदूर परिषदों और रील की आर्थिक परिषदों से सम्बन्धित हैं।

उपरोक्त अवस्थाओं में यदि मजदूरों किसी कानून के बारे में चाहें तो वह रीलस्टाग के ३ भाग पर राय बनाने के सिधे प्रचारित किया जा सकता है।

(अ) रील का प्रेसीडेंट चाहे तो उसे लागू करने के पहले एक महीने के अन्दर।

(ब) या यदि मजदूरों पहले से किसी बिल को पेश करने की प्रार्थना करें तो वह सरकार के द्वारा रीलस्टाग में उपस्थित करना होता है। यदि ऐसे बिलों का सम्बन्ध कर या खर्च से हो तो प्रेसिडेंट उन्हें लेकर मये चुनाव करा सकता है।

## सोविथत रस्त

### कुछ अन्य बातें

आत्मरक्षितन कायेत में विधान बनाया है जिसके कुछ विद्यमानों को पदना स्कूल में अनिवार्य है ।

### विधान के मूल सिद्धांत—

( १ ) शहर और गांव के मजदूरों की लानाछाही का स्वागत और पूजापतियों का इमन । ( २ ) तथा शहरी और देशी सोविथतों में निहित है ( ३ ) प्रदेश की सोविथतें मिल कर प्रादेशिक कायेत और संघ बना सकती हैं । ( ४ ) धर्म का राज्य और स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं ( ५ ) सोविथतों की आत्म रक्षितन कायेत और उठकी कार्यकरिणी सबीब है । ( ६ ) समाचार पत्रों के समस्त प्रकाशन के साधन मजदूरों को दे दिये गये हैं । ( ७ ) समा करने, बहुत निहालने और संगठन करने की स्वतन्त्रता है— हल ( Hall ) का उपयोग उम्हें गर्न करने और प्रकाशित करने की अनुमति है । ( ८ ) स्वयं-समठन के समस्त साधन जिसमें मिगुस्क शिक्षा भी है मजदूरों और किसानों को निना रोड-टोक मिले हुए है । ( ९ ) जो काम नहीं करेगा उसे लाना नहीं मिलेगा ( १० ) समाज बादी विमुक्ति की रक्षा और सेम्प-सेवा अनिवार्य है । ( ११ ) विदेशियों को नागरिकता और मजदुरी के अधिकार सोविथतों के मार्जत दिये जाते हैं । ( १२ ) धार्मिक या राजनीतिक अपराधी विमाम पात्र के हकदार हैं । ( १३ ) सब नागरिक समान हैं—कोई विशेष सुविचार्य नहीं। अन्न मतवालों का इमन मर्तो होता । ( १४ ) व्यक्ति और समाज ऐसे काम करने के लिये बर्जित हैं जो समाजवादी राज्य को डेस पहुँचाये ।

## अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

### शासन विधान में परिवर्तन—

कार्बनिक पहल—१९ राज्य। में कांग्रेस के लिये और २१ में वैधानिक परिवर्तनों के लिये लागू है—कमी कमी नागरिकों को पहल के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये पॉच सैण्ट या अधिक दिया जाता है। कैलीफोर्निया में पहल पर औसतन खर्च १५०० पौंड पड़ता है। शक्ति-समूह और घोषणाबी बलही है क्योंकि अल्पसंख्यकों को अनियमित नहीं माना जाता। कमी कमी पहल करने के पहले उन विषयों पर प्रेसलेट मिलकर चर्चे करते हैं।

पहल के लिए सरकारी नहीं होते।

वैधानिक संशोधन के द्वारा आधारभूत अधिकारों को कम किया जा सकता है।

अनसूचित-नाशना के अर से अनेकों विषय पास नहीं किये गये और पहल होने से अनेक अच्छे विषय अस्वीकृत मही किये गये।

बाली का अधिकार है किन्तु बहुत कम उपयोग में लाया जाता है।

जुने हुए अष्टस्रो, जिनमें व्यापारीय भी शामिल हैं, की बाली हर राज्य में हो सकती है और व्यापारीयों को छोड़ कर अन्यी की हर राज्य में।

१६ वीं संशोधन—अल्प-कर राज्य का विपक्ष करार दिया गया।

पैरा प्रोह—राज्यों के विरुद्ध युद्ध करना। निष्कासन में लून सराफ नहीं किया जाता। सब राज्यों में एक ही मुद्रिपाई और मुद्रम चार्ज है—किन्तु अपराधी प्रत्यर्पण बलही है।

कुल राज्यों में नावाकितों से मजबूती लेना अपराध है।

१५ वीं संशोधन ग्रेवीजेन्ट और बाहल ग्रेवीजेन्ट के पुनर्वास्यत्व।

१७ वीं संशोधन सराफ बन्धी के मामलों में सम्मिलित अधिकार।

१९ वीं संशोधन बी-मताधिकार।

१५ वीं संशोधन दक्षिणी राज्यों ने नीग्रो के लिये समानाधिकार सम्बन्धी नियम रख कर दिये।

रोक-थाम की व्यवस्था—(१) व्यवस्थापक विभाग (२) प्रभुत्व विभाग (३) स्वाय विभाग—एक दूसरे से अलग और स्वतन्त्र रहे जाते हैं। पहला दूसरे या तीसरे के साथ, दूसरा पहले या तीसरे के साथ तीसरा पहले या दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

प्रेसीडेन्ट कांग्रेस के विना को बीटो कर सकता है किन्तु कांग्रेस के बहुमत से उक्त बीटो को अमान्य कर सकता है। स्वायत्त कांग्रेस के कानूनों को अन्वेषण कर सकते हैं। कांग्रेस और प्रेसीडेन्ट का आपस में विरोध हो सकता है या दोनों का ही स्वायत्तता से।

अमेरिका का प्रेसीडेन्ट शासन भी करता है और सरकार भी चलाता है—ब्रिटिश राजा शासन करता है किन्तु सरकार नहीं चलाता—फ्रांसीसी प्रेसीडेन्ट न शासन चलाता है और न ही सरकार चलाता है—अनरल प्रेसीडेन्ट सरकार चलाता है।

मुहरमेबाजों को स्वायत्तता की आवश्यकता के कारण बहुत दिनों तक नहीं करनी होती है—औरकारी के स्वायत्तता और भी बुरे हैं—बहुत अधिक समय लगता है—जुर्गे का प्रवण होने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि (अ) कोई ठीक सूची नहीं (ब) जुरे के नामों के बारे में एकराज किया जा सकता है।

अनेको स्वायत्तता के सम्मुख उठाये गए एकराजों पर पूरे स्वायत्तता द्वारा विचार होते-होते एक वर्ष या अधिक भीत जाता है। बकील यदि चाहें तो जुरे पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं—दक्षिणी राज्यों में वार्षिक और कानूनी कठोर व्यवस्था आम बात है।

पुराइयों—बमकाना; मोटों को गलत विनना, टैमनी के हथकण्डे—टैमनी के पास पुलिस और स्वाय-विभाग में दिसाने के लिए भौकरीयों रहती हैं—निरोधक और प्रवारक होते हैं—बुनाक-प्रदातते उनके आदमियों से घरी रहती हैं—ग्रेव को पैठा देते हैं—परिकाओं की मदद करते हैं—सभी पार्टियों के उन मशीन मास्त्रिकों को जो राज-मौलि में मैत्रिकता के सिद्धान्त को नहीं मानने, गुजरा की बाग नारतन्त्र होती है।



अमेरिका के नागरिक रेमिस्तान के परमाणुओं के रेत के समुद्र के समान हैं किन्हीं छोटी इमारत या ठावर से जाती रहती है।

अपराध—ठेकों का कब विचार—मलों का विचार—कानून तोड़ने वाले प्रायः इराद से करी रहते हैं और पुलिस प्रायः स्वयं इन तकबदियों में फँसी रहती है।

वार्मिक मेदमाय नहीं है—कोई कटुता नहीं है—महाद्वीप की तरह बगमेद नहीं है—वार्मियों काही मोतकों पर लेविल की तरह है—राज्य ही नहीं कोई प्रेस किसी राजनीतिक के अधिकार में हो।

नागरिक को खूब सुझावें प्राप्त होती हैं किन्तु पार्टी के हस्तारल में फँसे रहते हैं—ये कानूनों के तुरे निर्धारक किन्तु मनुष्यों के अधिक निर्धारक हैं।

## १२

## स्वीडन

कुछ अम्य बातें

यूरोप में प्राचीनतम विधान है।

बिना राजा की अनुमति के बरि राजकुमार शाही करे तो गद्दी का हकदार नहीं रहता।

अन-मत्त-भारत—राजा किसी भी विषय की जनमत गवना के बिने मेव सकता है। इसमें अधिक संख्यावाले मदन के मतारता भाव होते हैं। रिकरुमम हर बीजे राज ६ व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त करती है जो स्वयं के मामलों के अदालत के राज प्रेस की स्वयंराज की निगरानी रखते हैं—इनमें दो बकील होते हैं। इनके द्वारा ही गई आज्ञा होतकों की अवरदायित्व से मुक्त कर देती है।

## • १३ •

## एस्थोनिया

कुछ अम्य बातें

नार्मनिक पहल और जनमत गवना का महत्त्वपूर्ण रपाय है।

**प्रस्तावना**

अच्छी है, अनिवार्य सेवा सेवा ।

१४

## आस्ट्रिया

**कुछ अन्य बातें**

ग्राम परिषद किया जाता है । जंगलों और क्षेत्रों के मजदूरों के अतिरिक्त ।

कुछ विषयों में कानून बनाने के अधिकार प्रांतों के पास है जैसे नागरिकता, पेशे, प्रतिनिधित्व और कर ।

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में अन्तिम अपील सब द्वारा नियुक्त एक कमीशन में होती है जिसमें न्यायाधीश प्रबन्ध करनेवाले अफसर और विशेषज्ञ होते हैं ।

जनमत-योजना में सफलता के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और वह प्रेसीडेन्ट द्वारा कराई जाती है ।

१५

## बेल्जियम

**कुछ अन्य बातें**

सेना में राज्य से भरती होती है ।

संधियों वार्नबन्धित होती हैं ।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कमेटियों या विभागों में बंटा है जिन्हें विचार के लिए विल भेजे जाते हैं । विरोध विलों के लिए विरोध कमेटियों नियुक्त की जा सकती हैं । उपरोक्त कमेटियों को हर महीने पच्चे बालकर नए सिरे से बना लिया जाता है । प्रत्येक विभाग का एक रिपोर्टर नियुक्त किया जाता है । इन सब रिपोर्टरों का एक केन्द्रीय विभाग

होता है जिसके रिपोर्टरों की नियुक्ति चेम्बरों का प्रेसीडेंट करता है। हाउस द्वारा प्रत्येक अधिवेशन में गुप्त वोट से दो स्थायी कमेटीयों चुनी जाती हैं। (१) राजस्व और विधायकी कमेटी, कृषि-व्यापार और उद्योग की कमेटी।

हाउस जब उचित समझता है तो विशेष कमेटीयों नियुक्त करता है और सीनेट में इसका आम विचार है।

१६

नार्वे

कुछ अन्य बातें

विधान संयुक्त राष्ट्र (१७८७ ई०) फ्रांस (१७९१ ई) स्पेन (१८१२ ई०) के आधार पर बना है।

कानून धर्म के बारे में निर्धार करता है।

१७ :

इंग्लैंड

कुछ अन्य बातें

ब्रिटेन का शासन विधान अनेकों चार्टरों, प्रणालियों, निर्धारों, नज़रों और कानूनों से मिलकर बना है जो बराबर बढ़ते रहते हैं, कमी रिश्त नहीं होते।

बर्ष आठ मेशमल असेम्बली एक्ट, १८१८ ई०—यह बर्ष असेम्बली को कानून बनाने की अनुमति देता है कि वे पार्लियामेंट के प्रस्ताव द्वारा उचित सहायता मिल जाने पर राजा मान लेता है।

परिशिष्ट

यू एस एस आर ( सोवियत रूस )

के

शासन विधान का मसविदा



: ६ :

एस एस आर (सोवियत रूस)

के

शासन विधान का मसविदा

चेक-पृष्ठ ८८, १६ ७६१ वर्ग मील ।

अनंतकाल : १६, १९, २५, ०००

राजधानी मास्को ।

---

पहला अध्याय

सामानिक संगठन

धारा १—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों का यह संघ मजबूत और  
तानों का समाजवादी राज्य है ।

धारा २—यू. एस. एस. आर. का राजनीतिक आधार काम  
रेषाओं के प्रतिनिधियों की सोवियत है जो जमींदारों और पूँजीपतियों  
तत्ता को उलट देते पर सर्वोच्च एकाधिकार की विषय से बनी और  
मजबूत हुई है ।

धारा ३—यू एस एस आर. में सम्पूर्ण सक्ति यावों और सपों में काम करने वालों को उनके प्रतिनिधियों की सोचिवतों के रूप में मिली हुई है।

धारा ४—यू एस एस आर. का आर्थिक आधार उसकी यह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन साधनों तथा संय का समन्वितकरण है जो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को उत्पाद फेंकने, उत्पादन के साधनों और संय में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करने तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण को समाप्त करने के बाद मजदूरी के साथ कायम किया गया है।

टिप्पणी—सोवियत संघ में 'सुधीम काउन्सिल' व्यवस्थापिका समा को कहते हैं। 'सोवियत' के अर्थ साधारणतः प्रतिनिधि-सभा समझा जा सकता है। 'पीपुल्स कमीस' वहाँ उन्हीं तरह होते हैं जैसे कि अन्य देशों में मंत्री; 'काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमीस' से सार्वभौम मंत्रिमंडल से होता है; 'कमसोवियत' का सार्वभौम शासन के विभाग (Department) से है; विपुलियों से सार्वभौम प्रतिनिधियों से है; 'वैसीकोवम' वहाँ की अपनी निराली संस्था है जो व्यवस्थापिका समा के अनिवेदन में न होने के समर्थ उसकी सहायता समस्त अधिकारों का उपयोग करती है।

धारा ५—यू एस एस आर. में समाजवादी सम्पत्ति का रूप या तो राज्य का अधिकार (अथ सम्पत्ति) है या उसका रूप सहकारिता और सामूहिक संग की सेती का अधिकार (व्यक्तिगत सामूहिक सेती की सम्पत्ति, सहकारिता समितियों की सम्पत्ति) है।

धारा ६ मृमि, इसमें स्थित चीने, जल, संगठ, भिन्न, पैररीकों कानों, रेलों, जल तथा वायु के यातायात के सम्पत्ति बैंक, उद्योग के साधन, राज्य द्वारा समर्थित बड़े संग (राज्य के संग मशीनें, ट्रेक्टर स्टेशन इत्यादि) और साथ ही शहरों और औद्योगिक बेगों में पणों के सम्पत्ति बैंक राज्य की यानी सार्वजनिक सम्पत्ति है।

धारा ७—सामूहिक सेतों के सार्वजनिक उपयोग और सहकारिता संगठन, अपने पशुओं, औजारों और सामूहिक सेतों और सहकारिता संगठनों की उपकरण और साथ ही उनकी सार्वजनिक इमारतें सामूहिक सेतों और सहकारिता संगठनों की सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति हैं।

प्रत्येक सामूहिक सेती में भाग लेने वाले परिवार के पास निजी उपयोग के लिये घर से लगा हुआ एक जमीन का टुकड़ा होता है और व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उस जमीन में छोटे-मोटे काम एक घर उत्पादक पशु और विभिन्न और छोटे-मोटे सेती के औजार हो सकते हैं— यह सेती सर्वोच्च बारा के अन्तर्गत होता है।

धारा ८—समूहिक सेतों द्वारा जो भूमि पिट्टी हुई है, वह बिना किसी अवधि वाली सदा के लिये उनको दे दी गई है।

धारा ९—यू एच एच आर की प्रदान समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अतिरिक्त कानून ऐसी छोटी छोटी अलग-थलग किसानों और कारीगरों की आर्थिक व्यवस्था की भी अनुमति देता है जिसमें निजी काम सम्पन्न हो और दूसरों की मजदूरी का शोषण न होता हो।

धारा १०—नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, उनकी धातु और वस्त्र में, घर और अन्य सरकारी बरेलू कार्यों में अन्य बरेलू या पारस्वी की वास्तुओं में और साथ ही व्यक्तिगत उपयोग और आराम की चीजों में प्रयुक्त है।

धारा ११—यू एच एच आर का आर्थिक जीवन पद्धति की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा तार्विक बन को बढ़ाने के लिये काम करने वालों के मौलिक और सांस्कृतिक मापदण्ड को समायोजित करने के लिये और यू एच एच आर की स्वतन्त्रता को मजबूत करने और उसकी रक्षा-सर्वोच्च योग्यता को बढ़ाने के लिये निर्दिष्ट और निर्धारित किया जाता है।

धारा १२—यू एच एच आर में प्रत्येक कार्य कर सकते योग्य व्यक्ति का इस सिद्धांत के अनुसार काम करने का कर्तव्य है : “यह, जो कार्य नहीं करता, भूता रहेगा।” यू एच एच आर में समाजवाद के इस सिद्धांत को पूरा किया जा रहा है “प्रत्येक से योग्यतानुसार कार्य, प्रत्येक को कार्यानुसार (आव का) भाग।”



## दूसरा अध्याय

## राज्य संगठन

धारा ११—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों का यह संघ एक संघ-राज्य है जो सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों को स्वेच्छा के आधार पर बना हुआ समुदाय है जिसमें उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं —

रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
ब्लाइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
तर्कमीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
उज़बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
कज़ाख सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,  
किर्गिज़ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक

धारा १४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों के संघ, जिसका प्रतिनिधित्व उसके सर्वोच्च विभाग और शासन के विभाग करते हैं, के निम्न लिखित अधिकार हैं —

- ( क ) संघ का विदेशी धामनों में प्रतिनिधित्व, अन्य देशों के साथ सम्बन्ध करना — और उन्हें अन्तिम स्वीकृति प्रदान करना ,
- ( ख ) युद्ध और शांति के प्रश्न ,
- ( ग ) मंचे प्रजातंत्रों का संघ में प्रवेश ;
- ( घ ) यू० एच० एच० धारा के शासन विधान की मर्यादा के सिधे नियन्त्रण और यह देखना कि संघ के प्रजातंत्रों के शासन विधान यू० एच० एच० धारा के शासन-विधान के अनुकूल हैं ;
- ( ङ ) संघ के प्रजातंत्रों के बीच होने वाले सीमा परिवर्तनों के सिधे स्वीकृति देना ,

- ( ब ) यू. एस. एस. आर की रक्षा का संगठन और यू. एस. एस. आर की समस्त इयियार बम्ब फौजों का निर्देशन ,
  - ( छ ) राज्य के एकधिकार के आधार पर विदेशी व्यापार ;
  - ( ज ) राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध ,
  - ( झ ) यू. एस. एस. आर के लिये राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाना
  - ( ञ ) यू. एस. एस. आर के लिये एक संयुक्त बजट की और यू. एस. एस. आर तथा के प्रजातन्त्रों और स्थानीय बजटों के लिये करो तथा अन्य आय की मदों के लिये रशोक्ति देना ,
  - ( ट ) बैंकों, औद्योगिक और खेती के कारबार और पूरे संघ के महत्व के व्यापारिक डामों का शासन ,
  - ( ठ ) वातावात और उन्देश के साधनों का प्रबन्ध ;
  - ( ड ) मुद्रा और उधार-व्यवस्था का निर्देशन ,
  - ( ढ ) सम्पत्ति का राज्य के द्वारा बोसा की व्यवस्था ,
  - ( ढ ) ऋण लेना और देना ;
  - ( त ) भूमि के उपयोग और उसमें स्थित पदार्थों, वनस्पतों और जल के उपयोग के लिये मूल विद्यमान निर्धारित करना ;
  - ( थ ) शिक्षा के क्षेत्र में और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये मूल विद्यमान निर्धारित करना ,
  - ( द ) राष्ट्र का आर्थिक हितान-किताब रखने के लिये एक केन्द्रीय पद्धति स्थिर करना ,
  - ( ध ) मजदूर-सम्बन्धी बुनियादी कानून बनाना;
  - ( न ) न्याय और कानूनी कार्यवाही के ढंग। शीवानी और औद्योगिक के कानूनों के संग्रह सम्बन्धी नियम बनाना;
  - ( प ) संघ की नागरिकता के कानून विदेशियों से अधिकारों के कानून;
  - ( फ ) पूरे संघ के लिये ग्राम रिहाई के कानून पास करना ।
- धारा १५—संघ के प्रजातन्त्रों की राज्यशक्ति केवल यू० एस० एस० आर, डे, शासन विधान की धारा १४ सीमित करती है। इन सीमाओं के बाहर संघ का प्रत्येक प्रजातन्त्र अपनी राज्यशक्त का स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग करता है। यू० एस० एस० आर संघ के प्रजातन्त्रों की राज्य शक्त के अधिकारों की रक्षा करता है।

धारा १६—प्रत्येक संघ में प्रजातन्त्र का अपना अलग शासन विधान है जो संघ की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और यू, एच, एच, आर के शासन विधान के पूर्ण अनुकूल बनाया जाता है।

धारा १७—संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को यू, एच, एच, आर से स्वतन्त्रता पूर्वक अलग हो जाने का अधिकार है।

धारा १८—संघ के प्रजातन्त्रों के क्षेत्र विन्य उनही इच्छा के परिवर्तित नहीं किये जा सकते।

धारा १९—यू, एच, एच, आर के कानून संघ के समस्त प्रजातन्त्रों के क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं।

धारा २०—यदि संघ के प्रजातन्त्र का कोई कानून संघ के कानून से भिन्न हो तो संघ का कानून ही मान्य होता है।

धारा २१—यू, एच, एच, आर के समस्त नागरिकों के लिये संघ की नागरिकता का एक ही कानून है। संघ के प्रजातन्त्रों का प्रत्येक नागरिक यू, एच, एच, आर का भी नागरिक होता है।

धारा २२—रशियन सोवियत फ़ेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्रदेश हैं—अज़ोव—कालासागर, सुदूरपूर्व, पश्चिमी उराले रिया, कैस्नोवॉठ उच्चो वीकेस्त प्रान्त, बोरोनेज़, पूर्वी उराले रिया, गोरकी पश्चिमी इवाज़ोव, कास्किनि डिपेच, डिबोरोव, कर्स्क, मिनिम्राड, मोल्दो, क्रॉस्क ऑरिनबर्ग, तारातोव, स्वर्बलोवस्क उच्चो रेस्तिनवाड, चेकिवाविस्क, वारोव्लाव्ज; सुदूरमुख्यतः सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक—तातार, बर्किर, दारिल्लान, तुर्बोर्न मंगोलिया, कबार् दिनो, ओमिश, मी, मोर्किश, जर्मन बोस्ना, उच्चो ओवेदि प्रा, उदमर्त, चेबन—इगुच, ब्राश, वाम्बू; सुदूरमुख्यतः प्रांत—बोरोव, बहुरी काराचोव, ओइरोव, लाकाश, चेईश।

धारा २३—यूरेमियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्रांत हैं—विस्तीका, मीमो—पेट्रोवस्क, डोनेस, कीव ओवेका, जारोव चैर्नोपोव और सुदूर मुख्यतः मोवडेवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।

धारा २४—अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में सुदूर मुख्यतः मारवीचेबन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और माग्गेनो-काश-बाश का सुदूर मुख्यतः प्रांत है।

धारा २२—आर्थिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में अगला क्रिम का कुर मुफ्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अगारियन का कुरमुफ्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और दक्षिणी सोवियत का कुरमुफ्तार प्राप्त है।

धारा २३—उत्तर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में काउ-अक्साक का कुरमुफ्तार सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्र है।

धारा २४—तामिळ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में गोर्नो-बस्ता क्या का कुरमुफ्तार प्राप्त है।

धारा २५—कज्जाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में निम्नलिखित प्राप्त हैं: अकम्पूबिरक, आकमाआता, पूर्वी कज्जाकस्तान, पश्चिमी कज्जाकस्तान कारागान्दा और दक्षिणी कज्जाकस्तान।

धारा २६—आरमीनिन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ब्राइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मुकमोनिन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और विभिन्न सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में कोई कुरमुफ्तार प्रजातन्त्र प्रवेश का प्राप्त नहीं है।

## तीसरा अध्याय

### समानवादी सोवियत प्रजातन्त्रों के संघ की राज्यसभा के सर्वोच्च विभाग

धारा ३०—यू. एस. एस. एस. आर की राज्यसभा का सर्वोच्च विभाग यू. एस. एस. आर की सुप्रीम काउन्सिल है।

धारा ३१—यू. एस. एस. आर. की प्रधान समिति समानवादी सोवियत प्रजातन्त्रों के संघ के शासन विधान धारा १४ में बताए गये उन समस्त अधिकारों का उल्लेख करती है जो शासन विधान द्वारा यू. एस. एस. आर की सुप्रीम काउन्सिल के मातहत यू. एस. एस. आर के अन्य विभागों को नहीं सौंपे गये हैं, वे विभाग हैं—यू. एस. एस. आर की

सुप्रीम काउन्सिल के यू, एल, एल, आर के पीपुल्स कमीशनरों की काउन्सिल और यू, एल, एल, आर की पीपुल्स कमीशनरों ।

धारा ३२—यू, एल, एल, आर के कानून बनाने के अधिकार का यू, एल, एल, आर की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा एक मात्र उपयोग किया जाता है ।

धारा ३३—यू, एल, एल, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दो मवन हैं— संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद ।

धारा ३४—संघ परिषद का चुनाव यू, एल, एल, आर के मन्त्रिक प्रति ३००००० की कम संख्या के पीछे एक हिपुटी की अनुमति से करते हैं ।

धारा ३५—राष्ट्रों की परिषद प्रमिशन की कुरमुस्तार प्रकाशनों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा प्रत्येक कुरमुस्तार प्रमिशन में धर्म नीतियों के हिपुटियों की सीमितता द्वारा प्रत्येक संघ के प्रकाशनों से दस हिपुटियों के अनुपात से, प्रत्येक कुरमुस्तार प्रकाशनों से पाँच हिपुटियों के अनुपात से और प्रत्येक कुरमुस्तार प्रमिशन से दो हिपुटियों के अनुपात से जुने जाते हैं ।

धारा ३६—यू, एल, एल, आर की सुप्रीम काउन्सिल बार वर्ष की अवधि के लिये चुनी जाती है ।

धारा ३७—यू, एल, एल, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों मवन ( संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद ) के समान अधिकार हैं ।

धारा ३८—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद दोनों ही समान रूप से कानून बनाने में सहज कर सकते हैं ।

धारा ३९—जब यू, एल, एल, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों मवनों में कोई कानून प्रकाशन प्रकाशक आधारण बहुमत से पार हो जाय तो वह बाकायदा कानून बन जाता है ।

धारा ४०—यू, एल, एल, आर, की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाए गए कानून यू, एल, एल, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियस के सेपरेट और सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं ।

धारा ४१—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद के अधिकारण साथ साथ प्रारम्भ होते हैं और साथ ही साथ उनका अन्त होता है ।

धारा ४२—संघ परिषद अपने लिये एक चेयरमैन और दो बाइल-चेयरमैन को चुनती है।

धारा ४३—राष्ट्रों की परिषद अपने लिये एक चेयरमैन और दो बाइल-चेयरमैन को चुनती है।

धारा ४४—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद के चेयरमैन अपनी अपनी भाषनाओं के अधिवेशनों पर नियन्त्रण रखते हैं और उनकी आन्तरिक व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करते हैं।

धारा ४५—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों मजनों के सम्मिलित अधिवेशनों का निर्देशन जारी जारी है संघ परिषद का चेयरमैन और राष्ट्रों की परिषद का चेयरमैन करता है।

धारा ४६—यू, एच, एच, आर, की काउन्सिल के अधिवेशन एक वर्ष में दो बार यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम द्वारा बुलाई जाती है।

यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम अपनी इच्छा से अपना संघ के किसी प्रजातन्त्र की मांग पर विशेष अधिवेशन बुला सकती है।

धारा ४७—यदि किसी प्रश्न पर संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद में आपस में मतभेद हो तो सम्मेलन के लिये वह प्रश्न एक सम्मेलन कमीशन के पास भेज दिया जाता है जो समान प्रतिनिधित्व के आपस पर निर्मित किया जाता है। अगर सम्मेलन-कमीशन किसी निर्णय नहीं आता अपना ठरका निर्णय दोनों में एक को संतुष्ट नहीं करता तो वह प्रश्न दोबारा विचारार्थ भेज दिया जाता है। यदि फिर दोनों मजनों किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो पाते तो यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल को मंग कर लेती है और मने चुनाव कराती है।

धारा ४८—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल दोनों मजनों के सम्मिलित अधिवेशनों में यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का जितने यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल प्रेसीडियम का एक चेयरमैन और बाइल-चेयरमैन प्रेसीडियम का निदेशक और प्रेसीडियम के ११ सदस्य होते हैं, चुनाव कराती है।

यू, एल, एल, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडिंग अपने समस्त कार्यों के लिये यू, एल, एल आर की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी है।

धारा ४९—यू, एल, एल, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडिंग—

( क ) यू, एल एल आर, की सुप्रीम काउन्सिल अधिवेशन बुलाती है,

( ख ) उचित निर्देश देकर लागू कानूनों की व्याख्या करती है।

( ग ) यू, एल, एल, आर के हाउस विधान की धारा ४७ के सम्मर्त यू, एल, एल आर की सुप्रीम काउन्सिल को रंग करती है और नये चुनाव कराती है।

( घ ) अपनी इच्छा से या यूनिवर्स के किसी प्रस्ताव की मंजूर कर बन मत-गणना ( Referendum ) कराती है।

( ङ ) यू, एल, एल, आर. के पीपुल्स कमीशनों की परिषद और प्रस्तावनों के पीपुल्स कमीशनों की परिषदों के निर्णय और आस्थाओं को यदि वे कानून के अनुसार न हों तो खर कर देती है,

( च ) यू एल, एल आर. की सुप्रीम काउन्सिल के अधिवेशनों के बीच में यू, एल एल, आर. के पीपुल्स कमीशनों की काउन्सिल के चेयरमैन की इच्छा पर यू एल, एल आर. के विभिन्न पीपुल्स कमीशनों को पद से हटाने और उन पर नई नियुक्तियाँ करती है जो बाद में यू, एल, एल, आर. की सुप्रीम काउन्सिल की स्वीकृति के लिये पेश कर दी जाती है।

( छ ) यू, एल, एल आर. के पदक प्रदान करती है;

( ज ) क्षमा प्रदान के अधिकार का उपयोग करती है;

( झ ) यू एल, एल, आर. की सशस्त्र फौज के उच्चतम आधीनता को नियुक्त करती है और हटाती है;

( ञ ) यदि यू, एल, एल, आर की सुप्रीम काउन्सिल के अधिवेशनों के बीच में यू एल, एल, आर. पर सशस्त्र आक्रमण हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है;

( ट ) पूर्ण या आंशिक सैन्य संगठन की आज्ञा देती है;

( ठ ) अन्तर्राष्ट्रीय समितियों को अन्तिम अनुमोदन देती है।

( ड ) यू. एल. एस. आर. के विदेशी राजदूतों की निम्ति करती है और उन्हें बापस बुलाती है ,

( ह ) विदेशी राजदूतों के परिचयपत्रों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करती है।  
धारा ५०—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद अपने अपने मवन के डिपुटियों की प्रामाणिकता की जाँच करने के निमित्त प्रमाण-पत्रों के देखने वाले कमीशनों के चुनाव करती है ।

इन प्रमाण-पत्रों को देखने वाले कमीशनों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम काउन्सिल के मवन इस बात का निर्णय करते हैं कि व्यक्तिगत डिपुटियों के प्रमाण-पत्रों को मान्य मान या उनके चुनावों को रद्द कर दिया जाय ।

धारा ५१—यू. एल. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल, जब आवश्यकता समझती है, तब किसी भी विषय पर जाँच करने वाले और विचार का निरोक्षण करने वाले कमीशनों की निम्ति कर देती है ।

समस्त संरवायें और अफसर इन कमीशनों की भौग को पूरा करने के लिये बाध्य है और उन्हें कमीशनों को आवश्यक चीजों और काम-काजों को पेश करना होता है ।

धारा ५२—यू. एल. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल के किसी डिपुटी पर बिना यू. एल. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की स्वीकृति के न हो अभियोग चलाया जा सकता है और न उसे बर्दो बनाया जा सकता है । जब यू. एल. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल का अभिवेशन न हो रहा हो तो यू. एल. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम की सहमति लेनी होती है ।

धारा ५३—यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अपना धननी अवधि के पूर्व सुप्रीम काउन्सिल के भंग हो जाने पर यू. एल० एस० आर. की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम उक्त समय तक सत्तावृद्ध रहती है जब तक कि यू. एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का मया चुनाव न हो जाय ।

धारा ५४—जब यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल



की तथा समाप्त हो जाती है जबवा कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही वह मंग कर दी जाती है तो यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल को प्रैसीडियम यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की तथा समाप्त होने जबवा उसके मंग होने के अधिक से अधिक दो माह के भीतर नये चुनाव कराती है ।

धारा १३—यू० एल० एस० आर० की अन-निर्वाचित सुप्रीम काउन्सिल को यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की पुरानी प्रैसीडियम अधिक से अधिक चुनाव के एक माह के भीतर बुलाती है ।

धारा ५३—यू० एल० एस० आर० की सुप्रीम काउन्सिल अपने दोनों सक्तों की संयुक्त बैठक में यू० एल० एस० आर० की सरकार—यू० एल० एस० आर० की पीपुल्स कमीटियों की काउन्सिल का निर्माण कराती है ।

## चौथा अध्याय

### संघ के प्रजातन्त्रों की राजसत्ता के सर्वोच्च विभाग

धारा ५३—संघ के प्रजातन्त्र की राजसत्ता का सर्वोच्च विभाग संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल है ।

धारा ५४—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र के नागरिकों द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है ।

प्रतिनिधित्व का अनुपात संघ के प्रजातन्त्रों के शासन विधान निर्दिष्ट करते हैं ।

धारा ५५—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र का एकमात्र कानूनसत्ता विभाग है ।

धारा ६०—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल—

( क ) प्रजातन्त्र का शासन-विधान बनाती है और यू० एल० एस० आर० व शासन विधान की..... धारा १६ के अनुसार उसे संशोधित करती है ;

( क ) उन शुद्ध मुक्तार प्रजातन्त्रों के जो उनके क्षेत्र में हैं शासन-विधानों पर अन्तिम स्वीकृति देती है और उनके क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है ;

( ग ) प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय आर्थिक योजना और बजट पर वह मति देती है ,

( घ ) वह के प्रजातन्त्रों के न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्डों में आम रिहाई और सम-प्रदान के अधिकार का उपयोग करती है ।

धारा ६१—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल को प्रेसीडियम को चुनती है जिसमें एक संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चेयरमैन, उसके सदस्य और संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं ।

संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के अधिकार संघ के प्रजातन्त्र का शासन विधान निश्चित करता है ।

धारा ६२—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल अपनी बैठकों का काम चलाने के लिए अपना चेयरमैन और उसके सदस्य नियुक्त करती हैं ।

धारा ६३—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र को सरकार को संघ के प्रजातन्त्र की विपुल कमीशन की कानूनी संगठित करती है ।

## पाँचवाँ अध्याय

सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ का शासन के अंग

धारा ६४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ को सर्वोच्च शासन और प्रमुख विभाग की राज्यसत्ता सू० एल० एल० आर० की विपुल कमीशन की काउन्सिल में निहित है ।

धारा ६५—सू० एल० एल० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की विपुल कमीशन की काउन्सिल उसके प्रति उत्तरदायी है ।

धारा ६६—यू० एच० एच० आर० की पीपुस्त कमीतारों को काठस्थित कानूनों के अन्तर्गत और उनको वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए निर्वाहों और आकाशों को निश्चित होती हैं और उनकी समीक्षा पर निबन्धन करती है ।

धारा ६७—यू० एच० एच० आर० की पीपुस्त कमीतारों की काठस्थित के निर्वाहों और आकाशों को मान्यता अनिवार्य है और यू० एच० एच० आर० के समस्त क्षेत्र में उनका पालन होना चाहिए ।

धारा ६८—यू० एच० एच० आर० की पीपुस्त कमीतारों की काठस्थित—

( क ) यू० एच० एच० आर० के संघ की और संघ के प्रजातन्त्रों की पीपुस्त कमतरियों और अपनी सत्ता के अन्तर्गत आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के काम का संवाहन और एकीकरण करती है ।

( ख ) राज्य के बजट और राष्ट्रीय आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए और मुद्रा तथा उधार व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए क्रम ठठा सकती है ,

( ग ) सार्वजनिक शक्ति स्थापित करने के लिए, राज्य के हितों की रक्षा के लिए और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए क्रम ठठा सकती है ,

( घ ) निदेशी राज्यों के साथ संबंधों को आम निर्देश देती है ;

( ङ ) यह निर्दिष्ट करती है कि प्रतिवर्ष बिजने नागरिक सक्रिय ऐनिक सेवा के लिए मुलाए जाते हैं और देश की सशस्त्र बलों को आम देखभाल और सहाई का भ्राम रखती है ।

धारा ६९—यू० एच० एच० आर० की पीपुस्त कमीतारों की काठस्थित को यू० एच० एच० आर० के अधिकार-क्षेत्र की समस्त शासन और आर्थिक शाखाओं और संघ के प्रजातन्त्रों की पीपुस्त कमीतारों की काठस्थित के निर्वाहों और आकाशों को मंजूर करने और यू० एच० एच० आर० की पीपुस्त कमीतारों की आकाशों और निर्देशों को रद्द करने का अधिकार है ।

धारा ७०—यू० एल० एल० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल में जो यू० एल० एल० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है, निम्नलिखित सदस्य होते हैं —

यू० एल० एल० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;

यू० एल० एल० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल का वाइस-चेयरमैन ;

यू० एल० एल० आर० की 'स्टेट प्लानिंग कमिशन' का चेयरमैन ,  
'ओरिएण्ट इंस्टीट्यूट कमिशन' का चेयरमैन ,

यू० एल० एल० आर० के वीपुस्त कमीतार ,  
रूपि के ठरन को सरीद करनेवाली कमेटी के चेयरमैन ;

उच्च शिक्षा की कमेटी का चेयरमैन ।

धारा ७१—यू० एल० एल० आर० की सरकार अर्थात् वीपुस्त कमीतारों से सुप्रीम काउन्सिल के डिपुटी कोई प्ररन करे तो उन्हें समा में उतका मौलिक अथवा लिखित उत्तर अधिक से अधिक तीन दिन में देना पड़ता है ।

धारा ७२—यू० एल० एल० आर० के वीपुस्त कमीतार यू० एल० एल० आर० की सभा के अंतर्गत आने वाले शासन की सभी शक्तियों का निर्देशन करते हैं ।

धारा ७३—यू० एल० एल० आर० के वीपुस्त कमीतार अपने वीपुस्त कमन्सिबल के क्षेत्र की सीमा में कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिये आकाश और निर्देशों को जारी करते हैं । साथ ही साथ वे यू० एल० एल० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल के निर्णयों और आकाशों को भी लागू करते हैं और यह देखते हैं कि उन्हें पूरा किया जाता है ।

धारा ७४—यू० एल० एल० आर० के वीपुस्त कमन्सिबल का तो संघ के हैं अथवा संघ के प्रजासत्तों के ।

धारा ७५—संघ की वीपुस्त कमन्सिबल यू० एल० एल० आर० के समस्त क्षेत्र में शासन की शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके द्वारा बनाये गये संगठनों द्वारा निर्देशन करती हैं ।

धारा ७६—संघ के प्रभारतंत्र की पीपुस्त कमसरियतों टमके अंतर्गत शासन की शाखाओं का उची नाम की संघ के प्रभारतंत्रों की पीपुस्त कमसरियतों के द्वारा निर्देशन करती है ।

धारा ७७—संघ की पीपुस्त कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुस्त कमसरियतें हैं :—

रक्षा ;

विदेशी मामले ,

विदेशी व्यापार ;

रेलें ;

संदेश के वाहन ,

बन्ध-यातायात ,

बड़े उद्योग-धंधे ।

धारा ७८—संघ के प्रभारतंत्र की पीपुस्त कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुस्त कमसरियतें हैं —

मोहन संवर्षी उद्योग का ,

प्रकार्य संवर्षी उद्योग का ;

सफाई उद्योग का ,

कृषि का ;

राज्य के अनाज और पशु कामों का ,

राजस्व का ,

पर-व्यापार का ,

पर-विनाय का ,

म्याद का ,

स्वास्थ्य का ।

## अध्याय छठा

### संघ के प्रजातंत्रों के शासन के ढंग

धारा ७१—संघ के प्रजातंत्र की सर्वोच्च शासन और प्रबन्ध के ढंग की रायदस्ता संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल में निर्दिष्ट है।

धारा ८०—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी और उसके निर्वन्ध में है।

धारा ८१—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल यू० एच० एच० आर० और संघ के प्रजातंत्र में लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरा करने के लिये आकाश्यों और नियंत्रणों को निष्कासते हैं। साथ ही वे यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल के नियंत्रणों और आकाश्यों को भी पूरा करते हैं और उनकी समीक्षा का निर्वन्ध करती है।

धारा ८२—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल खुदमुखतार प्रजातंत्रों की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल की आकाश्यों तथा नियंत्रणों को मंजूर करने का अधिकार रखता है और जन जीवियों के हिपुटियों के प्रदेष्टों, प्रांतों, खुदमुखतार प्रांतों की लोकियतों की कार्य कारिणी समितियों के नियंत्रणों और आकाश्यों को रद्द कर सकती है।

धारा ८३—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल में जो संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है निम्न लिखित सदस्य होते हैं —

संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीटारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;

बाइस-चेयरमैन ;

'स्टेट ज़ागिंग कमीशन' का चेयरमैन ;

पीपुल्स कमीटार —

मोजन संबंधी उपयोग का ;

प्रकाश संबंधी उपयोग का ;

बचको डायोस का ,  
 कृषि का ;  
 राज्य के अनाज और पशु फार्मों का ;  
 राजस्व का ,  
 एह व्यापार का ;  
 एह निमाय का ;  
 न्याय का ;  
 स्वास्थ्य का ;  
 शिक्षा का ,  
 स्थानीय डायोस का ,  
 समुदाय की आर्थिक व्यवस्था का ;  
 सामाजिक मजदूरी के कामों का ;  
 कृषि के उत्पादनों की सरीर संबंधी कमीशन का एक प्रतिनिधि ,  
 कच्चा के प्रबन्ध का प्रबन्ध ,  
 संघ के पीपुल्स कमन्स रिबल्टों के प्रतिनिधि-सदस्य ।

धारा ८४—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीशनर संघ के प्रजातंत्र की शासन-व्यवस्था के अंतर्गत समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रबन्ध करते हैं ।

धारा ८५—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीशनर अपने अपने पीपुल्स कमन्स रिबल्टों के अधिकार-क्षेत्र की सीमा, ये सू० एल० एल० धार० और संघ के प्रजातंत्र के कामूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिये तथा सू० एल० एल० धार० की और संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीशनरों की आठमिनल की आभाषों और निर्देशों को पूरा करने और लागू करने के लिए आभाषों और निर्देशों को दे सकती है ।

धारा ८६—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्स रिबल्टें या क्षेत्र प्रजातंत्र की हैं अथवा प्रजातंत्र की हैं ।

धारा ८७—संघ-प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्स रिबल्टें राज्य के उच्च भाग का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं । वे संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्स रिबल्टों की आठमिनल और उही प्रकार की सू० एल० एल० धार० की पीपुल्स कमन्स रिबल्टों के मातहत होती हैं ।

धारा ८८—प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्समें राज्य के शासन के उस माग का प्रथम करती है जो उनके अधिकार में है। वे सीबी एच के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्सों की काउन्सिल के मातहत होती हैं।

## अध्याय सातवाँ

### सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्यसभा के सर्वोच्च अंग

धारा ८९—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की राज्य सभा का सर्वोच्च अंग सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की सुप्रीम काउन्सिल होती है।

धारा ९०—सुदमुक्तार प्रजातंत्र सुप्रीम काउन्सिल उस प्रजातंत्र के नामरिकों द्वारा सुदमुक्तार प्रजातंत्र के शासन विधान द्वारा निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार चार वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ९१—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक मात्र कानून बनाने वाला विभाग है।

धारा ९२—प्रत्येक सुदमुक्तार प्रजातंत्र का अपना शासन-विधान है जो सुदमुक्तार प्रजातंत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और संघ के प्रजातंत्र के शासन-विधान की अनुकूलता में बनाया जाता है।

धारा ९३—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चुनाव करती है और सुदमुक्तार प्रजातंत्र के शासन-विधान के अनुसार एक पीपुल्स कमन्सों की काउन्सिल बनाती है।



## अध्याय आठवाँ

## राज्यसत्ता के स्थानीय अंग

धारा २४—सेवो, ग्रामों, झुबमुकडार गाँवों, प्रदेसों, जिलों, शहरों और गाँवों (स्टेथीरलाउ, क्लोर्ग, किरलकच, कोस्स) में राज्यसत्ता के अंग कम जीवियों के विपुटियों के लोबियत हैं।

धारा २५—अम जीवियों के विपुटियों की लोबियतें, सेवो, गाँवों, झुबमुकडार गाँवों, प्रदेसों, जिलों, शहरों और गाँवों से नागरिकों द्वारा अपने अपने सेवो, गाँवों, झुबमुकडार गाँवों, प्रदेसों, जिलों, शहरों और गाँवों से दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा २६—अम जीवियों के विपुटियों की लोबियतों में प्रतिनिधित्व का अनुपात संघ के प्रजातंत्रों के शासन-विधान निर्धारित करते हैं।

धारा २७—अमजीवियों के विपुटियों की लोबियतें उन शासन के विभागों के कार्यों की देखभाल करती हैं जो उनके मस्तहत हैं। वे राज्य में शांति बनाये रखने, कानूनों का पालन कराने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, स्थानीय आर्थिक और सांस्कृतिक निर्माण का कार्य और स्वायत्त बजट बनाने का कार्य करती हैं।

धारा २८—अमजीवियों के विपुटियों की लोबियतें यू० एच० एच० आर० और संघ के प्रजातंत्र के कानूनों द्वारा निर्धारित राज्यसत्ता की सीमा के अंतर्गत नियंत्रित करती हैं और आकांक्षे निष्कारण हैं।

धारा २९—सेवो, गाँवों, झुबमुकडार गाँवों, प्रदेसों, जिलों और शहरों, की अमजीवियों के विपुटियों की लोबियतों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले विभाग उनके द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समितियों होते हैं जिनमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और सदस्य होते हैं।

धारा ३०—छोटे स्थानों में अमजीवियों के विपुटियों की आम लोबियतों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले अंग, संघ के प्रजातंत्रों के शासन-विधानों के अनुसार, एक चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्य होते हैं।

धारा १०१—भमजीवियों के डिपुटियों की तोकियतों के कार्य-कारिणी विभाग भमजीवियों के डिपुटियों की तोकियतों के प्रति जो ठगई जुनडी है और चाय ही भम जीवियों के डिपुटियों की ऊंची धोकियत के कार्यकारिणी विभाग के प्रति लीये जसरदायी होते हैं ।

## अध्याय नवाँ

### न्यायालय और अभियोग

धारा १०२—यू० एच० एच० आर० में निम्नलिखित न्यायालय हैं—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट, सप के प्रजातन्त्रों का सुप्रीम कोर्ट, प्रादेशिक और प्रांतीय न्यायालय, हुए मुकदमारे प्रांतों के न्यायालय, यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल के निर्माण से स्थापित यू० एच० एच० आर० के विशेष न्यायालय, और जनन्यायालय न्याय करने के लिये ।

धारा १०३—इन समस्त न्यायालयों में कानून द्वारा विशेषता बताए गये मामलों के अतिरिक्त अन्य अभियोगों की सुनवाई बनता के सहाकारी न्यायाधीशों की सहायता से होती है ।

धारा १०४—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय विभाग है इसके सुपुर्ब यू० एच० एच० आर० और सप के प्रजातन्त्रों के समस्त न्याय विभागों की कार्यवाही का नियन्त्रण है ।

धारा १०५—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट और यू० एच० एच० आर० के विशेष न्यायालय यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पाँच वर्ष के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०६—सप के प्रजातन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट सप के प्रजातन्त्रों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०७—हउमुकदमारे प्रजातन्त्रों के सुप्रीम कोर्ट उन प्रजातन्त्रों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०८—प्रादेशिक और प्रांतीय न्यायालय और ज़ुबुलुतार प्रान्तों के न्यायालय अमलीयों के डिपुटियों की प्रादेशिक और प्रांतीय सीनियर और ज़ुबुलुतार प्रान्तों के अमलीयों के डिपुटियों की सीनियरों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा १०९—कम-न्यायालय जिले के मायरिकों द्वारा प्रत्यक्ष, आम, समान, मतधिकार के आधार पर गुप्त मत से तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ११०—न्यायालयों की कार्यवाही तब अवका ज़ुबुलुतार प्रान्तों में अवका ज़ुबुलुतार प्रान्त की भाषा में होती है। जो व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानते उन्हें मुकद्दमे की समाप्त बातों के जानने का अवसर एक अनुवादक के माफ़त दिया जाता है और उसे न्यायालय के सामने अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है।

धारा १११—यू० एल० एल० आर० के समस्त न्यायालयों में केवल कानून द्वारा निर्धारित मामलों के अतिरिक्त सुनवाई कुछे आम होती है और अभियोगी के सफ़ाई का अधिकार सुरक्षित है।

धारा ११२—न्यायाधीश स्वतन्त्र हैं और केवल कानूनों के मातहत हैं।

धारा ११३—यू० एल० एल० आर० में समस्त पीपुल्स कम-एरिबटों, और उनके मातहत संस्थाओं, साथ ही तब वहाँ पर नियुक्त व्यक्तियों और नागरिकों द्वारा कानूनों के अधोक्षित पात्रन की सर्वोच्च वेतनमात्र यू० एल० एल० आर० के सरकारी बजट के हारा में है।

धारा ११४—यू० एल० एल० आर० का सरकारी बजट यू० एल० एल० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है।

धारा ११५—यू० एल० एल० आर० के सरकारी बजट द्वारा प्रशासकों प्रदेशों और प्रान्तों के सरकारी अभियोगों और साथ ही ज़ुबुलुतार प्रान्तों और ज़ुबुलुतार प्रान्तों के सरकारी बजट पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

धारा ११६—जिले के सरकारी बजट तब के प्रशासकों के सर

कारी बकीलों द्वारा यू० एच० एल० आर० के सरकारी बकील की सहमति से पाँच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

धारा ११७—अभिभोग लगाने वाले विभाग अपने कार्य समस्त स्थानीय विभागों से अत्यन्त स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं और केवल यू० एल० एल० आर० के सरकारी बकील के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

## अध्याय दूसरा

### नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व

धारा ११८—यू० एल० एल० आर० के नागरिकों को काम करने का अधिकार है—उन्हें अपने काम के लिये उसके परिमाण और गुणों के अनुसार वेतन उचित मारबंदीगुदा काम पाने का अधिकार है।

काम करने का यह अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के समान-बादी संगठन से, सोवियत समाज की उत्तम शक्तियों के निरन्तर विकास से, आर्थिक संकटों के अभाव से और बेकारी अन्त कर देने से सुरक्षित है।

धारा ११९—यू० एल० एल० आर० के नागरिकों को आराम करने का अधिकार है।

आराम करने का यह अधिकार मजदूरों के एक बहुत बड़े बहुमत के लिये काम का समय घटा कर सात घण्टे प्रति दिन कर देने से मजदूरों और मीकरो के लिये उचित आर्थिक शक्तियों का प्रवण करने से और मजदूरियों को रहने के लिये देश में स्वास्थ्य-शर्तों, आराम-शर्तों और इन्हीं का एक बहुत बड़ा जाल बिछा देने से सुरक्षित है।

धारा १२०—यू० एल० एल० आर० के नागरिकों को वृद्धावस्था में बीमारी में और कार्य के लिये अक्षम्य हो जाने की हालत में मौखिक रक्षा ( बीमा ) पाने का अधिकार है।

यह अधिकार मजदूरों और मीकरो के लिये राज्य के सर्व-र

सामाजिक बीमा के विस्तृत विकास से निःशुल्क बाधणी सहायता के प्रवन्ध से और अममीयों के लिये स्वास्थ्य-ग्रहों के एक बड़े जाल बिछा देने से सुरक्षित है।

धारा १२१—यू० एल० एल० आर० के मायमिकों को शिक्षा पाने का अधिकार है।

इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिये निःशुल्क, साम, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का प्रवन्ध है। उन्हे स्कूलों में छात्रों के एक बहुत बड़े बहुमत के लिये राज्य की ओर से बनीके की व्यवस्था है। स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है और कारकाओं, राज्य के लोगों, मशीन और दूरियों के रेशनों और सामूहिक लोगों पर काम करने वालों के लिये निःशुल्क औद्योगिक टैक्नीकल और प्रामोद्य अध्ययन का प्रवन्ध है।

धारा ११२—यू० एल० एल० आर० में नारियों को पुरुषों के साथ समस्त राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है।

नारियों को इन अधिकारों के उपयोग के अवसर देने के लिये उन्हें पुरुषों के साथ बराबर काम करने, आराम करने, सामाजिक बीमा, शिक्षा के अधिकार दिये गये हैं। साथ ही राज्य की ओर से माँ तथा बच्चे के हित की रक्षा का प्रवन्ध है, मातृत्व के समय खेतन तुही का प्रवन्ध है और प्रवृत्ति-ग्रहों, शिक्षा-ग्रहों और किडर मार्टनों के जाल बिछा दिये गये हैं।

धारा १२३—अति और राष्ट्रीयता का बिना भेदभाव किये यू० एल० एल० आर० के मायमिकों के अधिकारों की राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समानता एक हुनिवासी कानून है।

कोई भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों में कमी, अथवा बुरी ओर अति या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी मायमिकों को ही गंदे प्रवन्ध अथवा अप्रत्यक्ष हुनिवायें और साथ ही, असीम अथवा राष्ट्रीय विरोधता या युवा और अमाधर का प्रचार कानून द्वारा दखनीय अपराध है।

धारा १२४—नागरिकों को आभा-संबन्धी स्वतंत्रता देने के लिये यू० एच० एच० आर० में वर्च का राज्य से और स्कूल का वर्च से पूर्ण संबंध विच्छेद कर दिया गया है। धार्मिक कृत्यों को करने की स्वतंत्रता और वर्च के शिरोधार में प्रचार करने की स्वतंत्रता सब नागरिकों को है।

धारा १२५—भ्रम जीवियों के हित में समाजवादी व्यवस्था को हटाने के निमित्त, यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(क) भाषण स्वतंत्रता;

(ख) प्रेस की स्वतंत्रता;

(ग) समुदाय बनाने और समा करने की स्वतंत्रता;

(घ) बाजार में कुल्लू निष्कासने और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता।

नागरिकों को ये अधिकार भ्रमजीवियों और उनके संगठनों को प्रेस, काण्ड, सार्वजनिक भवन, बाजार संदेश के साधन और ठगै प्राप्त करने के लिये आवश्यक अन्य भौतिक शक्तों को देकर सुरक्षित किये गये हैं।

धारा १२६—भ्रम जीवियों के हित में और जनता के राजनीतिक कार्यों और विचारों के संगठन के लिये, यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को सार्वजनिक संगठन बनाने, मज़दूर समारोह, सहकारीता समितियाँ, युवक संगठन, खेल-कूद और रक्षा संगठन सांस्कृतिक, टेक्नीकल और वैज्ञानिक शोधों शोधों का अधिकार है और मज़दूरों और भ्रम जीवियों के अन्य वर्गों के सबसे अधिक सक्रिय और वर्तमान परावर्त नागरिकों को यू० एच० एच० आर० की कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित होने का अधिकार है। कम्युनिस्ट पार्टी भ्रम जीवियों के समाजवादी व्यवस्था को विकसित और हटाने के संघर्ष में समर्थी है और भ्रम जीवियों के समस्त सार्वजनिक और राज्य के संगठनों के उच्चतम तहों का प्रतिनिधित्व करती है।

धारा १२७—यू० एच० एच० आर० के नागरिकों के शरीर की सुरक्षा की गारंटी है। किसी भी नागरिक को बिना न्यायालय के निर्णय के अथवा राज्य के अधिपति की अनुमति के नहीं बनाया जा सकता।

धारा १९८—कानून द्वारा नागरिकों के घरों में प्रवेश निषिद्ध है और कानून पत्र-व्यवहार की गोपनीयता की रक्षा करता है।

धारा १९९—यू० एच० एच० आर० उन समस्त निवेशी नागरिकों को आश्रय देता है जो अमरीकियों के हितों की रक्षा अथवा अपने वैज्ञानिक कार्यों के कारण अथवा अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संरक्षण में भाग लेने के कारण तय किये जाते हैं।

धारा १९९—यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक को सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों के साथ के शासन विधान को मानना होता है कानूनों का पालन करना होता है, अम-अनुशासन मानकर चलना होता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और समाजवादी समुदाय के नियम मानकर चलना होता है।

धारा १९९—यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा और उसकी स्थिति बढ़ करनी होती है क्योंकि वह समाजवादी व्यवस्था की पवित्र नीति है, पितृभूमि के धन और शक्ति का स्रोत है, और समस्त अम-अमियों के समृद्धि यन्त्री सांस्कृतिक जीवन की कुञ्जी है। वे व्यक्ति जो सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं, कन्या के दुरमन हैं।

धारा १९९—आम सैनिक सेवा का नियम है। मजदूरों और किसानों की सशस्त्र सेना में सेवा यू० एच० एच० आर० के नागरिकों का सम्माननीय कर्तव्य है।

धारा १९९—पितृ भूमि की रक्षा करना यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। पितृभूमि के प्रति घोर, शत्रु को लोकात्, दुरमन से मिल जाना, राज्य की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाना किसी निवेशी राज्य के लिये आतंकी करना घोरतम अपराध है और इनके लिये कानून में निर्धारित नका से नका दण्ड दिया जा सकता है।

## अध्याय ग्यारहवाँ

### चुनाव परिपाटी

धारा ११४—भम जीवियों के डिपुटियों की समस्त लोचियों में, यू एल एल० आर० को सुपीम काउन्सिल में, लंप ए प्रजातों की सुपीम काउन्सिल में, भम जीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक और प्रांतीय लोचियों में लुक्कणार प्रजातों की सुपीम काउन्सिल में, भमजीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक, जिला, शहर और ग्राम लोचियों में मजबूतियों द्वारा आन, लमान, प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर गुन मठ से चुनाव होता है।

धारा ११५—डिपुटियों के ग्राम चुनाव होते हैं। यू एल० एल० आर० के समस्त नागरिकों को को चुनाव के वर्ष में १८ वर्ष की आयु के हो जाते हैं डिपुटियों के चुनाव में मत देने और चुने जाने का अधिकार है। विहित मन्त्रिक बाने व्यक्ति और स्थापानों द्वारा मताधिकार से स्पुत व्यक्ति इस संबंध में प्राज्ञार हैं।

धारा ११६—डिपुटियों के चुनाव में बराबर मताधिकार होता है। प्रत्येक नागरिक को चुनने और चुने जाने का अपनी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, शिक्षा-संबंधी योग्यता, ठरके लम्माधिक अम्म, लम्माति संबंधी स्थिति और पुराने कार्य के गहरूर में अधिकार है।

धारा ११७—नारियों को पुरुषों के साथ चुनने और चुने जाने के समान अधिकार हैं।

धारा ११८—लान सेना में सेवा करने वाले नागरिकों को अम्म नागरिकों के समान ही चुनने और चुने जाने के समान अधिकार हैं।

धारा ११९—डिपुटियों के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, ग्राम और शहरों की भमजीवियों के डिपुटियों की लोचियों से लेकर यू० एल एल० आर० की सुपीम काउन्सिल तक के चुनाव नागरिकों द्वारा लीये किये जाते हैं।

धारा १२०—डिपुटियों के चुनाव में गुन मठ-प्रदान होता है।

धारा १२१—अम्मेदवारों को निर्विहित क्षेत्रों में लका दिया जाता है।



ठम्मेबारी को सजा करने का अधिकार सभी सामाजिक संस्थाओं और भ्रमजीवियों की सोसाइटियों को है, कम्युनिस्ट पार्टी संगठनों को, मजदूर संघों को, सहकारिता समितियों को, युवक-बलों को और संस्कृतिक समुदायों को।

धारा १४२—प्रत्येक हिपुटी को अपने कार्य का लेला और भ्रमजीवियों के हिपुटियों की सोवियत के कार्य का विवरण मतदाताओं को देना होता है, उसे किसी भी समय कानून में निर्धारित पद्धति से मतदाताओं के बहुमत द्वारा वापिस बुलाना का शक्ति है।

## अध्याय सारहवाँ

### चिह्न, ध्वजा, रामधानी

धारा १४३—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ का राज्य चिह्न त्रिखों के निम्न पर बना हुआ, हँसिया और हथोका है और उसे चारों ओर से भ्रम की बालों घेरे हुए है। इसके साथ संघ के प्रजातंत्रों की भाषाओं में लिखा रहता है "हुनिया के मजदूरों, एक हो!" इस चिह्न के ऊपर पोंच नोक वाला तारा रहता है।

धारा १४४—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ की राज्य-ध्वजा लाल कपड़े पर हथोके पास ऊपरी सिरे पर सुन्मले रंग में हँसिया और हथोका बना रहता है और उनके ऊपर सुन्मले रंग के केनारे वाला एक पोंच नोक का तारा रहता है। लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात १ और २ के रहता है।

धारा १४५—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ की रामधानी बैन्सको है।

